चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 07 मार्च–13 मार्च 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भारत और नेपाल की सेनाएं मिल कर निपटेंगी आतंकियों से

नेपाल सीमा पर सेना

1. नेपाली सेनाध्यक्ष की लखनऊ में शीर्ष सैन्य अफसरों से कई दौर की बातचीत
2. लखनऊ व पिथौरागढ़ में दोनों देश की सेनाओं ने आतंकियों से युद्ध का किया अभ्यास
3. संसदीय समिति ने लिया सुरक्षा ज़रूरतों का जायज़ा, मध्य कमान पर दारोमदार
4. आईएसआई और आईएसआईएस से मुक़ाबले की तेज़ हुई दोतरफ़ा कवायद
5. विशेषज्ञों ने कहा, सीमा सुरक्षा का सम्पूर्ण प्रबंधन सेना को दे दिया जाए
6. भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में बसाई गई अवैध बस्तियों से ख़तरा

प्रभात रंजन दीन

बढ़ती आतंकी हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने भारत–नेपाल के खुले सीमाक्षेत्र पर सेना तैनात करने का प्रस्ताव दिया है. भारत–नेपाल सीमाक्षेत्र में बढ़ती जा रही आतंकी–आपराधिक–अराजक गतिविधियों से सेना और खुफिया एजेंसियां चिंतित हैं. नेपाल सीमा पर द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के सेना के प्रस्ताव पर रक्षा मामलों की संसदीय समिति विचार कर रही है. वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पिछले दिनों सेना के मध्य कमान मुख्यालय जाकर शीर्ष सेनाधिकारियों से बातचीत की और सुरक्षा जरूरतों का जायजा लिया. केंद्र रक्षा विशेषज्ञों की उस सलाह पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है जिसमें सीमा सुरक्षा का सम्पूर्ण प्रबंधन सेना के हाथ में दिए जाने की सिफारिश की गई है. इसमें यह भी शामिल है कि सीमा पर तैनात अर्ध सैनिक बलों पर भी सेना का ही कमांड एंड कंट्रोल रहे . विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि सेना से रिटायर होने वाले पूर्व सैनिकों को लेकर टेरिटोरियल आर्मी की बटालियनें खड़ी की जाएं, जिसे सीमा पर तैनात किया जा सके और सीमा की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी हो सके. नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री का भारत दौरा इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है. दोनों तरफ सीमा की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता है. यह समय की मांग है...

आईएसआईएस के संभावित खतरों, आईएसआई पोषित आतंकवाद और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों के कारण देश के सुरक्षा मापदंड और अनिवार्यताएं तेजी से बदली हैं. इसे देखते हुए भारतीय सेना ने नेपाल और भारत से जुड़ी 1757 किलोमीटर सीमा पर ठीक उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया है जैसी सुरक्षा का द्विस्तरीय बंदोबस्त पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर है. पाकिस्तान से लगे 3323 किलोमीटर सीमा–क्षेत्र में बीएसएफ तैनात है और उसके ठीक पीछे भारतीय सेना की कतारें तैनात रहती हैं. बांग्लादेश से लगी 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर भी बीएसएफ तैनात है लेकिन उसे कवर करने के लिए सैन्य इकाइयां नजदीक में तैनात नहीं हैं. भारत–नेपाल सीमा पर न तो बीएसएफ है और न निकट में सैन्य इकाइयां तैनात हैं. यहां सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तैनात है. एसएसबी को आतंकवादियों से सीधे लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है और दूसरी तरफ वह नेपाल के रास्ते भारत में हो रही जाली करेंसी और हथियारों की तस्करी व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है. एसएसबी की नाकामियां देश की सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए काफी गंभीर हैं. कुछ ही अर्सा पहले जब एसएसबी के 13 जवानों को नेपाली सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया और काफी देर तक बंधक बनाए रखने केबाद भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से छोड़ा तब एसएसबी की कमजोरी उजागर हुई थी. इससे भारत की काफी किरकिरी भी हुई थी. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा सीमा क्षेत्र सेना के मध्य कमान के तहत आता है, लिहाजा नेपाल सीमा की सुरक्षा उसकी चिंता का विषय है. इस मसले पर मध्य कमान का लखनऊ मुख्यालय इधर लगातार सक्रिय है. सेना मामलों की संसदीय समिति ने भी दो और तीन फरवरी को मध्य कमान का दौरा कर शीर्ष सैन्य अधिकारियों से सीमा सुरक्षा के विभिन्न मसलों पर विचार–विमर्श किया और सेना की राय से सहमति जताई. उधर, पश्चिम बंगाल से लगी नेपाल सीमा और बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सेना के पूर्वी कमान ने रक्षा मंत्रालय को अपनी राय से अवगत करा दिया है. सुरक्षा प्राथमिकता का ही नतीजा है कि नेपाल के थलसेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री कई दिन लखनऊ में रहे , भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकें कीं्रसैन्य इकाइयों का निरीक्षण किया और भारत–नेपाल सेना के साझा युद्धाभ्यास का जायजा लिया. भारत और नेपाल के सैनिकों का साझा अभ्यास लखनऊ में भी हुआ और उत्तराखंड में भी. नेपाली सेना के साथ हुए इस बार के साझा अभ्यास की खास बात यह रही कि भारतीय सेना ने नेपाली सेना को युद्ध के साथ–साथ आतंकियों से लड़ने का भी अभ्यास कराया और भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की भी ट्रेनिंग दी. इन अभ्यासों में आतंकवादियों से मुकाबले के लिए ज्वाइंट–ऑपरेशन की तकनीक पर अधिक जोर दिया गया. नेपाल के सेनाध्यक्ष ने भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है. नेपाल की सेना के साथ साझेदारी और समझदारी का रवैया दिखा कर भारत सरकार ने नेपाल सरकार की यह भ्रांति भी हटाई है कि नेपाल के मधेसियों को भारत समर्थन दे रहा है. इस भ्रम से पर्दा हटने के बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत आए और आपसी रिश्ते प्रगाढ़ किए. लंबे अर्से तक चले विवाद के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की सौहार्दपूर्ण भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है. छह दिनों की यात्रा पर भारत आए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली

नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री भारतीय सेना की मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी के साथ लखनऊ में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लड़ाई छोड़बो नहीं... | P-4

इराक़ : क्या था और क्या हो गया | P-5

रेल बजट : आम आदमी को क्या मिला | P-6

नेपाल सीमा पर सेना

पृष्ठ 1 का शेष

ने कहा भी कि भारत के साथ हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं. भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा संवेदनशीलता को लेकर बढ़ी इस सक्रियता में देश के थलसेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग के हाल ही हुए मध्य कमान के दौरे और मध्य कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार की विभिन्न सैन्य इकाइयों के दौरों को भी जोड़ कर देखा जा रहा है.

खबर के विस्तार में जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नेपाल में किस तरह अपनी पकड़ मजबूत बनाई है. केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी कहती है और जमीनी तथ्य भी बताते हैं कि नेपाल से लगे सीमा क्षेत्र में आईएसआई संरक्षित भारत विरोधी तत्वों को विस्तार से बसाया गया जिससे नकली करेंसी और हथियारों की तस्करी से लेकर तमाम आपराधिक गतिविधियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ गईं. लश्कर–ए–तैयबा के कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल समेत कई आतंकवादियों की नेपाल में हुई गिरफ्तारियां इसकी सनद हैं. भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी कहते हैं कि आईएसआई पोषित तत्वों ने मधेसियों के आंदोलन में घुसपैठ कर नेपाल में हिंसक अराजकता फैलाने की कोशिश की और यह रंग दिया कि मधेसियों के आंदोलन को भारत की तरफ से समर्थन मिल रहा है. जबकि इसके पीछे असली इरादा सीमाई इलाके में घनघोर अस्थिरता फैलाना और भारत को बदनाम करना था. खुफिया एजेंसियों का मानना है कि नेपाल सीमा पर बसाई गई अवैध बस्तियों से ही आईएसआईएस जैसे खतरों के भी सतह पर आने की आशंका है. लिहाजा, जिस तरह म्यांमार की सेना के साथ मिल कर साझा ऑपरेशन और साझा निगरानी के फार्मूले पर उत्तर पूर्व में सहमति से काम हो रहा है उसी तरह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिल कर भी साझा सख्ती, साझा निगरानी और साझा ऑपरेशंस पर सहमति बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. सेना के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि तीनों देशों ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है. इसे व्यवहारिक शक्ल में बदलने के लिए जरूरी ढांचागत और व्यवस्थागत बंदोबस्त किए जा रहे हैं. भारत–नेपाल सीमा की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यवार मंजूरी दे दी है. भारत–नेपाल सीमा पर सेना की तैनाती का प्रस्ताव व्यवस्थागत बंदोबस्त का ही अहम हिस्सा है.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय संसदीय समिति दो फरवरी को मध्य कमान के लखनऊ मुख्यालय पहुंची और अपने दो दिवसीय दौरे में

भारत–नेपाल सीमा सुरक्षा के विभिन्न मसलों और सैन्य आश्यकताओं पर गहन विचार–विमर्श किया. इसमें सीमा पर सैन्य इकाइयों की तैनाती, उसके लिए जरूरी स्थापना, इस पर आने वाले खर्च से लेकर तमाम सम्बद्ध मसले शामिल थे. संसदीय समिति के साथ बातचीत में मध्य कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसी इन सी) लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी व मध्य कमान के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे. संसदीय समिति ने सेना के मध्य कमान की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया. मध्य कमान के सेना कमांडर ने सीमांत क्षेत्रों में सड़कों और रेलवे के ढांचागत विकास की त्वरित अनिवार्यता को खास तौर पर रेखांकित किया. भारत–नेपाल सीमा पर सीमा स्तम्भों और सीमा चौकियों की चाक–चौबंद व्यवस्था के पहले सीमाई सड़कों का पुख्ता होना आवश्यक है. इसी इरादे से केंद्र सरकार ने 3853 करोड़ रुपये की लागत से नेपाल सीमा पर 1377 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसका राज्यवार विवरण यह है कि उत्तराखंड में नेपाल से लगी सीमा पर 530 करोड़ की लागत से 173 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर 1621 करोड़ की लागत से 640 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और बिहार में नेपाल सीमा पर 1702 करोड़ रुपये की लागत से 564 किलोमीटर सड़क बनेगी.

मध्य कमान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और संसदीय समिति की दो दिवसीय बैठक में उठे मसलों की जानकारी देते हुए एक सेनाधिकारी ने बताया कि सड़कों के निर्माण के बाद भारत–नेपाल सीमा को रेखांकित करने वाले स्तम्भों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा. सीमा–स्तम्भों के सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है. संसदीय समिति के रवाना होने के एक दिन बाद ही पांच फरवरी को लखनऊ पहुंचे नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री के समक्ष भी यह मसला उठा और यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमा–स्तम्भों के पुनरस्थापन, मरम्मती व क्षेत्र निर्धारण के काम में परस्पर सहयोग करेंगे. नेपाल के सेनाध्यक्ष अपने 10 सदस्यीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ लखनऊ पहुंचे थे. दोनों देशों के सेनाधिकारियों के बीच दोनों देशों की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कई दौर की बातचीत हुई और सहमतियां बनीं. नेपाल के सेनाध्यक्ष ने 11वीं गोरखा रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया और सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जायजा लिया. उनके साथ मध्य कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी मौजूद रहे . दोनों सेनाओं के बीच यह तय हुआ कि पारम्परिक रूप से दोनों देश की सीमाएं तो खुली रहेंगी, लेकिन जिस तरह बिना जांच–पड़ताल के निर्बाध रूप से लोगों का आवागमन बना रहता है,

भारत-नेपाल सीमा पर लगे 8553 स्तम्भों में से तकरीबन 2750 सीमा-स्तम्भ ध्वस्त हो चुके हैं या उन्हें हटा कर वहां पर लोग रहने लगे हैं. यहां तक कि सीमा स्तम्भों के दोनों तरफ सौ-सौ मीटर के नो-मैंस-लैंड पर भी लोगों को बसा दिया गया है. सीमा-स्तम्भों को हटा कर किया गया अतिक्रमण और सुनियोजित तरीके से लोगों को बसा दिए जाने को सेना भविष्य के खतरे का संकेत मानती है.

उस पर अब सख्त निगरानी और नियंत्रण रखने की आवश्यकता है.

उल्लेखनीय है कि भारत–नेपाल सीमा पर लगे 8553 स्तम्भों में से तकरीबन 2750 सीमा–स्तम्भ ध्वस्त हो चुके हैं या उन्हें हटा कर वहां पर लोग रहने लगे हैं. यहां तक कि सीमा स्तम्भों के दोनों तरफ सौ–सौ मीटर के नो–मैंस–लैंड पर भी लोगों को बसा दिया गया है. सीमा–स्तम्भों को हटा कर किया गया अतिक्रमण और सुनियोजित तरीके से लोगों को बसा दिए जाने को सेना भविष्य के खतरे का संकेत मानती है. रक्षा मंत्रालय के समक्ष पेश किए गए तथ्यों और आंकड़ों के मुताबिक नेपाल सीमा पर लगे स्तम्भों में से 1,451 स्तम्भ गायब हैं और वहां पर लोग बाकायदा बस्तियां बना कर रह रहे हैं. करीब 13 सौ स्तम्भ बुरी तरह ध्वस्त कर दिए गए हैं. बिहार की दशा और भी खराब है. बिहार से लगी नेपाल सीमा पर अवैध बसावट भीषण शक्ल अख्तियार कर चुकी है. बिहार–नेपाल सीमा पर 970 स्तम्भ ढहाए जा चुके हैं और अधिकांश स्थानों पर (नो मैंस लैंड समेट कर) अवैध बस्तियां बस चुकी हैं. खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि सीमा स्तम्भों को गायब कर वहां बसाई गई अवैध बस्तियों से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं और वे तस्करों से लेकर आतंकी और अपराधी तत्वों का सुरक्षित ठिकाना बन चुकी हैं. भारत–नेपाल सीमा का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगा विशाल क्षेत्र दोनों देशों के नियंत्रण से बाहर फिसलता जा रहा है, लिहाजा इस पर फौरन द्विपक्षीय बंदोबस्त और कार्रवाई आवश्यक है. सीमा स्तम्भों का ऐसा ही हाल भारत–भूटान सीमा का भी है, जहां नौ सौ से अधिक स्तम्भ गायब हो चुके हैं. भारत–भूटान के 699 किलोमीटर वाले मुक्त सीमा क्षेत्र में कुल 1705 स्तम्भ हैं. फिलहाल, भारत–नेपाल सीमा पर स्तम्भों के गायब होने के कारण क्षेत्र को लेकर बन रहे भ्रम को दूर कर उन्हें फिर से स्थापित करने और मरम्मत करने की दिशा में काम हो रहा है. जहां स्तम्भ गायब हैं वहां सीमा के सटीक निर्धारण के लिए सेना कार्टोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है. इसमें सर्वेक्षण विभाग की भी मदद ली जा रही है. सीमा पर नेपाल के स्तम्भ कम हैं और भारत के ज्यादा, फिर भी, विषम (ऑड) और सम (इवन) नंबरों के आधार पर भारत और नेपाल के सुरक्षा बल अपने–अपने क्षेत्र में स्तम्भों को फिर से स्थापित करने का जतन कर रहे हैं. सम संख्या भारत के स्तम्भों की है तो विषम संख्या वाले स्तम्भ नेपाल के हैं. सीमा क्षेत्र के निर्धारण और गायब स्तम्भों की शिनाख्त के काम में सुरक्षा बल के साथ–साथ भारत के सर्वे विभाग की आधा दर्जन टीमें उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रही हैं. उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और बिहार के रक्सौल, जयनगर में खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि इन सीमाई क्षेत्रों में स्तम्भ हटा कर अवैध बस्तियां बसाने का काम धुंआधार हुआ है. सीमा स्तम्भों की पहचान करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने का फैसला सेना की सतर्कता के बाद हुआ है, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भू–स्थानिक आंकड़ा केंद्र को भी संलग्न करने का निर्णय हुआ है. भारत–नेपाल सीमा कार्यकारी समूह इसकी निगरानी कर रहा है. सीमा स्तम्भों पर जीपीएस उपकरण लगाए जाएंगे और उनके नियंत्रण के लिए तकरीबन सौ कंट्रोल प्वाइंट्स होंगे, जहां स्तम्भों के बारे में जानकारियां दर्ज रहेंगी.

सेना सूत्रों ने कहा कि भारत–नेपाल सीमा प्रबंधन का काम कई क्रम में होगा. सीमा स्तम्भों की पहचान और उसके निर्माण के साथ ही सीमा चौकियों के प्रबंधन को भी दुरुस्त किया जाना है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक नेपाल से जुड़ी सीमा 1757 किलोमीटर तक विस्तृत है. इसमें उत्तराखंड से 263 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 566 किलोमीटर, बिहार से 729 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर और सिक्किम से 99 किलोमीटर सीमा लगती है. इस 1757 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में फिलहाल 455 सुरक्षा चौकियां हैं, जिसकी संख्या बढ़ाई जा रही है. प्रत्येक चार किलोमीटर के अंतर पर एक सुरक्षा चौकी बनाने का प्रस्ताव है. फिलहाल जो चौकियां हैं, वे एसएसबी की निगरानी में हैं, जिसे बीएसएफ के सुपुर्द करने का प्रस्ताव है. इन 455 सीमा रक्षा चौकियों में उत्तराखंड की 53, उत्तर प्रदेश की 148, बिहार की 193, पश्चिम बंगाल की 43 और सिक्किम की 18 रक्षा चौकियां शामिल हैं. सीमा सुरक्षा को लेकर नेपाल का रवैया अबतक गैर जिम्मेदाराना रहा है. नेपाल ने यह माना है कि तकरीबन 18 सौ किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) की तैनाती बगैर किसी ठोस योजना के की गई. इस वजह से सीमा के स्तम्भों की हिफाजत की रणनीतिक जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सका. नेपाल की तरफ कुल 87 बॉर्डर आउट पोस्ट हैं, जबकि भारत ने 455 सुरक्षा चौकियां बना रखी हैं और इसे बढ़ाया जा रहा है.

सीमा सुरक्षा के इन जरूरी मसलों पर जद्दोजहद के साथ ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाली सेना का साझा युद्धाभ्यास सूर्य–किरण–9 भी शुरू हुआ.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 01
दिल्ली, 07 मार्च–13 मार्च 2016
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

थलसेना की ऑपरेशनल शाखा से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने कई देशों से जुड़ने वाली अपनी सीमाओं के प्रबंधन को दुरुस्त करने की दिशा में ठोस काम किया है. श्रीलंका से जुड़ी समुद्री सीमा पर राष्ट्र विरोधी और तस्करी की गतिविधियां नियंत्रण में आ गई हैं. यही स्थिति बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर भी कायम हुई है. बांग्लादेश और म्यांमार सरकार से साझा सहमति बना कर वहां भी सीमा प्रबंधन का द्विपक्षीय बंदोबस्त किया जा रहा है.

नेपाल सीमा पर सेना

पृष्ठ 2 का शेष

आठ फरवरी से 21 फरवरी तक चले युद्धाभ्यास की खासियत यह रही कि इसमें नेपाली सेना की सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली रुद्र धोज बटालियन शरीक हुई. मध्य कमान के कार्यवाहक मेजर जनरल संजय शर्मा के नेतृत्व में मध्य कमान के पंचशूल ब्रिगेड के तहत यह युद्धाभ्यास हुआ. भारत और नेपाल का यह नौवां साझा युद्धाभ्यास था, लेकिन यह युद्धाभ्यास खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार नेपाली सेना को आतंकवादियों से मुकाबला करने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की भी खास ट्रेनिंग दी गई. साझा युद्धाभ्यास के आखिरी दौर में दोनों तरफ की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इसमें नेपाली सेना के मेजर जनरल शेखर सिंह बंसायत और भारतीय सेना की पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राकेश मनोचा भी शरीक हुए. इस संयुक्त अभ्यास में पर्वतीय क्षेत्रों में लड़े जाने वाले जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी सैन्य ऑपरेशन के बारे में विशेषज्ञीय ट्रेनिंग हुई और तकनीकी व खुफिया जानकारियां साझा की गईं.

थलसेना की ऑपरेशनल शाखा से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार ने कई देशों से जुड़ने वाली अपनी सीमाओं के प्रबंधन को दुरुस्त करने की दिशा में ठोस काम किया है. श्रीलंका से जुड़ी समुद्री सीमा पर राष्ट्र विरोधी और तस्करी की गतिविधियां नियंत्रण में आ गई हैं. यही स्थिति बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर भी कायम हुई है. बांग्लादेश और म्यांमार सरकार से साझा सहमति बना कर वहां भी सीमा प्रबंधन का द्विपक्षीय बंदोबस्त किया जा रहा है. यही पहल नेपाल और भूटान के साथ हो रही है और भारत-नेपाल विस्तृत सीमा क्षेत्र के पुख्ता प्रबंधन की दिशा में ठोस काम हो रहा है. उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जबकि म्यांमार से सटी भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है. इसमें उत्तर पूर्व के चार राज्यों की सीमा लगती है. अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सीमा, नगालैंड की 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर सीमा म्यांमार से जुड़ती है. पाकिस्तान से जुड़ने वाली भारतीय सीमा सबसे विस्तृत है. भारत के साथ लगने वाली पाकिस्तान सीमा तकरीबन 3323 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है. जम्मू-कश्मीर में कुल 708 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा है. इसमें अकेले जम्मू में भारत और पाकिस्तान के बीच 210 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है. भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब से सटा 553 किलोमीटर सीमाक्षेत्र है. भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात से लगी 508 किलोमीटर लंबी सीमा है. राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमा 1037 किलोमीटर की है. इतने विस्तृत सीमा क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसफ) और उसके ठीक पीछे सेना की लड़ाकू इकाइयां तैनात हैं. देश की अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी सैन्य इकाइयों की तैनाती का प्रस्ताव है, जिसे लेकर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय गंभीर है.

आतंकी हरक़तों का बड़ा ज़रिया बन सकता है नेपाल का सीमा क्षेत्र

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने इस बात की तस्दीक की है कि नेपाल से लगा सीमा क्षेत्र आने वाले समय में आतंकवादी हरकतों का बड़ा मार्ग बन सकता है, लिहाजा इसकी समुचित व्यवस्था समय रहते की जानी चाहिए. पिछले कुछ ही अंतराल में कुख्यात आतंकी यासीन भटकल, पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा, जब्बार, जावेद कमाल, नेपाल के कपिलवस्तु का रहने वाला वसीम उर्फ खब्बू, बबर खालसा के सुखविंदर सिंह, भाग सिंह, अजमेर सिंह जैसे कई कुख्यात आतंकवादियों के पकड़े जाने से यह उजागर हुआ कि नेपाल आतंकवादियों के बड़े हब के रूप में विकसित हो चुका है. वैसे, मुंबई बम कांड के अभियुक्त टाइगर मेमन को भी भारत-नेपाल सीमा पर ही गिरफ्तार किया गया था. कभी नेपाल सरकार में मंत्री रहे मिर्जा दिलशाद बेग ने नेपाल में आईएसआई को फलाने-फुलाने में सक्रिय भूमिका अदा की थी. उसकी हत्या के बाद ऐसे नामों की कड़ी में सौकत बेग, युनुस अंसारी, फैजान अहमद, मजीद मनिहार जैसे अनगिनत लोगों का नाम जुड़ता गया जो नेपाल की राजनीति में प्रभावी कद रखते थे और अब भी रखते हैं. ये आईएसआई के एजेंट भी हैं और पाकिस्तान से फर्जी नोट मंगा कर उसे भारत में तस्करी कराते हैं. इसमें जामिम शाह भी एक नाम था, जिसे आईएसआई ने मीडिया टाइकून के रूप में नेपाल में खड़ा करने और भारत के प्रति नेपाल में नफरत पैदा करने वाली खबरें प्रसारित-प्रचारित कराने के लिए अकूत धन लगाया था. जामिम की हत्या हो जाने के बाद आईएसआई ने अपनी इस मंशा के लिए अन्य हथकंडों का इस्तेमाल किया. इस तरह आईएसआई की गतिविधियां लगातार बढ़ती ही चली गईं. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश के महराजगंज स्थित सोनौली बार्डर से ही पिछले डेढ़ साल में डेढ़ सौ से अधिक आतंकी पकड़े जा चुके हैं. आईएसआई की जड़ें नेपाल में इतनी गहरी रही हैं कि यासीन भटकल ने नेपाल में ही इंडियन मुजाहिदीन का गठन करना उपयुक्त समझा था. एक लंबा दौर गुजरा है जब नेपाल के रास्ते ही आतंकवादियों की आमदरफ्त हो रही थी. यहां तक कि जब कश्मीर में आतंकियों के पुनर्वास की योजना बनी और उनके समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा गया तो पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकवादी नेपाल के रास्ते ही भारत आए. खुफिया एजेंसी बताती है कि नेपाल के रास्ते कम से कम चार सौ आतंकवादी भारत पहुंचे. गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि चार साल में साढ़े तीन सौ आतंकवादियों ने नेपाल पहुंच कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आगे आत्मसमर्पण की इच्छा जताई और एसएसबी ने उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार के सुपुर्द किया. विचित्र तथ्य यह है कि पाकिस्तान में छिपे कश्मीरी आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर, सलमाबाद, चकन दा बाग सुरक्षा चौकी या इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते आने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इन प्रस्तावित रास्तों से कोई भी आतंकी नहीं आया. इसके लिए सबने नेपाल को अपना पसंदीदा स्थान चुना. आईएसआई पोषित आतंकवादी नेपाल से जुड़े तीनों राज्यों की खुली सीमा का खूब लाभ उठा रहे हैं लेकिन सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल ठीक से निगरानी नहीं कर पा रहा है. आतंकी गुट अकूत धन के लिए नशीले पदार्थों की अंधाधुंध तस्करी कर रहे हैं. एसएसबी का तर्क यह है कि उन्हें पासपोर्ट एंड कस्टम्स एक्ट का अधिकार नहीं दिया गया है, लिहाजा तस्करी की गतिविधियों पर कारगर रोक संभव नहीं हो पा रही. एसएसबी को तस्करों को गिरफ्तार करने, बरामद पदार्थों को जब्त करने और उनसे पूछताछ करने का अधिकार नहीं है. इसके लिए अलग से कस्टम विभाग और नारकोटिक्स महकमे के अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ता है.

मध्य कमान में तैनात मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ अर्सा पहले नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस कर चीनी अधिकारियों के जायजा लेने की हरकतों को भी काफी गंभीरता से लिया गया. चीन के कस्टम विभाग के अधिकारियों के छद्म में चीनी सेना के अधिकारी और चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने भारतीय सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया था. हालांकि नेपाली सेना के अधिकारियों ने बताया था कि चीन के कस्टम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल लांग चिंग वी व अन्य चीनी अधिकारियों ने निरीक्षण किया था. लेकिन चीनी अधिकारियों की अधिक दिलचस्पी भारत-नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड में क्यों थी और उसी खास क्षेत्र का वे घंटों तक क्या निरीक्षण करते रहे, इसका समुचित जवाब नेपाली पक्ष से नहीं मिल पाया था. लेकिन इस घटना के बाद ही इस मामले में सेना ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू किया.

दूसरी तरफ रक्षा रणनीति के विशेषज्ञों ने भी देश के सीमा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार से कहा है कि देश की सम्पूर्ण सीमा की सुरक्षा का प्रबंधन और नियंत्रण सेना के हाथ में दे दिया जाए. जिन सीमाओं की निगरानी का दायित्व अर्ध सैनिक बल के जिम्मे है, उन्हें भी सेना की निगरानी और नियंत्रण में रखा जाए, ताकि सीमा की सुरक्षा प्रोफेशनल तरीके से हो सके. पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमाएं देश के 17 राज्यों के 92 जिलों से गुजरती हैं, लिहाजा बदले हुए सुरक्षा परिदृश्य में देश के विशाल सीमा क्षेत्र की हिफाजत के लिए कठोर प्रोफेशनल-मैनेजमेंट की आवश्यकता है. अभी सीमा सुरक्षा के काम में सेना के साथ-साथ असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तैनात हैं. समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में तटरक्षक बल और उसके बाद नौसेना तैनात रहती है. अलग-अलग स्थानीय पहलुओं को देखते हुए अलग-अलग सीमा की खास-खास तरीके से हिफाजत की जरूरत है. विशेषज्ञों ने सीमा प्रबंधन मामले में रक्षा मंत्रालय को अग्रणी भूमिका में रखने की सलाह दी है और कहा है कि सीमा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों में रणनीतिक जरूरतों के मद्देनजर ढांचागत फेरबदल किया जाना चाहिए. रक्षा मामलों के थिंक-टैंक से जुड़े विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर जो केंद्रीय अर्ध सैनिक बल तैनात हैं, उन्हें भी सेना के सीधे नियंत्रण में दिया जाना अनिवार्य है. विशेषज्ञों ने म्यांमार सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स से लेकर बीएसएफ को देने के प्रस्ताव पर सख्त एतराज जताया है. अपेक्षाकृत कम उम्र में ही रिटायर हो जाने वाले पूर्व सैनिकों को लेकर टेरिटोरियल आर्मी की ऐसी बटालियनें खड़ी करने की सलाह दी गई है जिसे सीमा पर तैनात किया जा सके, जो सुरक्षा में अर्ध सैनिक बलों से बेहतर साबित होंगी. सीमा की निगरानी के लिए ड्रोन की सुविधाओं से भी सेना को लैस किया जा रहा है. सलाह देने वालों में केंद्र सरकार के गृह सचिव रहे जीके पिल्लई, थलसेना के एडजुटेंट जनरल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सब्बरवाल, मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी रहे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, थलसेना की उत्तरी कमान के पूर्व मेजर जनरल उमंग सेठी, सेना मुख्यालय के डीडीजी रहे ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार जैसे सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हैं.

सीमा के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव के लिए भारत सरकार नेपाल को जरूरी उपकरण और तकनीक वगैरह भी मुहैया कराने जा रही है. सीमा स्तम्भों पर जीपीआरएस सिस्टम लगाने और निगरानी के लिए जरूरी तकनीकी साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ नेपाल को हथियार और आयुध भी दिए जा रहे हैं. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नेपाली सेना द्वारा भारत से मांगे गए सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है. इसके पहले भी हथियारों और उपकरणों की बड़ी खेप नेपाल भेजी जा चुकी है. नेपाल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ नियमित संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद विरोधी साझा कार्रवाई और दोनों देशों के बीच अभिसूचना के आदान-प्रदान पर भी सहमति हुई है. पिछली खेप में नेपाली सेना को भारत ने नेपाली मुद्रा में 1.76 अरब रुपये के हथियारों की आपूर्ति की थी. इसमें भारी संख्या में विभिन्न बोर की गोलियां, बम निरोधी उपकरण और विस्फोटकों सहित 26,000 अलग-अलग तरह के हथियार और उपकरण शामिल थे. भारत की तरफ से नेपाल को कारतूसों, बम निरोधी उपकरणों और विस्फोटकों से भरे 45 ट्रक, गैर-घातक साजो-सामान में 35 बख्तरबंद वाहन, 216 हल्के और 154 भारी वाहन सहित सैकड़ों वाहन और भारी वाहनों में 7.5 टन क्षमता वाले 58 ट्रक भेजे गए थे. इसके अलावा नेपाल को बारूदी सुरंग, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और टाइम पेंसिल भी मुहैया कराए जा रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

दोस्ती दोनों के लिए ज़रूरी

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत आकर हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं. नेपाल की गलतफहमियां क्या थीं, यह स्पष्ट है. चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रदूषित माहौल में गलतफहमियां गहरा रही थीं, लेकिन भारत ने उसे समय रहते दूर करने की कोशिश की. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओली से मिलते हुए कहा कि नेपाल की सुरक्षा भारत की सुरक्षा के साथ अंतरनिहित है. इस पर नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को बिग-ब्रदर नहीं बल्कि बड़ा भाई कहा. नेपाल का पूरा तंत्र हफ्तेभर से अधिक समय तक भारत में था. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेकर सेनाध्यक्ष राजेंद्र छेत्री और तमाम शीर्ष सेनाधिकारियों की टीम के भारत में होने का मतलब है और दुनिया को संदेश भी है. दरअसल भारत और नेपाल अलग-अलग रह ही नहीं सकते. दोनों देशों के संस्कार, परम्पराएं, रिश्तेदारियां, व्यापार जैसे तमाम आयाम एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं. पुरातन समय से दोनों देश तकरीबन दो केार किलोमीटर की लंबी विस्तृत सीमा बिल्कुल खुले तौर पर निर्बाध बांटते रहे हैं, जहां कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं रही. 1950 में तो एक संधि भी हुई थी जिसमें नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिक की तरह ही समान शिक्षा और समान आर्थिक अवसर देने की बात कही गई थी. भारत ऐसा अकेला देश है जहां नेपाली नागरिकों को सिविल सेवा सहित दूसरी सरकारी सेवाओं में समान हिस्सा लेने का अधिकार है. भारत में 80 लाख से अधिक नेपाली नागरिक काम करते हैं. तकरीबन एक लाख से अधिक नेपाली नागरिक भारतीय सेना और अर्ध सैनिक बलों में काम कर रहे हैं. इसी तरह तकरीबन 10 लाख भारतीय नागरिक नेपाल में रहते हैं. भारत की तमाम बड़ी कंपनियां नेपाल की बड़ी निवेशक हैं. नेपाल का करीब 50 फीसदी विदेशी पूंजी निवेश भारतीय कंपनियों और योजनाओं के जरिए आता है. दो सौ से अधिक भारतीय उपक्रम नेपाल में काम कर रहे हैं. इनमें आईटीसी, डाबर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स, मणिपाल ग्रुप, एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट, टाटा पावर जैसी कई कंपनियां शामिल हैं. नेपाल के कुल कारोबार में 70 फीसदी व्यापार भारत के साथ होता है. ■

जंतर मंतर से किसानों-आदिवासियों की हुंकार

लड़ाई छोड़बो नहीं...

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

किसानों से ज्यादा इस रैली में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे छाए रहे. हालांकि आंदोलन की मांगों में इसे अप्रत्यक्ष तौर पर जगह दी गई थी. मांग थी कि झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जनतांत्रिक अधिकारों का हनन बंद करो और बढ़ती फासीवादी ताकतों पर लगाम लगाओ. इस वजह से मंच सामाजिक कम, राजनीतिक ज्यादा नज़र आ रहा था. हालांकि राजनीतिक लोगों ने भी इसमें शिरकत कर अपना समर्थन दिया. जदयू के राज्य सभा सासंद अली अनवर ने इसमें शिरकत की और कहा कि यह सरकार मजदूर और किसान विरोधी है. मोदी जी ने चुनाव के दौरान किसानों से जो वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया. इसलिए किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं.

गांव छोड़बो नहीं
जंगल छोड़बो नहीं
माई माटी छोड़बो नहीं
लड़ाई छोड़बो नहीं...

नवीन चौहान

24 फरवरी को यह गीत दिल्ली के जंतर-मंतर में 15 राज्यों के तकरीबन पांच हजार लोग एक साथ गाते दिखाई दिए. लगभग 300 सामाजिक संगठनों और आंदोलनों से जुड़े लोग इस गीत के माध्यम से सरकार को चुनौती दे रहे थे कि इस देश की जनता प्राकृतिक संसाधनों की हो रही अंधाधुंध लूट का पुरजोर विरोध करती रहेगी. पिछले साल 24 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ इन्हीं जन संगठनों ने प्रदर्शन किया था और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने की मांग की थी. तीन बार सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाई, लेकिन अंततः देश भर में हो रहे चौतरफा विरोध की वजह से उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे. इस महारैली में आए लोगों का मानना है कि यह उनकी जीत है. सभी संगठनों की एकता की वजह से सरकार को जनता के आगे घुटने टेकने पड़े और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा था. हालांकि इन लोगों को आज भी इस बात की आशंका है कि कहीं सरकार भूमि अधिग्रहण (संशोधन) कानून को पिछले दरवाजे से न ले आए. सरकार ने इस बिल को अभी वापस नहीं लिया है. यह बिल फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास है. समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के हैं और समिति के अधिकांश सदस्य 2013 के कानून में किए जाने वाले संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष बार-बार समिति का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, ताकि मौका मिलने पर समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जा सके और कानून को पास कराया जा सके.

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. 2013 का कानून हमारे सपनों का कानून नहीं था, इसमें बहुत सी खामियां हैं, खेती करने वाले मजदूरों की सहमति का उसमें प्रावधान नहीं है, भूमि अधिग्रहण से वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. मोदी सरकार जो कानून लाना चाहती है, उसमें सरकारी योजनाओं में लोगों की सहमति लेने का प्रावधान नहीं है, जबकि निजी योजनाओं के लिए ऐसा प्रावधान है. सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी योजनाओं में ग्रामसभा की अवहेलना क्यों? दूसरी बात कि इस कानून में पुनर्वास की बात तो है, लेकिन वह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा देने जैसा है, जबकि कानून में पैसे देने का प्रावधान भी है. सरकार में अगर हिम्मत है तो सरकार लोगों को उसी तरह की व्यवस्था करवाने की हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा वो हमारी पीढ़ियों, पुराने गांवों को हाथ लगाने की हिम्मत न करे.

इस महारैली से सरकार को यह संदेश दिया गया कि यदि सरकार दोबारा भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करने का प्रयास करेगी तो देश के किसान, मजदूर, मछुआरे, वनाश्रित, दलित, आदिवासी सभी मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे. जमीन उनकी मां है और वे इसे बचाने के लिए लड़ते रहेंगे. रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला ने कहा कि जिस तरह हमें सरकार के जमीन छीनने के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उसी तरह मजदूरों के लिए भी लड़ना पड़ेगा, किसानों के लिए भी लड़ना पड़ेगा, उसी तरह झूठे राष्ट्रवाद से भी लड़ना पड़ेगा. इसके खिलाफ बगावत करना भी किसान का फर्ज है. हमें गांव-गांव में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए. देश को बांटने वाली ताकतें जन-आंदोलनों से नज़र घुमाने के लिए, बढ़ती महंगाई से नज़र घुमाने के लिए इस तरह के सवाल उठा रही हैं, जिससे कि लोग इन भावनात्मक मुद्दों के बीच फंस जाएं. ये लोगों के बीच में फूट डालना चाहते हैं, ताकि देश का गरीब, किसान, मजदूर एकजुट होकर जल, जंगल, जमीन की लड़ाई न कर सके. इसलिए इस साजिश का भंडाफोड़ करना हमारा काम है. इन साजिशकर्ताओं को पीछे करने के लिए हमें भारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी.

किसानों और प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि अब कहां गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, क्यों अब नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है? चुनाव के दौरान तो वह किसानों को लागत का डेढ़ गुना फसल का दाम देने की बात कर रहे थे. आज उनकी नीतियों की वजह से खेती की लागत दर बढ़ गई है, सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप कम प्रीमियम दर रखी है, हम उनकी इस सोच के समर्थक हैं. उन्होंने चार तरह के इंश्योरेंस को एकत्र कर एक इंश्योरेंस कर दिया है, केंद्र और राज्य इसकी जिम्मेदारी मिलकर संभाल रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे, मझोले और सीमांत किसान हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 68 प्रतिशत है, ऐसे किसान इतना कम प्रीमियम भी नहीं दे सकते. उनके लिए यह बीमा निशुल्क कर देना चाहिए. सरकार ने नगदी फसलों में जो 5 से 10 प्रतिशत प्रीमियम कर दिया है, वह हमें स्वीकार नहीं है. उन्होंने नगदी फसलों में कपास और रबड़ के साथ आलू, गन्ना, शकरकंद और टमाटर भी जोड़ लिया है. क्या गन्ना, कपास, टमाटर नगदी फसलें हैं? इन फसलों का बीमा राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियां करें तो ज्यादा बेहतर होगा.पूर्व सांसद और सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य सुहासिनी अली ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कॉर्पोरेट घरानों और पूंजीपतियों से कहती है कि आप प्रदेश की जिस ज़मीन पर उंगली रखेंगे, वे उस जमीन को उन्हें दे देंगे, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

देश के आदिवासी इलाकों से आए लोगों ने सरकार द्वारा वनाधिकार कानून-2006 को कमजोर करने की कोशिश की बात कही. उनका आरोप है कि सरकार वनाधिकार कानून को चोर दरवाजे से बदलने में लगी हुई है. झारखंड में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, ताकि आदिवासियों की जमीन कॉर्पोरेट्स को दी जा सके. भूमि अनुवर्ती सूची का विषय होने की वजह से राज्यों के अधीन भी है, तमाम राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से भूमि अधिग्रहण कानून बना रही हैं. राजस्थान सरकार ने तो यह मन बना लिया है कि वह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में नहीं जाएगी, बल्कि राज्य में मौजूद सरकारी ज़मीन को चिन्हित करके सीधे कॉर्पोरेट्स को दे देगी. इसी तरह आंध्र प्रदेश में भू-अधिग्रहण बिल को बाइपास करके लैंडपूलिंग के जरिए जमीन ली जा रही है, अमरावती में नई राजधानी के निर्माण के लिए यही प्रक्रिया अपनाई गई है. ऐसे में लोगों को लगता है कि सरकार राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से कानून को नहीं बदल सकती है, लेकिन राज्यों के कानूनों में बदलाव करके अपने लिए रास्ते खोलना चाहती है. इसके लिए वह वन कानूनों में कुछ तकनीकी बदलाव करना चाहती है, जिसके लिए उसे संसद न जाना पड़े. जैसे कि कानून के लागू होने की समयसीमा निर्धारित करना, कंपनियों के हाथ में वृक्षारोपण का काम सौंपना, सामुदायिक अधिकारों के मसले को जड़-मूल से खत्म करना और जैसा कि महाराष्ट्र में वनोपज को वापस वन विभाग के नियंत्रण में दिया जाना. इसलिए इस वक्त भू-अधिकार के साथ वनाधिकार का मुद्दा गहरे रूप से जुड़ गया है.

किसानों से ज्यादा इस रैली में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे छाए रहे. हालांकि आंदोलन की मांगों में इसे अप्रत्यक्ष तौर पर जगह दी गई थी. मांग थी कि झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जनतांत्रिक अधिकारों का हनन बंद करो और बढ़ती फासीवादी ताकतों पर लगाम लगाओ. इस वजह से मंच सामाजिक कम, राजनीतिक ज्यादा नज़र आ रहा था. हालांकि राजनीतिक लोगों ने भी इसमें शिरकत कर अपना समर्थन दिया. जदयू के राज्य सभा सासंद अली अनवर ने इसमें शिरकत की और कहा कि यह सरकार मजदूर और किसान विरोधी है. मोदी जी ने चुनाव के दौरान किसानों से जो वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया. इसलिए किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं. अब लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को वे हवा दे रहे हैं. उनके राज में गरीबों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है, राहत मिली है तो कॉर्पोरेट घरानों को. इसलिए यह लड़ाई तो होगी और केवल संसद से बात नहीं बनेगी, लोगों को अपने हक की लड़ाई सड़क पर भी लड़नी होगी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यह बात समझनी होगी कि पिछले साल किसानों की आत्महत्या से शुरुआत हुई और इस साल यह छात्रों की आत्महत्या तक पहुंच गई है. यह देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है कि देश का विकास आखिर हो किसके लिए रहा है. मोदी जी कौन से डिजिटल इंडिया को लाने की बात कर रहे हैं. हमारी लड़ाई सड़क से शुरू होकर संसद तक जाएगी.

औद्योगिक गलियारा, स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया जैसी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार जमीन लेन की फिराक में है. इसके लिए वह वन, पर्यावरण और राज्यों के कानूनों के माध्यम से रास्ता तलाश रही है. सरकार अपने कार्यकाल के तकरीबन 20 महीने पूरे कर चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 60 महीने देने की बात की थी. अब उनके पास केवल दो तिहाई समय अपने वादों को पूरा करने के लिए बचा है. आखिर के 12 महीने चुनावी महीने होंगे. इसलिए उनके पास कुछ करने के लिए केवल 28 महीने शेष बचे हैं, इसलिए लोगों को विश्वास में लेने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है. उन्हें सबका साथ सबका विकास के अपने नारे को लेकर आगे बढ़ना होगा. ऐसा करके ही वह अपने विकास के वादे को पूरा करने में सफल होंगे. ■

navinonline2003@gmail.com

भूमि अधिकार आंदोलन महारैली की मुख्य मांगें

1. भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल-2015 वापस लो. भूमि अधिग्रहण नहीं भू-अधिकार चाहिए.
2. भूमि-अधिग्रहण कानून-2013 की अवहेलना बंद करो और राज्य सरकार द्वारा की जा रही छेड़छाड़ एवं बनाए गए कानूनों की मंजूरी रोको.
3. राज्य सरकारों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाओ.
4. वनाधिकार कानून 2006 से छेड़छाड़ बंद करो और प्रभावी तरीके से लागू करो.
5. कृषि संकट से निपटने के लिए तात्कालिक उपाय करो, फसल का उचित दाम और क्षति, फसल के बदले उचित मुआवजा दो.
6. बुनियादी भूमि सुधार एवं भूमि हदबंदी लागू करो या अतिरिक्त जमीन का बंटवारा करो. गरीबों के लिए आवास मुहैया कराओ और जबरन विस्थापन बंद करो.
7. मनरेगा कानून में बदलाव करो, आवंटन बढ़ाओ और 300 दिन, 300 रुपये रोज का काम सुनिश्चित करो.
8. टीएस सुब्रमण्यम समिति द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय कानूनों को खारिज करो.
9. श्रम कानूनों में फेरबदल खत्म करो, मजदूरों का अधिकार बहाल हो.
10. महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और अत्याचार को रोकने के लिए उचित कार्रवाई हो.
11. झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जनतांत्रिक अधिकारों का हनन बंद करो और बढ़ती फासीवादी ताकतों पर लगाम लगाओ.

क्या हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें

1. सीलिंग सरप्लस और बंजर भूमि का वितरण.
2. मुख्य कृषि भूमि और जंगल कॉरपोरेट क्षेत्र को ग़ैर कृषि प्रयोजनों के लिए देने पर रोक.
3. आदिवासियों और चरवाहों को जंगल में चराई का अधिकार.
4. एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा की स्थापना.
5. कृषि भूमि की बिक्री विनियमित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना.
6. सस्ता स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पुनर्जीवित करें.
7. माइक्रोफाइनांस नीतियों का पुनर्गठन, जो आजीविका वित्त के तौर पर काम करें. सस्ती क़ीमत, सही समय-स्थान पर गुणवत्ता युक्त बीजों और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
8. कम जोखिम और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, जो किसानों को अधिकतम आय प्रदान करने में मदद कर सके.
9. जीवन रक्षक फसलों के मामले में बाज़ार हस्तक्षेप योजना की आवश्यकता.
10. अंतरराष्ट्रीय मूल्य से किसानों की रक्षा के लिए आयात शुल्क पर तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता.
11. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन में सुधार. धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए.
12. न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की औसत लागत की तुलना में कम से कम 50 फीसद अधिक होना चाहिए.
13. ऐसे बदलाव की ज़रूरत है, जो घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए स्थानीय उत्पाद की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विकास को बढ़ावा दे.

पूरे इराक़ में, चाहे वह नजफ़ हो, कर्बला हो, बग़दाद हो या कुफ़ा, हर तरफ़ फ़ौजी टैंक नज़र आ रहे थे. दुकानों पर ज़रूरत की हर वस्तु मौजूद थी, लेकिन जब बिस्किट के एक छोटे पैकेट की क़ीमत एक हज़ार दीनार बताई गई, तो हमारी सांस रुक-सी गई. एक ख़ुशहाल मुल्क, जो जंग का शिकार रहा, जिसने गृहयुद्ध झेला और अब आईएसआईएस का आतंक झेल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था की बदहाली हमने अपनी आंखों से देखी. बग़दाद में एक बुज़ुर्ग से पानी की बोतल ख़रीदते समय जब हमने उनकी माली हालत के बारे में पूछा, तो उस बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए.

इराक़
क्या था और क्या हो गया

डॉ. वसीम राशिद

> यह शिया-सुन्नी की लड़ाई नहीं है, बल्कि आईएसआईएस के ख़िलाफ़ इराक़ की जंग है. दुनिया में प्रचार किया जा रहा है कि सद्दाम हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सुन्नियों पर अत्याचार हो रहे थे, इसलिए आईएसआईएस वजूद में आया, जबकि यह एक दुष्प्रचार भर है. आईएसआईएस सुन्नियों को भी मार रहा है, उनकी बस्तियां उजाड़ रहा है. ये वे शब्द हैं, जो नजफ़ की धरती पर क़दम रखते ही भारतीय मीडिया ग्रुप के कानों में पड़े.

भारतीय मीडिया ग्रुप, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे, को हज़रत इमाम हुसैन बोर्ड की ओर से इराक़ की सही तस्वीर जानने के लिए आमंत्रित किया गया था. नजफ़ एयरपोर्ट पर विभिन्न देशों के कई ग्रुप हज़रत इमाम हुसैन एवं हज़रत अली के रौज़े की ज़ियारत के लिए मौजूद थे. किसी के चेहरे पर कोई डर या खौफ़ नहीं था, जबकि इस वक्त इराक़ के नाम से पूरी दुनिया भयभीत हो जाती है. नजफ़ से लेकर कर्बला तक के रास्ते में आबादी का कोई नामोनिशान नहीं था. हां, तक़रीबन प्रत्येक दो किलोमीटर पर जबरदस्त चेकिंग हो रही थी. वहां मौजूद इराक़ी सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे. इस समय आईएसआईएस की वजह से पूरे इराक़ में सघन जांच-पड़ताल हो रही है. आबादी थी, दुकानें थीं, लेकिन लोग नहीं थे. हाई अलर्ट के चलते सड़कों पर चहल-पहल नज़र नहीं आ रही थी. लेकिन, नजफ़ से कर्बला में दाख़िल होते ही लोग दिखने लगे. बड़ी संख्या में महिलाएं काला बुर्क़ा पहने इमाम हुसैन के रौज़े की तरफ़ जा रही थी. कर्बला की लगभग पूरी आबादी शिया है, लेकिन सुन्नी भी इमाम हुसैन के रौज़े पर हाज़िरी देते है. भारतीय मीडिया ग्रुप की पहली मुलाकात रौज़े इमाम हुसैन ट्रस्ट के प्रमुख शेख अब्दुल मेंहदी कर्बलाई से हुई, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हम सबका स्वागत किया. उन्होंने भारतीय भाईचारे एवं मेलजोल की तारीफ़ करते हुए कहा कि कभी इराक़ के लोग भी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आईएसआईएस ने सब बर्बाद कर दिया. कर्बलाई ने भारतीय मीडिया से बार-बार कहा कि इराक में शिया और सुन्नी के बीच कोई जंग नहीं है. अगर भारतीय मीडिया हमारी यह बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सके, तो इराक़ पर उसका एहसान होगा. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ग़लत तस्वीर पेश की जा रही है कि इराक़ में शिया और सुन्नी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है. अगर ऐसा होता, तो आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ने वालों में सुन्नी और ईसाई शामिल न होते. आईएसआईएस ने न सिर्फ़ शिया, बल्कि दूसरे पंथ-मजहब के केंद्रों को भी तबाह किया और सभी का खून बहाया. भारतीय मीडिया ग्रुप को रौज़े इमाम हुसैन, टीला-ए-ज़ैनब, खेमागाह और रौज़ा-ए-अब्बास का भी दौरा कराया गया.

जुमेरात (गुरुवार) का दिन था और शायद हर जुमेरात के दिन इमाम हुसैन के रौज़े पर बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचते हैं. वहां बड़े-बड़े दालानों में काले बुर्क़े पहने महिलाएं बैठी थीं और पुरुष भी. कुछ महिलाओं से बड़ी मुश्किल से बातचीत हुई. भाषा की समस्या थी, लेकिन इशारों की भाषा भी बेहतरीन भाषा है. इसलिए इशारों में उनसे इराक़ के हालात जानने की कोशिश की, तो पता चला कि 11-12 वर्षीय बच्ची से लेकर वृद्ध महिलाएं तक आईएसआईएस से बख़ूबी वाक़िफ़ थीं और उसके लिए दुश्मन शब्द का इस्तेमाल कर रही थीं. पाकिस्तानी महिला सकीना, जिनके पति कर्बला में कार्यरत हैं, ने जुबान समझी और बताया कि आईएसआईएस के आने से पहले इराक बेहतर स्थिति में था, लेकिन आज पूरे मुल्क में हर घर का कम से कम एक युवक आईएसआईएस के ख़िलाफ़ किसी न किसी पैरा मिलिट्री फोर्स में शामिल है. कर्बला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. आबादी में जनजीवन सामान्य था. बाज़ारों में रौनक़ थी. दुकानों में रंग-बिरंगी मिठाइयां सजी हुई थीं. जगह-जगह बुर्क़े बिक रहे थे और गहने भी. किसी के चेहरे पर कोई ख़ौफ़ नहीं था. बताते हैं कि आईएसआईएस के आने के बाद ज़ियारत करने वालों की तादाद में वृद्धि हुई है. इस बार चेहल्लुम (मोहर्रम का चालीसवां दिन) के मौक़े पर तक़रीबन 22 मिलियन ज़ायरीन कर्बला आए.

कर्बला में मिले अल-हसन नामक शख्स का कहना था कि ज़ायरीन की लगातार बढ़ती तादाद साबित करती है कि लोग आईएसआईएस से नहीं डरते. कर्बला में हमने शहीदों के जनाज़े भी निकलते देखे. आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जब कोई शिया मारा जाता है, तो उसका जनाज़ा जुलूस की शक्ल में बड़ी इज्ज़त के साथ लाया जाता है, जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते हैं. अल-हसन ने बताया कि सद्दाम हुसैन के बाद फौज में किसी की अनिवार्य रूप से भर्ती नहीं होती थी, लेकिन शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह सिस्तानी के फ़तवे के बाद इराक़ के हर घर से पंद्रह से पचपन साल तक का कोई न कोई पुरुष फ़ौज में शामिल हुआ है. कर्बला से बग़दाद तक सौ किलोमीटर का सफ़र यूं तो ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते बड़ी-बड़ी तोपों और टैंकों के साथ इराक़ी सैनिक नज़र आए. कड़ी जांच-पड़ताल के बाद जब हम दजला के किनारे बसे बग़दाद पहुंचे, तो नज़ारा देखकर दंग रह गए. वह बग़दाद, जो अब्बासी ख़िलाफ़त का केंद्र था, जो पूरी दुनिया में तिजारती शहर क़ाहिरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक शहर माना जाता था, जिस बग़दाद की तस्वीर हम अपने ज़ेहन में लेकर गए थे, बिल्कुल बदला हुआ था. गगनचुंबी इमारतें, जिन पर कभी सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगी होती थी, उन पर गोलियों के निशान नज़र आ रहे थे. दजला नदी के पुल से हशद अल शाबी (अर्द्धसैनिक बल) के वाहन गुज़र रहे थे. सैनिकों में कम उम्र के युवक भी शामिल थे. सड़क पर भीख मांगती ग़रीब एवं वृद्ध महिलाएं भी नज़र आईं. शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी के रौज़े के क़रीब एक धूल-मिट्टी से अटा बाज़ार था, जहां ज़ायरीन अपनी पसंद की चीजें ख़रीद रहे थे. लेकिन, ख़ुशहाल बग़दाद कहीं खो गया था.

इराक़ी मुद्रा, जिसका कभी दुनिया में जलवा था, आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है. एक हज़ार भारतीय रुपये के बदले 17 हज़ार इराक़ी दीनार मिल रहे थे. शेख़ अब्दुल क़ादिर के रौज़े पर ख़ानकाह-ए-क़ादरिया के सज्जादानशीन शेख़ अब्दुल हमीद मोहम्मद से मुलाक़ात हुई, जिनके बेटे चार मार्च, 2014 को बग़दाद के नज़दीक एक हमले में मारे गए थे. उनका कहना था कि इस वक्त इराक़ का असल दुश्मन आईएसआईएस है और उसके ख़िलाफ़ जंग में सुन्नी भी शामिल हैं. बग़दाद में 20 मिनट रुकने के बाद एक जगह हम भोजन के लिए रेस्टोरेंट में गए, जहां युवकों के साथ-साथ छोटे-छोटे बच्चे भी काम करते नज़र आए. जब उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सद्दाम के वक्त खाने को था, बोलने की आज़ादी नहीं थी. अब बोलने की आज़ादी है, तो खाने को नहीं है. पूरा बग़दाद देखना तो संभव नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन के महल के सामने से गुज़रते हुए महसूस हुआ कि जहां कभी पानी के नलों की टोटियां तक सोने की होती थीं, बड़े-बड़े खूबसूरत क़ालीन बिछे रहते थे, वहां आज धूल उड़ रही थी. हमारे ड्राइवर ने अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी जुबान में बताया कि एक वक्त था, जब ख़ौफ़ के चलते यहां से कोई गुज़रता नहीं था और लोग दूर से सिर झुकाकर निकल जाते थे और आज है कि उल्लू बोल रहे हैं. बग़दाद की सड़कों पर शहीदों की तस्वीरें मीलों तक लगी हुई नज़र आईं. ये लोग इराक़ी फौज़ में थे और आईएसआईएस के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए थे. बग़दाद में आईएसआईएस से लोहा लेने वाले सिविल मिलिशिया के लोगों से भी मुलाक़ात हुई. सिविल मिलिशिया अल हशद के सलाहकार करीम अल नूरी और सूबा अल-अंबार के कमांडर इन चीफ शेख़ मोहम्मद मुख़लिफ़ ने बताया कि आईएसआईएस के ख़िलाफ़ तीन मोर्चों पर जंग जारी है. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं सिविल मिलिशिया अल हशद ने अली अकबर ब्रिगेड, अल अब्बास ब्रिगेड, मोक्तदा अलसद्र बिग्रेड के साथ मिलकर आईएसआईएस से मुक़ाबला किया और तिकरित, रमादी, सलाहुद्दीन व अल-अंबार में कामयाबी हासिल की.

सुन्नी फिरक़े से संबंध रखने वाले शेख़ मोहम्मद मुख़लिफ़ का कहना था कि आईएसआईएस ने हज़ारों सुन्नियों को मार डाला, उनके घर उजाड़ डाले. वह सुन्नी कबीलों को यह कहकर उकसा रहा है कि वे उसकी फौज़ में शामिल होकर शियाओं को नेस्तनाबूद करें. शेख मोहम्मद मुख़लिफ़ से जब पूछा गया कि हशद शिया मिलिशिया है? तो उन्होंने कहा, जब हमने देखा कि शिया बसरा और कर्बला के अंदर हमें बचाने आ गए हैं, तो यह एहसास हुआ कि ये हमारे भाई हैं. छोटे व कम उम्र के बच्चों को मैदान-ए-जंग में कैसे भेजा जा सकता है? इस सवाल पर वजीर-ए-आज़म के सलाहकार फालेह अल फैयाज़ ने कहा, हम उन्हें तीन महीने की ट्रेनिंग देते हैं. इस वक्त इमरजेंसी का माहौल है और फिर जिहाद के ख़तरे के बाद हमारी पहली ज़िम्मेदारी मुल्क है. हिंदुस्तानियों के आईएसआईएस में शामिल होने के सवाल पर अल अब्बासी ब्रिगेड के सीनियर कमांडर शेख़ मुस्लिम अल ज़ैदी का कहना था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया समेत तक़रीबन 80 देशों के लोग आईएसआईएस में शामिल हैं, लेकिन हिंदुस्तान से किसी के शामिल होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. अल हशद के डायरेक्टर जनरल सैयद अफ़ज़ल अल सामी का कहना था कि इराक़ से ख़ात्मे के बाद आईएसआईएस दक्षिणी एशिया का रुख़ कर सकता है, इसलिए हिंदुस्तान को सावधान रहने की ज़रूरत है.

पूरे इराक़ में, चाहे वह नजफ़ हो, कर्बला हो, बग़दाद हो या कुफ़ा, हर तरफ़ फ़ौजी टैंक नज़र आ रहे थे. दुकानों पर ज़रूरत की हर वस्तु मौजूद थी, लेकिन जब बिस्किट के एक छोटे पैकेट की क़ीमत एक हज़ार दीनार बताई गई, तो हमारी सांस रुक-सी गई. एक खुशहाल मुल्क, जो जंग का शिकार रहा, जिसने गृहयुद्ध झेला और अब आईएसआईएस का आतंक झेल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था की बदहाली हमने अपनी आंखों से देखी. बग़दाद में एक बुज़ुर्ग से पानी की बोतल खरीदते समय जब हमने उनकी माली हालत के बारे में पूछा, तो उस बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए. कर्बला सूबे के गवर्नर अक़ील अल तुरैही से जब इराक़ की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था, सरकार ने मोबाइल स्कूल बनाए हैं, हमारे पास अस्पताल नहीं है. दुनिया को चाहिए कि वह हमारा साथ दे, ताकि हम उबर सकें. जो लोग आईएसआईएस के हाथों बर्बाद हुए हैं, हमारी कोशिश है कि शांति के बाद उन्हें वहीं बसाया जाए, जहां से वे आए हैं. फ़िलहाल तालीम का बेहतर इंतज़ाम नहीं है. अभी हम सिर्फ़ शरणार्थियों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

कर्बला शहर में रात के वक्त इमाम हुसैन के रौज़े पर जो रौनक़ नज़र आती है, वह कहीं और नज़र नहीं आई. इसी तरह बग़दाद, जो कभी नाइट लाइफ के लिए मशहूर था, अब शाम ढलते सूना हो जाता है. इराक़ के सभी शहरों में शरणार्थी शिविर लगे हैं. भारतीय मीडिया ग्रुप ने जब ऐसे ही एक शिविर का दौरा किया, तो कैमरे और पत्रकारों को देखकर बड़ी संख्या में बच्चे एकत्र हो गए. वे धूल से सने थे, कई बच्चों के पैरों में चप्पलें तक नहीं थीं. इस शिविर में 8,500 लोग हैं, जिनमें शिया, सुन्नी एवं ईसाई यानी सभी शामिल हैं. जब हमने शिविर के प्रबंधक से पूछा कि इनमें कितने शिया, सुन्नी या ईसाई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब इराक़ी हैं. शिविर में मौजूद एक साठ वर्षीय महिला, जो अपने पति और बच्चों को आईएसआईएस के हमले में खो चुकी हैं, ने जब हमसे भोजन के लिए पूछा, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए. हम कर्बला यूनिवर्सिटी भी गए, जहां लड़कियों के मुक़ाबले लड़के कम नज़र आए. स्थानीय अख़बार रौज़ा-ए-हुसैन के संपादक सैयद सबाह तालिबानी ने कहा कि जो हालत 1947 से पहले हिंदुस्तानियों की थी, वही इस वक्त हमारी है. यहां शिया-सुन्नी की लड़ाई नहीं है, यहां सिर्फ़ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई है, वतन को बचाने की लड़ाई है और हमारे वजूद की लड़ाई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश का युवा आक्रोशित क्यों है

राजीव रंजन

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और देशद्रोह के आरोप में फंसे जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को न्याय दिलाने के लिए पिछले दिनों हज़ारों छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया. झंडेवालान स्थित अंबेडकर भवन से शुरू हुआ यह मार्च जेएनयू के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था. इसमें जेएनयू, जामिया मिलिया सहित कई विश्वविद्यालयों के छात्रों के अलावा रोहित वेमुला के परिवारीजन और बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बीएपीएसए), नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (एआईएसए) स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), मूल निवासी संघ-हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे संगठन शामिल हुए. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं वाम दलों के बड़े नेता भी जंतर-मंतर पहुंचे. मार्च में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिस्सा लिया.

छात्रों के मार्च का समर्थन करते हुए राहुल गांधी आरएसएस पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है. हरियाणा में जो कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा. उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला भविष्य की बात करते थे, इसलिए उनका दमन किया गया. वह देश की बेहतरी और उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन आरएसएस भूतकाल की बात करता है और उसका सिद्धांत है कि जो भी भविष्य की बात करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा. भाजपा और संघ को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ऐसा भारत चाहता है, जहां सिर्फ़ उसकी विचारधारा चले, लेकिन हम ऐसे भारत की लड़ाई लड़ते हैं, जहां हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी. राहुल ने कहा, मैं जब हैदराबाद गया था, तो मैंने वहां बताया था कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव समाप्त करने के लिए क़ानून की ज़रूरत है.

भेदभाव ख़त्म करे सरकार

रोहित वेमुला जैसे छात्र, बल्कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. रोहित के साथ जो हुआ, वैसे सामाजिक भेदभाव की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो. जेएनयू के छात्रों पर लगे देशद्रोह के मामले वापस लिए जाएं. सरकार का हस्तक्षेप ख़त्म हो. हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए. अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी, तो हम जनता के पास जाएंगे. सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए उससे कोई खास उम्मीद नहीं है. उम्मीदें जनता से हैं, खुद से हैं. उमर खालिद या अन्य छात्र सुरक्षा कारणों से परिसर से गायब थे. जब मामला ठंडा पड़ा, सुरक्षा मिली, तो वे वापस आ आए.

-जाबाज, *जेएनयू छात्र.*

साज़िश

सरकार ने साज़िश के तहत कन्हैया को फंसाया है. कन्हैया ने जेएनयू में किसी तरह का देशद्रोही नारा नहीं लगाया था. जेएनयू के छात्र देशभक्त हैं. हम कन्हैया की रिहाई तक संघर्ष करते रहेंगे.

-देवीदीन, *बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बीएपीएसए), जेएनयू.*

खाली पद भरे जाएं

देश के विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं छात्राओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वह ख़त्म किया जाए. शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पद भरे जाने चाहिए.

-आकाश गौतम, *बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बीएपीएसए), जेएनयू.*

कन्हैया ग़रीबी के ख़िलाफ़ लड़ता है

रोहित वेमुला पीएचडी छात्र था. जब उसके जैसे छात्र को टॉर्चर और आत्महत्या करने को मजबूर किया जा सकता है, तो एक आम छात्र की बिसात क्या है. कन्हैया मेरा जूनियर है, उसे मैं भलीभांति जानता हूं. वह ग़रीबी और भुखमरी के ख़िलाफ़ लड़ता है. वह देश के ख़िलाफ़ कभी भी नारे नहीं लगा सकता. यह सारा दुष्प्रचार मीडिया का है.

-डॉ. दशरथ, *बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बीएपीएसए), जेएनयू.*

सब कुछ जल्दबाजी में किया गया

धरना-प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है. कोई किसी के पक्ष में भी बोल सकता है और विरोध में भी. रोहित वेमुला को देश विरोधी करार दिया गया, उसे हॉस्टल में प्रवेश नहीं करने दिया गया. जेएनयू प्रकरण में इतनी जल्दबाजी हुई कि कुछ भी समझ में नहीं आया. मीडिया के कुछ लोग कुछ ही पलों में फ़ैसले तक सुना देते हैं, वकील ऊल-जुलूल बयान देते हैं. जहां तक जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने की बात है, तो मैं उस दिन परिसर में नहीं था. लेकिन, मैं कह सकता हूं कि परिसर में देश विरोधी नारे नहीं लगे होंगे. फुटेज की सही तरीके से जांच होनी चाहिए. हमारे यहां न्यायपालिका है, उसे फ़ैसले सुनाने दें, न कि खुद किसी फ़ैसले तक पहुंच जाएं.

-अमन, *जेएनयू.*

चलो दिल्ली नामक इस मार्च में शामिल बुद्धिजीवी, छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा एवं लाल-नीले झंडे लिए थे. छात्रों का कहना था कि जैसा रोहित वेमुला के साथ हुआ, वैसा किसी और के साथ न हो, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए. छात्रों ने मांग की कि कन्हैया कुमार के ख़िलाफ़ दर्ज देशद्रोह का मुक़दमा वापस लिया जाए, वीडियो फुटेज की जांच हो और मीडिया ट्रायल को सुबूत मानकर कार्रवाई न हो. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी एवं ओबीसी कोटे की रिक्तियां भरी जाएं, ब्राह्मणवादी प्रोफेसर दलित छात्रों के साथ भेदभाव बंद करें. छात्रों का कहना था कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दें.

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोहित वेमुला समाज के दबे-कुचले लोगों की आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें खुदकुशी करने को विवश किया. केजरीवाल ने कहा कि कन्हैया के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं है. केंद्र सरकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है और उसके आदर्श नाथूराम गोडसे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दलित विरोधी है और उससे कोई भी खुश नहीं है. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह भी दी कि छात्रों से पंगा मत लेना. हालांकि, उस समय उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ी, जब लोगों ने आरक्षण विरोधी केजरीवाल जैसे नारे लगाए. केजरीवाल बोले, मैंने कब कहा कि आरक्षण विरोधी हूं. मैंने तो हमेशा आरक्षण का समर्थन किया. ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली की सुरक्षित विधानसभा सीटों से चुनाव जीते आम आदमी पार्टी के विधायक निजी तौर पर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मार्च में शामिल हुए. मार्च में आम आदमी पार्टी की युवा छात्र इकाई ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी को क्या मिला

तरुण फोर

सारे देश की नजर रेल बजट पर टिकी थी. लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार का रेल बजट कुछ ऐसा होगा, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचेगा. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में रेल बजट पेश किया. बजट पेश करने से पहले उन्होंने कहा कि यात्री रेलवे की आत्मा हैं. हमारी प्राथमिकता में यात्रियों की सुरक्षा और सेफ्टी सबसे ऊपर है. रेल मंत्री के मुताबिक, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया रेलवे के लिए प्राथमिकता रहेगी. बजट में यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इससे पिछले बजट में भी सरकार ने किसी तरह का रेल किराया बढ़ाने की घोषणा नहीं की थी. बावजूद इसके, साल भर यात्रियों को झटके पर झटके लगते रहे. सालभर में रेलवे ने रेल बजट के बाद बिना बताए ही तमाम तरह के किरायों में वृद्धि कर दी. इस बजट में सिक्योरिटी के लिए स्टेशनों, बोगियों में सीसीटीवी की बात कही गई है. रेल मंत्री ने कहा कि हमने 2020 तक बड़ी लाइनों के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है. साथ ही 2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य रखा गया है. रेल मंत्री ने एलान किया कि 2020 तक 95 फीसदी ट्रेनें समय पर चलेंगी. ट्रेन के हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगेंगे. चार नए प्रकार की स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं. पहली ट्रेन हमसफर, जिसमें सिर्फ एसी थ्री कोच होंगे. बोगियों में खाना भी मिलेगा. दूसरी अंत्योदय ट्रेन, जिसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड कोच ही होंगे. तीसरी ट्रेन तेजस, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और उसमें वाई-फाई भी मिलेगा. चौथी ट्रेन, उदय है, जो डबल डेकर एयरकंडीशन्ड यात्री ट्रेन है. यह बिजी रूट्स पर ओवरनाइट चलेगी.

चार नई प्रकार की ट्रेनों के अलावा ट्रेनों से जुड़े कुछ और भी नए एलान किए गए हैं. जैसे तीर्थ स्थानों के लिए आस्था सर्किट ट्रेनें चलेंगी. इसके तहत अजमेर, बिहारशरीफ, मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार, तिरुपति, द्वारका और गया स्टेनशनों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. दिल्ली में रिंग रेल सर्विस का विस्तार किया जाएगा. इसमें 21 स्टेशन बनाए जाएंगे. अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद में सब अर्बन ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा. मुंबई में एलिवेटेड ट्रेन चलेगी. कोलकाता में मेट्रो रेल के 100 किमी का विस्तार किया जाएगा. प्रभु ने रेल बजट में सोशल मीडिया का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से रोज रेलवे को एक लाख से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं. सोशल मीडिया रेलवे के लिए शिकायतों का प्लेटफॉर्म है. सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि यात्री 139 पर फोन करके टिकट कैंसिल करा पाएंगे. उन्होंने दिल्ली में रिंग रोड के तर्ज पर रिंग रेलवे सेवा से 21 स्टेशनों को जोड़ने की भी घोषणा की. सुरेश प्रभु ने कहा कि हम संचालन अनुपात 92 फीसदी हासिल करने की कोशिश करेंगे. इस साल के आकलन में 8720 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है. रेल बजट में 1.21 लाख करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है. प्रभु ने कहा कि उन्हें सरकार से 40 हजार करोड़ रुपये बजटीय सहयोग की उम्मीद है. नए बजट के मुताबिक अब रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी. महिला हेल्पलाइन बनाई जाएगी, जो 24 घंटे काम करेगी. 2017 से 400 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा मिलेगी. मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक 17 हजार अतिरिक्त जैविक शौचालय चालू हो जाएंगे.

रेल बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं. महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 होगा. रेल में यात्रा कर रहे महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए अलग से खाना उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिहाज से बोगी के बीच में महिलाओं का आरक्षण होगा. 311 स्टेशनों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे. हर कैटेगरी में 30 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए होंगी. रेल बजट से आम आदमी को क्या मिला, इसकी अगर बात की जाए तो कुछ छोटी-मोटी सुविधाओं के अलावा, कुछ खास देखने को नहीं मिला. मसलन, जनरल बोगी में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी. यात्री अब जनरल बोगी में भी बिस्तर खरीद सकेंगे. रेल में बुजुर्गों के लिए 120 सीटें आरक्षित होंगी. सारथी सेवा दिव्यांगों और वृद्धों के लिए भी शुरू की जायेगी. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, प्रोजेक्ट फाइनेंस, आधुनिक फाइनेंसिंग और निजी निवेश से रेलवे को जोड़ने की नई पहल की गई है. लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं, जहां प्रभु की रेल धीमी दिख रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रेल बजट से जुड़ी कुछ खास बातें

- रेलवे बॉन्ड जारी करेगी, विदेश से पैसा जुटाने की योजना.
- रेलवे यात्रियों के डाटा का कॉमर्शियल इस्तेमाल करेगा.
- रेलवे भाड़ा कारोबार को यात्री से अलग करने की शुरुआत कर रही है.
- रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन सबसे महत्वपूर्ण सुधार, पीपीपी सेल बनेगा .
- रेलवे में निजी व बैंकिंग निवेश लाने की कोशिश.
- प्रभु ने रेल की गति बढ़ाने का खाका पेश किया. भारतीय रेल दुनिया में सबसे धीमी चलती है.
- नौ किलोमीटर ब्रॉड गेज प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य.
- रेलवे को निजी निवेश और आधुनिक फाइनेंस से जोड़ने की नई पहल.

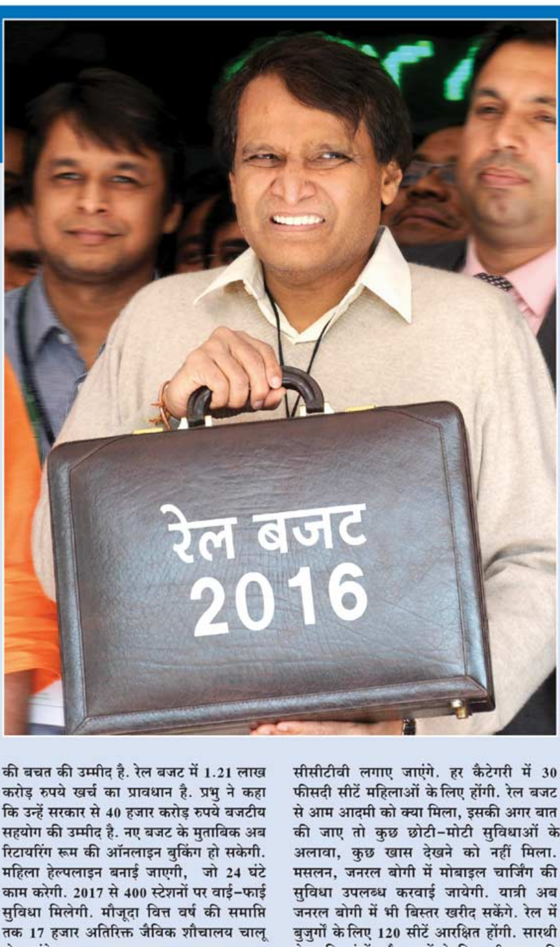

किसने क्या कहा

रेलवे पटरी से उतर गई है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन आय घटती जा रही है.

- लालू प्रसाद यादव

पिछले साल का रेल बजट जीरो बजट था, इस साल का रेल बजट भी जीरो बजट है और दोनों को मिलाकर देखें तो यह एक बिग जीरो है.

- डेरेक ओ ब्रायन, *तृणमूल कांग्रेस*

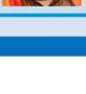

यह सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है.

- अमित शाह

यात्री किराया नहीं बढ़ाने के पीछे सबसे अहम कारण इस साल पांच राज्यों में होने वाले चुनाव हैं.

- मल्लिकार्जुन खड़गे, *कांग्रेस*

इस रेल बजट में कुछ भी नया नहीं है और ऐसा रेल बजट लाने से बेहतर होता कि रेलमंत्री इसे पेश ही नहीं करते.

- दिनेश त्रिवेदी, *पूर्व रेलमंत्री.*

यह दिशाहीन बजट है. सिर्फ आंकड़ों को पेश करके कई तरह के दावे किए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है.

- मोहम्मद सलीम, *सीपीएम*

नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने सात निश्चयों की घोषणा की थी और ऐतिहासिक जनादेश के ज़रिये सत्ता में आने के बाद वह उन्हें लागू करने को आतुर हैं. उक्त सात निश्चयों के ज़रिये वह सूबे के छात्र, युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ-साथ ग्रामीण बिहार को व्यापक तौर पर अपने साथ जोड़ने को बेताब हैं. उनकी राजनीतिक चाहत है कि अगले संसदीय चुनाव के पहले तक उक्त कार्यक्रमों के ज़रिये सूबे में अपना एक ठोस (जाति एवं धर्मविहीन) मतदाता समूह संगठित किया जाए. इसी के मद्देनज़र बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है.

बिहार विकास मिशन

काम कठिन है समय कम

बिहार विकास मिशन का संकट आर्थिक से ज़्यादा दूसरा है. सबसे बड़ी दिक्कत तो प्रशासन की कछुआ चाल को लेकर है. उपलब्धियां पेश करने का सरकारी तरीका पूरी तरह प्रचारमूलक है. नौकरशाह (और उनके फीडबैक पर राजनेता भी) धन आवंटन को ही उपलब्धि मान लेते हैं. आवंटन और कार्यान्वयन के बीच की दूरी बातों से पाट देने की कुटिल परंपरा चल रही है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कल्याण, श्रम एवं रोज़गार सहित विभिन्न विभागों में देखा जा सकता है. इससे सत्ता के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जनता का भरोसा कम होता है.

सरोज सिंह

बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार के सात निश्चयों और विकास मिशन की धूम है. महा-गठबंधन के मंत्री एवं नेता हर काम को सात नीतीश निश्चयों के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं नौकरशाह हर उस काम को अब बिहार विकास मिशन के हवाले छोड़ रहे हैं, जिस पर तत्काल वे कुछ कहना-करना नहीं चाहते. बिहार विकास मिशन के गठन की घोषणा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने की और उसे ज़मीन पर उतारने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा को मिशन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है. मिशन की वित्तीय नियमावली बनाने और अन्य औपचारिक ज़रूरतें पूरी करने की ज़िम्मेदारी मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को सौंपी गई है. मिशन के शासी निकाय की पहली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बातें साफ़ कीं. मिशन के गठन का औपचारिक फ़ैसला बीती 25 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट के संकल्प के अनुसार, मुख्यमंत्री मिशन के अध्यक्ष होंगे. मिशन में राज्य के सभी मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, विकास आयुक्त एवं पुलिस महानिदेशक के अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव भी शामिल किए गए हैं.

मिशन में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रशांत किशोर को खास तौर पर शामिल किया गया है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और उनकी ज़िम्मेदारी नीति निर्धारण एवं उसके कार्यान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री को परामर्श देना है. मिशन के सात उपमिशन होंगे, जो नीतीश कुमार के विभिन्न निश्चयों से जुड़े हैं. बिहार विकास मिशन की बैठक हर दो महीने पर होगी, लेकिन अध्यक्ष जब ज़रूरत समझेंगे, उसकी बैठक आहूत की जाएगी. इसी तरह उपमिशनों की बैठक हर महीने आहूत करने का प्रावधान है. उपमिशन सूबे के विकास आयुक्त की देखरेख में काम करेंगे. उक्त मिशन विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय एवं कार्यक्रम प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे, साथ ही विकास कार्य लागू करने के लिए तकनीकी सहायता, मॉनिटरिंग तंत्र एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के समाधान भी खोजेंगे. इसके मद्देनज़र विभागों को विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश से लेकर ज़िला स्तर तक इकाइयां गठित की जाएंगी, जिनके ज़रिये पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाएं हासिल की जाएंगी. बिहार विकास मिशन एवं उसके सातों उपमिशनों को प्रभावशाली और सक्षम बनाने के लिए सरकार ने उन्हें निदेशक, सहायक निदेशक एवं पेशेवर विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का फ़ैसला भी लिया है.

ग़ौरतलब है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने सात निश्चयों की घोषणा की थी और ऐतिहासिक जनादेश के ज़रिये सत्ता में आने के बाद वह उन्हें लागू करने को आतुर हैं. उक्त सातों निश्चयों के ज़रिये वह सूबे के छात्र, युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ-साथ ग्रामीण बिहार को व्यापक तौर पर अपने साथ जोड़ने को बेताब हैं. उनकी राजनीतिक चाहत है कि अगले संसदीय चुनाव के पहले तक उक्त कार्यक्रमों के ज़रिये सूबे में अपना एक ठोस (जाति एवं धर्मविहीन) मतदाता समूह संगठित किया जाए. इसी के मद्देनज़र बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है. लेकिन, मिशन के गठन के पहले से ही उक्त सात निश्चयों को लेकर वह काफी सक्रिय रहे. नीतीश कुमार की सारी चिंता किसी भी क़ीमत पर महिलाओं, युवाओं एवं छात्रों से जुड़े अपने निश्चय बिना विलंब लागू करने की है. उक्त सात निश्चयों में से एक यानी सरकारी नौकरियों की सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है. अब बिहार सरकार की सभी सीधी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा रही है.

अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ सूबे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू होनी है, जिसके तहत 12वीं उत्तीर्ण प्रत्येक ज़रूरतमंद युवा को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए बैंकों से चार लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराई जाएगी. रोज़गार की तलाश में सूबे से बाहर जाने वाले युवाओं को प्रतिमाह एक-एक हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी योजना है. ज़िलों में रोज़गार परामर्श केंद्र शुरू करने की तैयारी चल रही है. युवाओं एवं छात्रों से संबंधित निश्चयों के तहत कॉलेज-विश्वविद्यालय परिसरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने और स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता विकास के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाने पर काम चल रहा है. उद्यमिता विकास के संदर्भ में मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज-स्कूल, पॉलिटेक्निक आदि संस्थाओं को लेकर भी तैयारी चल रही है. सरकार ने तय किया है कि अगले दो वर्षों के दौरान उन सभी बसावटों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, जो अभी तक वंचित हैं. साथ ही सूबे के सभी विद्युतविहीन घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के निश्चयों को ज़मीन पर उतारने के लिए अगले बजट में विशेष तौर पर धन की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर समीक्षा कर उक्त सात निश्चयों से जुड़े कुछ विभागों के योजना बजट को मंजूरी दे दी है. नीतीश निश्चय लागू करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.39 लाख करोड़ से लेकर 2.70 लाख करोड़ रुपये तक के व्यय का अनुमान है. सरकार ने इन निश्चयों के लिए अब तक 5,581 करोड़ रुपये की योजना अंतिम तौर पर स्वीकार कर ली है. लेकिन, यह तो चंद विभागों के खर्च का आकलन है. सभी निश्चयों से जुड़े विभागों को 60 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक रकम आवंटित करनी होगी. एक अधिकारी के अनुसार, राज्य के अधिकांश कल्याण कार्यक्रम इन निश्चयों के दायरे में आते हैं, लिहाजा धन की कोई समस्या आड़े नहीं आएगी.

दशकों पुराने अति विश्वस्त राजनीतिक सहकर्मी-सखा और प्रिय नौकरशाहों की भी नीतीश कुमार से दूरी बढ़ रही है. महा-गठबंधन सरकार के अधिकांश मंत्रियों को लगता है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर सुपर मंत्री बन गए हैं. चूंकि नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में मुख्यमंत्री को सलाह देने की ज़िम्मेदारी उनकी है, लिहाजा मान लिया गया है कि उन्हें संतुष्ट किए बगैर किसी भी मसले पर मुख्यमंत्री की सहमति कठिन है.

यह सही है कि नीतीश कुमार के उक्त सात निश्चय लागू करने में पैसा बाधक नहीं बनेगा और सरकार की इच्छाशक्ति पर भी किसी को अविश्वास नहीं है. नीतीश अगर कोई काम ठान लेते हैं, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से बिहार भलीभांति परिचित है. उनके उक्त निश्चयों को लेकर सत्तारूढ़ महा-गठबंधन के घटक दलों में भी कोई मतभिन्नता नहीं है, बल्कि सर्व-सहमति है. स्वच्छता एवं पेयजल जैसे कार्यक्रमों के लिए केंद्र ने भी खजाना खोल रखा है. उद्यमिता विकास से जुड़े नीतीश के निश्चयों को केंद्रीय उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से एक बड़ी मदद मिलेगी. केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ने से केंद्र से पैसा भी भरपूर आ रहा है. सो, विविध कल्याण कार्यक्रमों केसाथ-साथ उक्त निश्चयों को पूरा करना आसान हो जाएगा. यह तय है कि राज्य को अपने आंतरिक स्रोतों से भी धन की व्यवस्था करनी होगी. ऐसे में जहां बैंकों पर निर्भरता अधिक है, वहां परेशानी हो सकती है. इस लिहाज से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ युवा-छात्र कल्याण संबंधी अनेक कार्यक्रम लागू करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नीतीश स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस साल नए शैक्षणिक सत्र के साथ शुरू करने को कृत संकल्प हैं, लेकिन अभी तक बैंकों का रुख बहुत सहज नहीं दिख रहा. इस क्रेडिट कार्ड के ऋण की ब्याज दर को लेकर भी अब तक सहमति नहीं बन सकी है. इसी तरह ग्रामीण सड़क योजना के मद में केंद्रीय सहायता में कमी आने से गांव-गांव सड़क कार्यक्रम की गति भी धीमी पड़ सकती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की कमी भी बिहार के आड़े आ सकती है. निश्चित तौर पर उक्त सारी बाधाएं दूर करने के ठोस उपाय करने होंगे.

बिहार विकास मिशन का संकट आर्थिक से ज़्यादा दूसरा है. सबसे बड़ी दिक्कत तो प्रशासन की कछुआ चाल को लेकर है. उपलब्धियां पेश करने का सरकारी तरीका पूरी तरह प्रचारमूलक है. नौकरशाह (और उनके फीडबैक पर राजनेता भी) धन आवंटन को ही उपलब्धि मान लेते हैं. आवंटन और कार्यान्वयन के बीच की दूरी बातों से पाट देने की कुटिल परंपरा चल रही है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कल्याण, श्रम एवं रोज़गार सहित विभिन्न विभागों में देखा जा सकता है. इससे सत्ता के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जनता का भरोसा कम होता है. और, बिहार में यही हो रहा है. मुख्यमंत्री के जनता दरबार सहित अनेक कार्यक्रमों में इसकी झलक देखी जा सकती है. मुख्यमंत्री के सातों निश्चयों को लेकर राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर सतत जागरूकता की ज़रूरत है. ग़लत फीडबैक से नौकरशाही को नहीं, राजनीतिक नेतृत्व को नुक़सान हो सकता है, जिसकी विश्वसनीयता दांव पर है. योजना के कार्यान्वयन एवं धन के इस्तेमाल के लिए बेहतर रोडमैप और उसका अनुपालन ज़रूरी है. बिहार में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बड़ी रकम सरेंडर हो जाती है या फिर उसे रख लिया जाता है. इस बार भी हालत सुखद नहीं है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और अब भी विभिन्न विभागों को आवंटित धन में से 25 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होने बाकी हैं. इससे मार्च-लूट के ज़रिये वित्तीय हेराफेरी की गुंजाइश बढ़ जाती है. ऐसा क्यों होता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. उम्मीद है कि नीतीश कुमार के सात निश्चयों के कार्यान्वयन पर लापरवाह और ग़ैर जवाबदेह नौकरशाही की छाया नहीं पड़ेगी.

बिहार की मौजूदा सत्ता राजनीति में प्रशांत किशोर ताकतवर नाम बन गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वह सबसे विश्वस्त सहयोगी माने जाने लगे हैं. दशकों पुराने अति विश्वस्त राजनीतिक सहकर्मी-सखा और प्रिय नौकरशाहों की भी नीतीश कुमार से दूरी बढ़ रही है. महा-गठबंधन सरकार के अधिकांश मंत्रियों को लगता है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर सुपर मंत्री बन गए हैं. चूंकि नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में मुख्यमंत्री को सलाह देने की ज़िम्मेदारी उनकी है, लिहाजा मान लिया गया है कि उन्हें संतुष्ट किए बगैर किसी भी मसले पर मुख्यमंत्री की सहमति कठिन है. इसी तरह शीर्ष नौकरशाही के एक तबके को लगता है कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच अब तक केवल मुख्य सचिव होते थे, लेकिन अब सलाहकार भी आ गए हैं. इस तबके को लगता है कि प्रशांत किशोर की रिपोर्टिंग उनके भविष्य के लिए बहुत अहम है. हालांकि, प्रशांत किशोर को लेकर अब तक कोई ग़लत रिपोर्ट कहीं से नहीं सुनी गई है, लेकिन सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा का विषय रहा है. यही नहीं, विकास मिशन की पहली बैठक में ही दबे स्वरों में इस आशय की राय सामने आई. हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपने और अधिकारियों के बीच किसी तीसरे के आ जाने की आशंका सिरे से खारिज कर दी. इन तमाम हालात के चलते विकास मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं समय की भी खासी कमी है. नीतीश कुमार अगले संसदीय चुनाव तक अपने निश्चयों की उपलब्धियां पेश करने में खुद को समर्थ देखना चाहते हैं. उनकी राजनीतिक ज़रूरत और वक्त की कमी जैसे दो पाटों को मिशन आख़िर कैसे साधता है, यह देखना दिलचस्प होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल सरकार के कार्यों एवं विचारों को दर्शाता है. सरकार के साथ समस्या यह है कि वह बोलती कुछ है और करती कुछ है. मोदी जी के सभी भाषणों में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात होती है. वह कहते हैं कि संविधान ही एकमात्र किताब है, जिसका अनुसरण देश को करना चाहिए. दूसरी तरफ़ एक मंत्री यह सुझाव देते हैं कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाना चाहिए. समस्या यह है कि आरएसएस से जुड़े संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं श्रीराम सेना आदि, जो सीधे उनसे (मोदी) नहीं जुड़े हैं, लेकिन वे सब मिलकर हिंदू विचार को थोपने की कोशिश करते हैं.

भारत के लोग अंधे और बहरे नहीं हैं

रेल बजट पेश किया गया. कोई विशेष योजना, विशेष छूट या अतिरिक्त भाड़ा वृद्धि नहीं देखी गई. मूल रूप से यह एक आम रेल बजट की तरह रहा. निश्चित तौर पर कुछ स्वागत योग्य क़दम उठाए गए, मसलन, वृद्धों एवं महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण आदि. यह सब किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि रेलवे एक संस्था के तौर पर बहुत अक्षमता के साथ चल रहा है. उसे कड़ी निगरानी की ज़रूरत है. यह काम अतिरिक्त प्रबंधन, विशेष योजनाओं और कुछ खास तरह की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के ज़रिये हो सकता है.

जैसे कि हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं. रेलवे में हमेशा गंदगी रहती है. जब भी हम रेल यात्रा करते हैं, तो पाते हैं कि रेलें साफ़ नहीं हैं. अन्य एफिशिएंसी पैरामीटर्स (दक्षता मानदंडों) और बुलेट ट्रेन की बात भूल जाइए, आप सिर्फ़ पहले रेल की स्वच्छता सुनिश्चित कीजिए, रेल यात्रा को आरामदायक बनाइए. इस कार्य में आप ठेकेदारों को लगा सकते हैं और उन्हें इसके लिए भुगतान कर सकते हैं. जब हम यूरोप में रेल यात्रा करते हैं, तो देखते हैं कि रेलें कितनी साफ़-सुथरी और आरामदायक हैं. ज़ाहिर तौर पर वहां और यहां के बीच अंतर है. भारत के मुक़ाबले वहां रेलों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम है. भारत में लाखों लोग रोज़ाना रेल से सफर करते हैं. इस सरकार को आए दो साल हो चुके हैं. प्रधानमंत्री ने खुद 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी. अब रेल यात्रा को अधिक आरामदायक और खुशनुमा बनाने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए. रेल बजट ठीकठाक है. सुरेश प्रभु के पास लालू यादव जैसा कोई करिश्मा नहीं है और न वह उनकी तरह अपना बजट भाषण पढ़ते हैं. वह एक सक्षम, लेकिन दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने अपना बजट भाषण सामान्य तरीके से पढ़ा.

दूसरा मुद्दा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण. राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल सरकार के कार्यों एवं विचारों को दर्शाता है. सरकार के साथ समस्या यह है कि वह बोलती कुछ है और करती कुछ है. मोदी जी के सभी भाषणों में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात होती है. वह कहते हैं कि संविधान ही एकमात्र किताब है, जिसका अनुसरण देश को करना चाहिए. दूसरी तरफ़ एक मंत्री यह सुझाव देते हैं कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाना चाहिए. समस्या यह है कि आरएसएस से जुड़े संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं श्रीराम सेना आदि, जो सीधे उनसे (मोदी) नहीं जुड़े हैं, लेकिन वे सब मिलकर हिंदू विचार को थोपने की कोशिश करते हैं. वे सब देश में एक ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहते हैं, जहां हिंदू हावी हों. भारत में तो पहले से ही 85 प्रतिशत आबादी हिंदुओं की है. वे प्रमुख धर्म के तौर पर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उक्त संगठनों में हीनता का एक बोध है. वे हिंदू समुदाय को आक्रामक बनाना चाहते हैं. इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. यह सब कैसे ख़त्म होगा, एक गंभीर मुद्दा है. निश्चित तौर पर राष्ट्रपति वही बोलेंगे, जो सरकार के रिकॉर्ड में है. अन्य संगठन जो कुछ कर रहे हैं, वह क़ानून व्यवस्था की समस्या है. इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण ठीक है.

अब एक और बात, जिसे सरकार में शामिल लोग अपने लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं. स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लंबा भाषण दिया. मैंने वह भाषण सुना. सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि वह एक अच्छी वक्ता हैं, उनकी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी है, उनके तथ्य ठीक हैं. असल में वह एक सांसद के तौर पर भी भाजपा के लिए बेहतर वक्ता हो सकती हैं. हालांकि, इसका फ़ायदा सिर्फ़ राज्यसभा में मिलेगा, क्योंकि ईरानी राज्यसभा सदस्य हैं. अब बात आती है उनके अपने मौजूदा दायित्व की. मैं इस धारणा को नहीं मानता कि चूंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए. यहां हमें संविधान देखना चाहिए. यह साफ़ है कि सांसद कौन बन सकता है. एक खास उम्र के बाद और कुछ निश्चित मानदंड पूरा करने वाला शख्स सांसद बन सकता है. और, जो सांसद बन सकता है, वह मंत्री भी बन सकता है. इसलिए ऐसे तर्क सही नहीं हैं. इससे कोई समस्या भी नहीं है. उनके भाषण में दो-तीन बातें महत्वपूर्ण हैं. पहली बात यह कि पुलिस और सरकार ने जेएनयू प्रकरण में जो कुछ किया, उसे लेकर उन्होंने अपने पक्ष में कई सारे तर्क देने की कोशिश की. लेकिन, पुलिस की कार्रवाई सही नहीं थी. पुलिस ने इस मामले में असंगत और सीमा से बाहर जाकर काम किया. यह सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मदद करने के लिए किया गया, जिसने पहले से ही एक ग़लत टेप बनाकर मीडिया और लोगों के बीच बांट दिया था. बाद में पता चला कि यह जानबूझ कर ग़लत ढंग से बनाया गया टेप है. जिस तेजी के साथ यह टेप बनाया और जारी किया गया, उससे लगता है कि शायद इसके लिए कुछ पुलिस वालों को भी विश्वास में लिया गया हो. यह एक गंभीर मुद्दा है. अंतिम बार जिस जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष को आपातकाल के समय गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम है डीपी त्रिपाठी.

पीडीपी, जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई, का यह आधिकारिक रुख है कि अफजल गुरु की फांसी ग़लत थी. फिर भी भाजपा को पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन, यदि एक छात्र अफजल गुरु के बारे में ऐसी बात बोलता है, तो उसे गिरफ्तार करके उसके साथ बदसलूकी की जाती है. यह किस तरह का तर्क है? क्या आप सोचते हैं कि भारत के लोग अंधे और बहरे हैं? ऐसा नहीं है. हर कोई देख रहा है, सबको सच पता है. जितनी जल्दी सरकार अपनी यह ग़लती सुधार ले, उतना ही बेहतर है.

बहरहाल, मूल तथ्य यह है कि जेएनयू एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जहां सभी प्रकार के विचारों को फलने-फूलने का मौक़ा मिलता है. यह कार्रवाई दिखाती है कि सत्ता का असल मकसद कुछ और है. असहमति अपराध नहीं है. यदि असहमति को अपराध बनाया जाता है, तो यह एक ख़तरनाक बात है. कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि देशद्रोह तभी है, जब सत्ता को गिराने या राष्ट्र के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने की कोशिश की जाए. नारेबाजी के ज़रिये महज अपने विचार व्यक्त करना देशद्रोह नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस में फाली एस नरीमन ने सही लिखा है कि यदि छात्र सचमुच भारत की बर्बादी जैसे नारे लगा रहे थे, तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके माता-पिता से कहा जाए कि वे अपने बच्चे के दिमाग़ की जांच कराएं. कोई भी भारत की बर्बादी नहीं चाहता. कोई भारतीय इस बात को पसंद नहीं करता. जहां तक अफजल गुरु की बात है, तो पूरा कश्मीर उसकी फांसी के ख़िलाफ़ है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी खुद सुप्रीम कोर्ट के बजाय जनता की सामूहिक चेतना की बात करता है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट वह जगह नहीं है, जहां कोई फ़ैसला करने के लिए जनता की राय या मतदान की ज़रूरत हो. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी को फांसी दी जाती है. इससे कम सजा दी जा सकती थी. पीडीपी, जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई, का यह आधिकारिक रुख है कि अफजल गुरु की फांसी ग़लत थी. फिर भी भाजपा को पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन, यदि एक छात्र अफजल गुरु के बारे में ऐसी बात बोलता है, तो उसे गिरफ्तार करके उसके साथ बदसलूकी की जाती है. यह किस तरह का तर्क है? क्या आप सोचते हैं कि भारत के लोग अंधे और बहरे हैं? ऐसा नहीं है. हर कोई देख रहा है, सबको सच पता है. जितनी जल्दी सरकार अपनी यह ग़लती सुधार ले, उतना ही बेहतर है. मैं आशा करता हूं कि न्याय पालिका कन्हैया को जल्द से जल्द रिहा करेगी. और, इस पूरे प्रकरण को शीघ्र भुला देना चाहिए. सरकार को बाकी बचे कार्यकाल में छात्रों को डील करते समय सावधान रहना चाहिए.

रोहित वेमुला का मामला जातिवाद का निम्नतम उदाहरण है. संबंधित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए. यह बहुत दु:खद मामला है. रोहित दुनिया में नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है. लेकिन, भविष्य में ऐसे मुद्दों से निपटने में सावधानी बरती जानी चाहिए. अंबेडकर के बारे में बात करना ठीक है. भाजपा अब अंबेडकर के बारे में बात कर रही है. ठीक है, यह वोट बैंक की राजनीति है. लेकिन, दलित इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं और वे भाजपा को वोट देने नहीं जा रहे. अभी संसद का सत्र चल रहा है. कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

जानदार कवर स्टोरी

कवर स्टोरी-वित्त मंत्री जी, कुछ तो गड़बड़ है (22-28 फरवरी, 2016) पढ़ी. कमल मोरारका जी ने विषय को बहुत ज़ोरदार ढंग से उठाया. तथ्यात्मक जानकारियों ने स्टोरी को जानदार बनाने का काम किया. एनपीए को लेकर किया गया विश्लेषण बताता है कि स्थिति काफी गंभीर है. देश का पैसा किस तरह कॉरपोरेट्स द्वारा हजम किया जा रहा है, यह भी बखूबी समझ में आया. सरकार को इस संबंध में कठोर क़दम उठाने चाहिए.

-शैलेंद्र शर्मा, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

आशंका निर्मूल नहीं

आलेख-भारतीय अर्थव्यवस्था: शोर बनाम सच्चाई (22-28 फरवरी, 2016) के अंतर्गत विशाल एसएन ने सही कहा कि नई-नई योजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं, ज़ोर-शोर से निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में घूम-घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है. एक तरफ़ बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ़ स्टार्टअप इंडिया जैसी मुहिम शुरू की जा रही है. लेकिन, इतना सब कुछ होने के बावजूद अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्ति का भाव पैदा नहीं हो रहा. लेखक की आशंका ग़लत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह चौतरफ़ा माहौल बनाया जा रहा है, वह वाकई बूम है या फिर बैलून.

-संजीव यादव, *विदिशा, मध्य प्रदेश.*

वोटों के तलबगार

आलेख-सियासी पाखंड का कालखंड (22-28 फरवरी, 2016) में प्रभात रंजन दीन ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा तस्वीर सबके सामने रख दी है. और, यही सच भी है कि राजनीतिक दल कभी किसी के सगे नहीं होते. उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ वोटों से मतलब होता है, जिसके लिए वे कुछ भी कर गुज़रने पर आमादा रहते हैं. जातिवाद किसी भी सभ्य-प्रगतिशील समाज के लिए ज़हर के समान है, लेकिन राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने की होड़ में इस ज़हर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं.

-सत्येंद्र भारद्वाज, *शाहदरा, दिल्ली.*

चौथी दुनिया
वित्त मंत्री जी, कुछ तो गड़बड़ है

अपराधियों की पौ बारह

बिहार में क़ानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति वाकई गंभीर हो गई है. विधानसभा चुनाव से पहले जो आशंका ज़ाहिर की जा रही थी कि जंगलराज पार्ट-2 आने वाला है, वह सच साबित होती दिख रही है. पिछले दिनों कई राजनेताओं की सरेआम हत्या कर दी गई, कोई रंगदारी मांग रहा है, विधायक छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप में पकड़े जा रहे हैं. यह अच्छा संकेत नहीं है. नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि लगातार धूमिल हो रही है. सरोज सिंह की रिपोर्ट-अपराध पर नियंत्रण ज़रूरी है (22-28 फरवरी, 2016), बहुत कुछ बताती है. ज़रूरत इस बात की है कि अपराधी कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो. अन्यथा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अपने फ़ैसले पर जनता को अफ़सोस होने लगेगा.

-राजेश्वर पांडेय, *समस्तीपुर, बिहार.*

किसानों की बदहाली

आलेख-किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा (22-28 फरवरी, 2016) के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के विचार पढ़ने का अवसर मिला. निस्संदेह, किसानों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली छिपी है. लेकिन, अफ़सोस इस बात का है कि देश का किसान बदहाल है, उसकी खोज-ख़बर रखना सरकार ने छोड़ दिया है, जबकि देश की सवा अरब आबादी का पेट वही किसान भरता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती वही किसान देता है.

-प्रकाश सहरावत, *रोहतक, हरियाणा.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

नन्हे हाथों में बंदूक!

आलेख-हथियारबंद संघर्षों में बच्चों का इस्तेमाल (22-28 फरवरी, 2016) के अंतर्गत जावेद अनीस ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है. अफगानिस्तान, सीरिया, अंगोला, इराक, इजरायल, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड में हिंसक लड़ाइयों में बच्चों को बतौर सैनिक इस्तेमाल किया जा रहा है. जिन हाथों में किताब-कलम होनी चाहिए, वे खूनखराबे में जुटे हैं. आलेख बताता है कि ऐसे बच्चों की संख्या तक़रीबन ढाई लाख है, जिनमें एक तिहाई लड़कियां हैं. आतंकी संगठनों ने इन बच्चों के हाथों में अत्याधुनिक एवं घातक हथियार थमा रखे हैं. यह निस्संदेह चिंतनीय है.

-रणधीर मीणा, *जोधपुर, राजस्थान.*

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

किसानों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए

> एक आतंकवादी के फर्ज़ी ट्विटर एकाउंट से की गई टिप्पणी देश के गृहमंत्री को परेशान कर देती है और वह उसे लेकर आरोप लगा देते हैं. लेकिन, किसानों की आत्महत्या न गृहमंत्री को परेशान करती है, न प्रधानमंत्री को और न नेता विपक्ष को. इसका मतलब यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों को यह संदेश भेज रहा है कि तुम्हारे किसी सवाल को हम न सुनना चाहते हैं, न तुम्हारी समस्याओं की तरफ़ नज़र डालना चाहते हैं.

मैं जानता हूं कि सरकार के कान में अख़बारों की लिखी बातें नहीं पहुंचतीं. जो निर्णय लेने वाले सज्जन हैं, वे टेलीविजन देखते हैं और खासकर उन चैनलों को देखते हैं, जो उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं या उनके विरोधियों के ऊपर हमले करते हैं. हम जैसे अख़बार वाले पत्रकारिता की ज़िम्मेदारी निभाते हैं और यह मानकर चलते हैं कि शायद सरकार में शामिल या सरकार का अधूरा हिस्सा रहे विपक्ष में शामिल लोगों की नज़र पड़ जाए और उन्हें उन तकलीफों का पता चल सके, जो देश के लोग उठा रहे हैं.

मैं जब तकलीफों की बात करता हूं, तो जीवन की तकलीफों की बात करता हूं. इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 60 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है. देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है. जो लोग खेती करते हैं या खेतिहर मज़दूर हैं, अगर उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी होगी, तो फिर उपज धीरे-धीरे कम होती जाएगी. और, अब देश में यही होता दिखाई दे रहा है. लोग धीरे-धीरे खेती के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं और खेती छोड़ने की योजना बना रहे हैं. शायद खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को यह अंदाज़ा हो गया है कि सरकारें उनकी नहीं सुनेंगी. पिछले 15 वर्षों में खेती अर्थव्यवस्था से बिल्कुल बाहर रही और अभी भी वह अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर है. इसीलिए संसद, सरकार या विपक्ष को कभी भी किसानों की आत्महत्या को लेकर चिंता नहीं हुई. किसानों की आत्महत्या के मामले अगर दो, चार या दस होते, तो भी उन्हें अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन किसानों की आत्महत्या की दर दिनोंदिन बढ़ रही है और सरकारी आंकड़े इसकी गवाही चीख-चीख कर दे रहे हैं. लेकिन, फिर भी व्यवस्था खामोश है. ऐसी असंवेदन संसद और संवेदनहीन राजनीति कभी नहीं देखी गई. क्या हमारी सरकार, हमारी संसद और हमारे विपक्ष की मंशा यह है कि जिस तरह जाटों ने उग्र आंदोलन किया, संपत्तियां तहस-नहस कर जनजीवन पंगु बना दिया और अपने हक़ में फ़ैसला करा लिया, उसी तरह का उदाहरण देश का किसान भी प्रस्तुत करे? धीरे-धीरे यही होने वाला है.

यह पूरा वर्ष अब आंदोलनों की भेंट चढ़ने वाला है. मुझे साफ़ दिखाई दे रहा है कि अगला वर्ष यानी 2017 किसानों के आंदोलन या उग्र आंदोलन का वर्ष होगा. अब तक किसानों ने कभी किसान होने के नाते अपनी समस्याओं को लेकर हुंकार नहीं भरी और न जनजीवन प्रभावित करने की कोशिश की. लेकिन, मेरे पास किसान संगठनों से जुड़े लोगों की जो आवाज़ें आ रही हैं, वे बताती हैं कि किसान अपने जीवन को लेकर निराशा की चरम सीमा की तरफ़ बढ़ रहे हैं. और, यह बात राजनेताओं को बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और उन्हें भी समझने में हिचक नहीं होनी

> लोग धीरे-धीरे खेती के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं और खेती छोड़ने की योजना बना रहे हैं. शायद खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को यह अंदाज़ा हो गया है कि सरकारें उनकी नहीं सुनेंगी. पिछले 15 वर्षों में खेती अर्थव्यवस्था से बिल्कुल बाहर रही और अभी भी वह अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर है. इसीलिए संसद, सरकार या विपक्ष को कभी भी किसानों की आत्महत्या को लेकर चिंता नहीं हुई. किसानों की आत्महत्या के मामले अगर दो, चार या दस होते, तो भी उन्हें अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन किसानों की आत्महत्या की दर दिनोंदिन बढ़ रही है और सरकारी आंकड़े इसकी गवाही चीख-चीख कर दे रहे हैं. लेकिन, फिर भी व्यवस्था खामोश है. ऐसी असंवेदन संसद और संवेदनहीन राजनीति कभी नहीं देखी गई.

चाहिए कि जब निराशा चरम सीमा पर पहुंचती है, तो हिंसा पैदा होती है. जब लोग सड़क पर आते हैं, खासकर खेती से जुड़े लोग, तब आप पुलिस और फौज तो लगा सकते हैं, लेकिन उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते.

इसलिए समय रहते सरकार और विपक्ष यानी संसद से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप कृपा करके किसानों की समस्याएं सामने रखकर उनसे बातचीत करें. देश की आर्थिक नीति किसानों को सामने रखकर बनाएं और उनकी आत्महत्या को उसका प्रारंभिक बिंदु मानें. किसानों की आत्महत्या किसानों के भीतर भयावह चित्र खींच रही है. संसद में देशद्रोह और देशप्रेम का सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सांसद, वह चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, यह नहीं कह रहा कि किसानों की आत्महत्या के ऊपर सवाल न उठाना या किसानों की आत्महत्या से चिंतित न होना या किसानों की आत्महत्या के कारणों को दूर न करना देशद्रोह का सर्वोत्तम उदाहरण है. और, इस अर्थ में हम मानें, तो वे सारे लोग, जो नकली देशप्रेम और नकली देशद्रोह का सवाल उठाते हैं, सीधे-सीधे देशद्रोह की परिधि में खड़े हो जाते हैं.

एक आतंकवादी के फर्ज़ी ट्विटर एकाउंट से की गई टिप्पणी देश के गृहमंत्री को परेशान कर देती है और वह उसे लेकर आरोप लगा देते हैं. लेकिन, किसानों की आत्महत्या न गृहमंत्री को परेशान करती है, न प्रधानमंत्री को और न नेता विपक्ष को. इसका मतलब यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों को यह संदेश भेज रहा है कि तुम्हारे किसी सवाल को हम न सुनना चाहते हैं, न तुम्हारी समस्याओं की तरफ़ नज़र डालना चाहते हैं. हमारे सामने आर्थिक विकास का वह नक्शा है, जिसमें देश के 60-70 प्रतिशत हिस्से के लिए कोई जगह नहीं है. अब सवाल है कि किसान क्या करें? इसका एक ही जवाब है कि न तो किसानों का कोई संगठन है और न कोई नेता. और, जब ऐसे आंदोलन होते हैं, जिनका न कोई संगठन होता है और न कोई नेता, तो वह हिंसक होता है और टूट-फूट वाला होता है.

मेरी सरकार से विनती है कि वह देश के ब्लॉकों को केंद्र बनाकर, किसान की उपज को प्रमुख कच्चा माल मानकर, गांव में रहने वालों को वहीं पर आजीविका कैसे मिले, इसकी योजना बनाए और ग्रामीण नौजवानों को उनके गांव के पास स्थित उद्योग-धंधों में शामिल करे. विकास का यह मॉडल देश को खड़ा कर सकता है. लेकिन, जब यह मॉडल देश के नीति निर्धारकों या नौकरशाहों को समझ में आए, तब तो कोई बात बनेगी! या फिर हो सकता है कि वे किसी उग्र आंदोलन का इंतज़ार कर रहे हों और सोच रहे हों कि जब आंदोलन होगा, तब हम कोई हल निकालेंगे. लेकिन, वह स्थिति शायद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

जेएनयू प्रकरण

भाजपा का सेल्फ-गोल

लॉर्ड पीटर मेंडलसन ने लेबर पार्टी के सदस्यों को पार्टी से संबंधित प्रतिकूल ख़बरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया था. इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, उसे एक्सकैलिबर नाम दिया गया था. एक्सकैलिबर इंग्लैंड के राजा किंग ऑर्थर की तलवार का नाम था. इसके चलते एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई, जिसने पार्टी को पुनर्निर्वाचित और मीडिया के क़रीब होने का मौक़ा दिया. जिस तरह हर सप्ताह भाजपा कार्यकर्ताओं या बाहरी लोगों द्वारा एक छोटी-सी घटना को उलझा कर और बड़ा करके पार्टी की किरकिरी कराई जाती है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा को भी एक्सकैलिबर जैसे किसी उपाय की आवश्यकता है. हर मामले पर प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करें, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब तक कोई प्रभावशाली अधिकारी अथवा शख्स किसी मामले को अपने हाथ में लेता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है. चूंकि आरएसएस सेना जैसे अनुशासन का दावा करता रहा है, इसलिए भाजपा को एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन उसके विभिन्न घटक जैसे सांसद-विधायक, नेता-कार्यकर्ता, समर्थक एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि मिलकर पार्टी की परेशानी बढ़ा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि पार्टी पर किसी का नियंत्रण नहीं है. अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जान-बूझ कर यह अव्यवस्था फैलाई जा रही है.

जेएनयू प्रकरण का जो भी नतीजा निकले, भाजपा को उसका लाभ नहीं मिलेगा. एक पल के लिए यह ज़रूर महसूस हुआ कि जेएनयू को बेनकाब करने का पार्टी का पुराना सपना पूरा हो गया. जेएनयू भाजपा के सबसे कम पसंदीदा विश्वविद्यालयों में से है, जिसके बारे में वह सोचती है कि वहां अभारतीय और भारत विरोधी वामपंथियों की भीड़ रहती है. लेकिन, अगले ही पल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अत्यधिक सक्रियता दिखाते हुए (जैसा कि उसने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था) जेएनयू प्रकरण को राष्ट्रद्रोह का मामला बताना शुरू कर दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस, जिसका मुक़ाबला की-स्टोन कॉप्स (एक हास्य फिल्म) से है, ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था. उसके बाद कैबिनेट मंत्री झंडे लहराने लगे और एक छोटे-से मामले को राष्ट्रीय संकट का रूप देने लगे. छात्र विद्रोह आम बात है और लोकतंत्र के लिए यह एक स्वस्थ परंपरा है. अमेरिका के विश्वविद्यालय परिसरों में वियतनाम युद्ध के ख़िलाफ़ 1965 के बाद दस वर्षों तक प्रदर्शन होते रहे, बावजूद इसके किसी पर राजद्रोह का मुक़दमा नहीं चला. विभिन्न पार्टियों के बीच गहन वाद-विवाद हुए, लेकिन किसी ने भी अदालत का सहारा नहीं लिया. 1968 के पेरिस छात्र आंदोलन ने फ्रांस में सरकार बदलने में अहम भूमिका निभाई. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरे अध्यनन के दौरान छात्रों के कई विद्रोह देखने को मिले, जिनमें से अधिकतर सरकार के विरुद्ध थे. नौजवानों-छात्रों से लोग विद्रोह की अपेक्षा रखते हैं.

अगर छात्र कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी का नारा लगते हैं, तब भी यह वास्तविक रूप से असंभव है. कश्मीर में भाजपा की सहयोगी पार्टी पीडीपी अफ़ज़ल गुरु से हमदर्दी रखती है और अलगाववादियों के प्रति बहुत सख्त नहीं है. दरअसल, कश्मीर एक ऐसी असंगति (एनोमली) है, जो भारत का अभिन्न अंग है और नहीं भी. अगर ऐसा न होता, तो कश्मीर के अलगाववादी भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त से कैसे मुलाकात कर पाते? कश्मीर

के सवाल पर लोगों के अलग-अलग और दृढ़ नज़रिये हैं. अगर ऐसा न होता, तो भाजपा इतने लंबे समय से आर्टिकल 370 की बात न करती. यूपीए ने वार्ताकारों की एक टीम कश्मीर भेजी थी. क्या वह भारत के किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसी टीम भेज सकता था? देश के किस कोने में प्रधानमंत्री के दौरे के समय मोबाइल बंद कर दिए जाते हैं?

> जेएनयू प्रकरण का जो भी नतीजा निकले, भाजपा को उसका लाभ नहीं मिलेगा. एक पल के लिए यह ज़रूर महसूस हुआ कि जेएनयू को बेनक़ाब करने का पार्टी का पुराना सपना पूरा हो गया. जेएनयू भाजपा के सबसे कम पसंदीदा विश्वविद्यालयों में से है, जिसके बारे में वह सोचती है कि वहां अभारतीय और भारत विरोधी वामपंथियों की भीड़ रहती है. लेकिन, अगले ही पल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अत्यधिक सक्रियता दिखाते हुए (जैसा कि उसने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था) जेएनयू प्रकरण को राष्ट्रद्रोह का मामला बताना शुरू कर दिया.

भाजपा के सुपर देशभक्तों के लिए यह दिखावा आसान है कि कश्मीर को लेकर नारे लगाना भी देशद्रोह है. लेकिन, सत्तारूढ़ दल खुद से असहमत होने वालों के प्रति दरियादिली दिखाए, न कि उनके मामूली उकसावे पर भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुस्से के दबाव में आने का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने जो भी ख्याति अर्जित की थी, वह खो गई. बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा. दरअसल, यह भाजपा का एक सेल्फ-गोल था. ■

feedback@chauthiduniya.com

लालू के सत्ता में लौटते ही फुलवरिया में लौटी खुशहाली

लालू प्रसाद के भतीजा रामानंद यादव कहते हैं कि साहेब जब सत्ता में थे तो फुलवरिया को दुल्हन की तरह सजा कर रखा जाता था. लेकिन उनके सत्ता से हटते ही रेलवे स्टेशन क्या फुलवरिया गांव का विकास ठप पड़ गया था. लेकिन उनके सत्ता में आते ही फिर से फुलवरिया में विकास की किरणें जगमगाने लगी हैं. टूटी सड़कें बनने लगी हैं, तेज प्रताप के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही अस्पताल में दवा आना भी शुरू हो गई है, समय से डॉक्टर आने लगे हैं

अखिलेश मिश्र feedback@chauthiduniya.com

गोपालगंज का फुलवरिया गांव उस समय चर्चा में आया जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर लालू प्रसाद आसीन हुए. मूलभूत सुविधाओं से महरूम फुलवरिया गांव के लोग आज अपने आपको खुशकिस्मत मानते हैं कि जिस गांव में जाने के लिए मात्र पगडंडी सड़कें थीं, वहीं गांव भी शहर कि तरह जगमगाने लगा. चौड़ी सड़कें, बड़ी-बड़ी इमारतें यह बताने के लिए तैयार हैं कि यह गांव लालू प्रसाद का है. 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए लालू प्रसाद ने फुलवरिया को सड़क, बिजली, डाकघर, बैंक, अस्पताल, निबंधन कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, थाना, मंदिर, स्कूल, हैलीपैड और रेलवे स्टेशन दिया. गांव के लोगों को लालू प्रसाद पर गर्व है. फुलवरिया गांव में 11 जून 1948 में जन्मे लालू प्रसाद का पुश्तैनी घर आज भी है, वहां मां मरझिया देवी की प्रतिमा लगी हुई है. लालू प्रसाद ने फुलवरिया के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. फुलवरिया को प्रखण्ड का दर्जा दिलाकर यहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए गए. विभिन्न सरकारी कार्यालय होने के चलते अपने कार्य निष्पादन कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है. फुलवरिया गांव में दुकानें खुल गईं, बाजार लगने लगा. फुलवरिया निवासी उपेन्द्र

यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद के बिना फुलवरिया गांव के लोगों का जीवन अधूरा है. लालू की देन है कि हमारा गांव एक आधुनिक गांव बन गया. उनके कारण ही फुलवरिया गांव के 50 से अधिक युवक रेलवे में नौकरी कर रहे हैं. फिर भी इस गांव से बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रांतों में नौकरी करते हैं. गांव के सुदामा यादव कहते हैं कि लालू ने हमें नाम और प्रसिद्धि सहित सब कुछ दे दिया है. लालू प्रसाद के भतीजा रामानंद यादव कहते हैं कि साहेब जब सत्ता में थे तो फुलवरिया को दुल्हन की तरह सजा कर रखा जाता था. लेकिन उनके सत्ता से हटते ही रेलवे स्टेशन क्या फुलवरिया गांव का विकास ठप पड़ गया था. लेकिन उनके सत्ता में आते ही फिर फुलवरिया में विकास की किरणें जगमगाने लगी हैं. टूटी सड़कें बनने लगी हैं, तेज प्रताप के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही अस्पताल में दवा आना भी शुरू हो गई हैं, समय से डॉक्टर आने लगे हैं. अब यहां अधिकारियों का आना-जाना शुरू हो गया है. महागठबंधन के सरकार में किंग मेकर के रूप में उभरे लालू प्रसाद का दबदबा आज भी गोपालगंज में चलता है. डीएम से लेकर थानेदार तक की पोस्टिंग उनकी मर्जी से गोपालगंज में होती है. तेजस्वी और तेजप्रताप के पास अच्छे मंत्री पद होने से नेताओं का भी जमघट उनके पास लगा रहता है. हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप अपने गांव फुलवरिया आए थे. जहां अधिकारियों और नेताओं का जमघट लगा रहा. गांव के लोग अब खुश हैं कि फिर से लालू प्रसाद की सत्ता लौट आई, इसी के साथ गांव के लोगों का भी विकास होगा. लालू प्रसाद के जीवनी पर प्रकाश डाला जाए तो एक साधारण परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव की राजनीति में प्रवेश भारतीय राजनीति में पहला कदम एक छात्र के रूप में हुआ था. उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा. लालू प्रसाद की शादी 1 जून 1973 को राबड़ी देवी के साथ हुई थी. लालू प्रसाद का राजनीतिक क्षेत्र गोपालगंज नहीं रहा, लेकिन उनका लगाव अपने गांव से हमेशा रहा. वह सारण निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए. 1980 से 1989 तक लगातार दो बार वह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे. 1983 में वह विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए. वह बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 1990 से 1997 तक रहते हुए फुलवरिया का सरकारी योजनओं के जरिए विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे, लालू प्रसाद ने हथुआ से बथुआ तक बड़ी रेल लाईन परियोजना का चयन कर दो साल में रेल खंड पर सवारी गाड़ी चला दी. लालू प्रसाद ने रेल मंत्री के रूप में 2008 में एक रेलवे लिंक के साथ अपनी पत्नी राबड़ी देवी के गांव सेलारकला को भी रेलवे लिंक से जोड़ दिया. उस समय फुलवरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. लालूप्रसाद के सत्ता से हटते ही जिस प्रकार उनको छोड़ दूसरे का दामन थाम लिया. उसी प्रकार फुलवारिया के विकास के प्रति नेताओं और अधिकारियों का रुझान ख़त्म हो गया था.■

बिहार के लिए उम्मीदों वाला रेल बजट

इस रेल बजट में 1,601 करोड़ रुपये की लागत से विक्रमशिला से कटोरिया तक नई रेल लाइन का निर्माण करने के साथ- साथ 227 करोड़ रुपये से मानसी-सहरसा-दौरम, मधेपुरा-सहरसा-कटिहार के बीच 172 किलो मीटर की नई रेल लाइन का निर्माण करने की घोषणा की गई है. इसी तरह 131 करोड़ रुपये की लागत से करौटा पतनेर मनकट्ठा सर्फेस तिहरी लाइन के निर्माण का भी फैसला किया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

रेल बजट के आने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह कर एक राजनीतिक बहस छेड़ दी थी कि मुझे रेल बजट से कोई उम्मीद नहीं है. चूंकि नीतीश कुमार रेल मंत्री भी रह चुके हैं इसलिए यह बहस कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई, लेकिन सुरेश प्रभु ने बिहार को रेल बजट में 3,171 करोड़ की सौगात देकर सारे कयासों का पटाक्षेप कर दिया. इसके बाद एनडीए के नेता कहने लगे कि नीतीश कुमार को बजट से पहले ही इस तरह की निराशा भरी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जदयू और राजद के नेताओं का अब भी मानना है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और रेल बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं है. खैर राजनीतिक बयानवाजी को अगर दरकिनार करके देखें तो सुरेश प्रभु के बजट से ऐसा नहीं लगता है कि बिहारवासियों को बहुत निराश होने की जरूरत है. बिहार के लिए जो बड़ी बात हुई है वह यह है कि सूबे की लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं के पूरा होने का रास्ता बजट में साफ हो गया है. मढ़ौरा और मधेपुरा में इंजन कारखाना के निर्माण में आने वाली सारी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है और इसके लिए टेंडर अवॉर्ड करने की घोषणा भी रेल मंत्री ने कर दी है. बिहार में चूंकि रेलवे में आधारभूत संरचना का समुचित विकास नहीं हो पाया है. इसलिए सुरेश प्रभु ने बजट में इस ओर काफी जोर दिया है.

इस रेल बजट में 1,601 करोड़ रुपये की लागत से विक्रमशिला से कटोरिया तक नई रेल लाइन का निर्माण करने के साथ ही साथ 227 करोड़ रुपये से मानसी-सहरसा-दौरम, मधेपुरा-सहरसा-कटिहार के बीच 172 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण करने की घोषणा की गई है. इसी तरह 131 करोड़ की लागत से करौटा पतनेर मनकट्ठा सर्फेस तिहरी लाइन के निर्माण का भी फैसला किया गया है. बिहार में यात्री सुविधाओं के लिए 51 करोड़ रुपये व यातायात सुविधा के लिए 39 करोड़ रुपये की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है. रेल बजट में सुगौली से वाल्मीकि नगर तक 744 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 10 किमी लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी राशि आवंटित की गई है. बिहार की लंबी मांग को पूरा करते हुए सुरेश प्रभु ने 700 करोड़ की लागत से 787 किमी लंबे रेलखंड के विद्युतीकरण का फैसला किया है. इसके अलावा 245 किमी सिंगल लाइन के दोहरीकरण की घोषणा भी बजट में की गई है. उत्तर बिहार के लोगों को अधिक सुविधा देने के लिए मोकामा में वर्तमान रेल पुल के सामानांतर एक और दोहरी रेल लाइन पुल बनाने की घोषणा बजट में की गई है. गया से मानपुर तक अलग से बाइपास रेल लाइन बनाने का फैसला भी बजट में किया गया है. इससे लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी. चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटन किया गया है. राजगीर तिलैया एवं नटेसर इस्लामपुर रेल लाइन के लिए 75 करोड़, बिहारशरीफ बरबीधा-शेखपुरा रेललाइन के लिए 176 करोड़ रुपये, हाजीपुर-सुगौली के लिए 100 करोड़ रुपये और छपरा-मुजफ्फरपुर के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

इस बजट से बिहार के लिए उम्मीद जगती है. लेकिन हमेशा की तरह रेल बजट को पक्ष-विपक्ष के नजरिए से देखा जा रहा है, नेताओं की प्रतिक्रिया भी बजट को लेकर कुछ इसी तरह की है. नीतीश कुमार कहते हैं कि रेलबजट में सुरेश प्रभु ने मुसाफिरों के साथ भद्दा मजाक किया है. नीतीश कुमार का कहना है कि हाई स्पीड गाड़ियों का कोई मतलब नहीं है. नीतीश कुमार का कहना है कि सबसे पहले रेल का ढांचा बदलना होगा तभी इन टेनों का मतलब है अन्यथा यह सब दिखावे वाली बात है.

कुल मिलाकर इस बजट से बिहार के लिए उम्मीद जगती है. लेकिन हमेशा की तरह रेल बजट को पक्ष-विपक्ष के नजरिए से देखा जा रहा है, नेताओं की प्रतिक्रिया भी बजट को लेकर कुछ इसी तरह की है. नीतीश कुमार कहते हैं कि रेलबजट में सुरेश प्रभु ने मुसाफिरों के साथ भद्दा मजाक किया है. नीतीश कुमार का कहना है कि हाई स्पीड गाड़ियों का कोई मतलब नहीं है. नीतीश कुमार का कहना है कि सबसे पहले रेल का ढांचा बदलना होगा तभी इन ट्रेनों का मतलब है अन्यथा यह सब दिखावे वाली बात है. नीतीश कुमार कहते हैं कि पिछले बजट से ही साफ-सफाई और यात्री-सुविधाओं की बातें हो रही हैं पर हक़ीकत क्या है इसे सब जानते हैं. इस बजट में भी इस संबंध में लंबी चौड़ी बातें कहीं गईं हैं पर जमीनी स्तर पर होना कुछ नहीं है. इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी रेलबजट को बेहद निराशाजनक बताया है. उनके बेटे और सूबे के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि अंत्योदय, हमसफर , तेजस और आस्था एक्सप्रेस की घोषणा तो कर दी गई है पर ये कहां से कहां तक चलेगी इस बारे में नहीं बताया गया है. लेकिन प्रदेश के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं कि इस बजट में बिहार को उम्मीद से ज्यादा मिला है. मार्च तक मुंगेर रेल पुल के चालू होने की बात कही गई है. इसके अलावा बिहार की लंबित योजनाओं के लिए भी बजटीय आवंटन किया गया है. मढ़ौरा और मधेपुरा के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है. नीतीश कुमार के बयान पर मोदी कहते हैं कि उन्हें हर बात में निराशा ही नज़र आ रही है. लगता है उनपर लालू प्रसाद का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है. बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार रात-दिन खड़ी है पर यह बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि वह केंद्र से किस तरह मदद लेती है. यदि उसकी हर काम में अड़चन डालने की प्रवृति बनी रहेगी तो विकास कैसे होगा? केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि यह बेहतरीन रेल बजट है और जिस तरह बिहार को इसमें केंद्र में रखा गया है. उससे यह साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लिए कितनी फिक्रमंद है. बयानों से बाहर निकलें तो कहा जा सकता है कि बिहार के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं पर इतना कुछ बजट में तो दिया ही गया है कि सूबे को निराश होने की जरूरत नहीं है. जरूरत इस बात की है कि जो घोषणाएं हुई हैं उनपर काम शुरू हो और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नज़र होनी चाहिए ताकि बिहार के लोंगों को कुछ सहूलियत हो सके.■

गया पुल एक, उद्घाटन दो बार

सुनील सौरभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार के पहले सिक्स लेन पुल के निर्माण की महत्वकांक्षी परियोजना पूरी हो गई, लेकिन इसके उद्घाटन पर खूब राजनीति हुई. एक पुल का दो बार उद्घाटन किए जाने के मामले को विरोधी दलों ने भी खूब उछाला. मगध की जीवन रेखा मानी जाने वाली फल्गु नदी पर बने सिक्स लेन पुल के एक लेन का उद्घाटन विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से रिमोट द्वारा किया था. वहीं दूसरी बार उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पुल के दूसरे लेन का उद्घाटन किया है.

इस पुल के दोनों उद्घाटन समारोह विवादों में रहे. 15 जुलाई, 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पटना से रिमोट के द्वारा पुल के एक लेन का उद्घाटन किया था. तब क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मानपुर की ओर से तथा दूसरे छोर से गया शहर के विधायक प्रेम कुमार ने जबरन फीता काटकर पुल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यह पुल केंद्र सरकार की राशि से बना है इसलिए इसका उद्घाटन करने का हक़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है. 18 फरवरी, 2016 को इस पुल के दूसरे लेन का निर्माण कार्य पूरा होने पर उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका उद्घाटन किया तो प्रतिपक्ष के नेता और गया शहर के विधायक प्रेम कुमार यह कहते हुए धरने पर बैठ गए कि उद्घाटन समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है. समारोह में क्षेत्रीय सांसद और विधायक को निमत्रंण नहीं दिया गया है. लेकिन प्रेम कुमार के धरने पर बैठने का कोई असर उद्घाटन समारोह पर नहीं पड़ा और न ही पुल निर्माण निगम के पदाधिकारियों ने इसे नोटिस में लिया.

प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र की राशि से निर्मित योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में एनडीए के नेताओं की उपेक्षा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा की जा रही है. यहां तक कि गया नगर निगम की मेयर सोनी कुमारी को भी उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था. नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ़, नवादा, शेखपुरा, जमुई, खिजरसराय तथा मानपुर सहित पूर्वी क्षेत्रों को गया शहर से जोड़ने वाले इस सिक्स लेन पुल के निर्माण पर लगभग 65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. पुल की लबांई 550 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है. हालांकि फल्गु नदी परइस पुल का निर्माण तो हो गया लेकिन मानपुर तथा गया शहर छोर पर एप्रोच सड़क का निर्माण नहीं होने से दोनों ओर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है. इस मामले को उद्घाटन समारोह में प्रदेश के पशुपालन मंत्री एवं वजीरगंज के विधायक अवधेश कुमार सिंह ने उठाया था. तब उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि पुल के दोनों ओर एप्रोच सड़क भी सिक्स लेन की बनाई जाएगी, जिससे कि लोगों के आवागमन में कोई परेशानी न हो. इस पुल का निर्माण शुरू से ही विवादों में रहा है. निर्माण कार्य के दौरान करीब दो करोड़ की लागत से बने डायवर्सन के तुरंत टूट जाने पर भी लोगों ने इस पुल के निर्माण कार्य का ठेका लेने वाली कंपनी पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा था कि पुल का निर्माण गुणवत्ता के अनुसार नहीं होगा. स्पैन एंव स्लैव निर्माण के दौरान भी इस ठेका कंपनी पर सवाल उठाया गया था कि थोड़ी सी बचत के लिए कंपनी गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है. तब राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता तथा इस पुल निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने-अपने हिसाब से सफाई दी थी. गया शहर के विधायक और प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार के पहले सिक्स लेन पुल के उद्घाटन समारोह में प्रोटोकॉल का जिस तरह उल्लंघन किया गया है उसे विधानसभा में उठाएंगे. वहीं दूसरी ओर गया नगर निगम की मेयर सोनी कुमारी पुल के उद्घाटन समारोह में मेयर को आमंत्रित नहीं करने को गया शहर का अपमान बताया.■

feedback@chauthiduniya.com

आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15

बिहार सबसे आगे

चौथी दुनिया ब्यूरो

विकास की रफ्तार के मामले में बिहार लगातार 10वें वर्ष देश के दूसरे प्रमुख राज्यों से आगे बना हुआ है. वित्त वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 10.52 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है. यह देश के अन्य सभी प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है. बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 पेश किया. राज्य में महा-गठबंधन सरकार के गठन और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद पेश हुए राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच विकास दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, बावजूद इसके बिहार की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्ति में 9,499 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं, राजस्व व्यय इस वर्ष बढ़कर 72,570 करोड़ रुपये हो गया है. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2005-06 से 2014-15 के दरम्यान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही है. यह वृद्धि दर राज्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि राज्य की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है.

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पटना प्रदेश का सबसे धनवान जिला है. बावजूद इसके पटना और गोवा के निवासियों के बीच की प्रति व्यक्ति आय में 20 हजार रुपये का अंतर है. हालांकि, साल 2012-13 के मुक़ाबले साल 2014-15 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के 37 प्रतिशत से बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गई है. पिछले साल बिहार में पूंजीगत निवेश में भी भारी वृद्धि हुई है. पूंजीगत निवेश बढ़कर 8,954 करोड़ रुपये हो गया है. इस वजह से राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 के 3970 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में 11,178 करोड़ रुपये हो गया है. लेकिन अभी भी यह फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट द्वारा तय सीमा तीन फीसदी से कम है. सरकार इसे अलार्मिंग नहीं मानती है. सर्वे में कहा गया है कि बिहार को 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कर विभाजन से अगले पांच सालों में तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा. टैक्स विभाजन में बिहार का हिस्सा 10.917 प्रतिशत से घटकर 9.665 प्रतिशत हो गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य बिंदु

- 10 सालों में विकास दर- 10.52 प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय औसत का 40.6 प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अब भी 59.4 प्रतिशत कम
- पूंजीगत निवेश में वृद्धि 8,954 करोड़
- कृषि में छह फीसदी से अधिक की वृद्धि
- गत वर्ष की तुलना में 9, 499 रुपये अधिक राजस्व प्राप्ति
- राजकोषीय घाटा तीन फीसदी से कम

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पटना प्रदेश का सबसे धनवान जिला है. बावजूद इसके पटना और गोवा के निवासियों के बीच की प्रति व्यक्ति आय में 20 हजार रुपये का अंतर है. हालांकि, साल 2012-13 के मुक़ाबले साल 2014-15 में बिहार में प्रति व्यवित आय राष्ट्रीय औसत के 37 प्रतिशत से बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गई है. पिछले साल बिहार में पूंजीगत निवेश में भी भारी वृद्धि हुई है.

जुमला बनते चुनावी वादे

राकेश कुमार

भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर किए गए नेताओं के वायदे महज जुमले बनकर रह गए हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपा के कई नेताओं ने वादा किया था कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा. केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हुए तकरीबन दो साल का वक्त पूरा होने वाला है लेकिन सरकार ने अब तक भोजपुरी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है. उनका यह चुनावी वादा भी जुमला बनता दिखाई पड़ रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में 21 फरवरी, 2016 को भोजपुरी जन-जागरण अभियान के तत्वावधान में भोजपुरी को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना-प्रदर्शन किया गया. धरने में देश भर के भोजपुरी भाषी लोगों ने हिस्सा लिया. धरना-प्रदर्शन में बेतिया के भोजपुरी एवं हिंदी के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि गोरख मस्ताना अस्वस्थ होने के बावजूद उपस्थित थे. भोजपुरी फिल्मों की बदौलत नाम और पैसा कमाने वाले अभिनेताओं की चुप्पी पर भी धरने में आक्रोश व्यक्त किया गया. जंतर-मंतर से अपील की गई कि भोजपुरी फिल्मों से जुड़े कलाकार भी इस आंदोलन में सहयोग करें. इसके साथ भोजपुरी को बदनाम करने वाले भद्दे गानों और द्विअर्थी संवादों का विरोध करने का भी निर्णय यहां लिया गया. पिछले दिनों बिहार के मोतिहारी में ऐसी फिल्मों के पोस्टरों को हटाने की मुहिम भी चलाई गई थी.

गौरतलब हो कि पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 25 करोड़ से भी ज्यादा है. यह भाषा सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यो में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी तकरीबन बारह देशों में बोली जाती है. इतनी समृद्धशाली भाषा को देश के बाहर कई देशों में मान्यता मिली हुई है. लेकिन यह दुख की बात है कि भोजपुरी अपने ही देश में अपनों के बीच हक़ नहीं मिल पा रहा है.

भोजपुरी भाषा मान्यता आंदोलन के तत्वाधान में संचालित भोजपुरी जन-जागरण अभियान देश भर में चल रहा है. इसके अंतर्गत भोजपुरी साहित्य-संस्कृति को सहेजने का काम भी हो रहा है. पिछले साल दिसंबर में जब इसी विषय पर धरना किया था. तब भाजपा के कई सांसदों ने कहा था कि भोजपुरी भाषी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिलने की खुशी मनाएंगे. लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका है. धरने में निर्णय लिया गया कि सरकार बजट सत्र के दौरान सरकार भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने की पहल नहीं करती है तो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के सांसदों का घेराव किया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल होने केलाभ

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यकारी भाषा बन सकेगी.
- सांसद, विधायक शपथग्रहण और कार्यवाही भोजपुरी में कर सकेंगे.
- संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भोजपुरी में उत्तर दिया जा सकेगा.
- संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में साहित्य का विषय रखा जा सकेगा.
- भारत सरकार के गजट का प्रकाशन भोजपुरी में भी हो सकेगा.
- राज्य भाषा का दर्जा मिल सकेगा.
- रिजर्व बैंक द्धारा जारी एक हजार, पांच सौ के नोट पर भोजपुरी में मूल्य का मुद्रण हो सकेगा.
- मानव संसाधन विभाग द्धारा भाषा के विकास के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार को दे सकेगी.
- भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार भोजपुरी की रचनाओं को मिल सकेगा.
- संबंधित राज्यों में विशेष आयोजन में आमंत्रण पत्र व कार्यवाही भोजपुरी में की जा सकेगी.
- संबंधित राज्यों में शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है.
- भारतीय भाषा केंद्र मैसूर में अनुदान हेतु व शिक्षण हेतु भोजपुरी एक स्वीकृत भाषा बन सकेगी.

भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने में हो रही देरी की वजह से यह आंदोलन बड़ा होता जा रहा है. गांधी की कर्मभूमि चंपारण से दिल्ली के जंतर-मंतर तक इसके लिए धरना-प्रदर्शन व बैठकों का दौर तेज हो चला है.

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें । दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मै 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूं मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

लाइफ स्टाइल सुधारें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr. Rajeev Kr. Ranjan
SIWAN
(MS) GEN SURGERY

सिवान के राजलक्ष्मी सर्जीकेयर के डॉ. आर. के. रंजन ने अपने अनुभव शेयर किये उन्होंने बताया कि हमारे यहां ऑपरेशन कराने वाले मरीज आते हैं जिनको हर्निया, पित की थैली में पत्थर, अपेन्डिक्स, हाइड्रोसील, किडनी में स्टोन हो गया हो। किडनी में स्टोन होने पर उन्होंने बताया कि मरीज को जिस साइड स्टोन रहता है उस साइड पेट में दर्द होता है। बायें साइड रहता है तो बायें में और दायें साइड रहता है तो दायें साइड पेट में दर्द महसूस होता है। पेट दर्द की दवा आदि लेने पर दर्द बढ़ जाता है ठीक नहीं होता है। इस तरह के केस में मरीज को चाहिए कि तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। दर्द के साथ पेशाब में जलन भी महसूस होती है तथा जलन के साथ कभी कभी पेशाब के रास्ते में खून भी आता है। बार-बार पेशाब होना इसके लक्षण हैं। इस तरह के बीमारी में मरीज को बुखार भी आ सकता है। यदि आपको इन सब से निजात पाना है तो रोजमर्रा की जिन्दगी में पानी की मात्रा बढ़ा दें **दैनिक जीवन में भोजन से चार गुना ज्यादा पानी शरीर में डालें**। खानें में एक ही प्रकार की सब्जी का सेवन ज्यादा न करें। टमाटर, पालक, जंक फूड, बन्दा गोभी की अधिकता स्टोन का कारण हो सकती है। डॉ. आर.के. रंजन का कहना है कि किडनी स्टोन मरीज को 5से 8 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। पेसेन्ट को रोटी, चना, दाल आदि का सेवन करना चाहिए और पालक, टमाटर बन्दागोभी जैसी सब्जियों से परहेज करना चाहिए। समय रहते यदि कुशल चिकित्सक के पास पहुंच जायेंगे तो दवा से इलाज संभव है नहीं तो फिर ऑपरेशन द्वारा ही इलाज संभव है। ■ -भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

हर घड़ी प्रगति की नई ऊंचाईयों की ओर अग्रसर

उत्तर प्रदेश की नई पहचान

हाईटेक सिटी से होगा ट्रांस गंगा क्षेत्र का कायाकल्प

आज उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा हर दिन नई योजनाओं एवं परियोजनाओं की शुरूआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश को सबसे उन्नतिशील और खुशहाल प्रदेश बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है और अपनी इस प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा जनपद उन्नाव परियोजना ट्रांस गंगा (हाईटेक, क्लीन-ग्रीन सिटी) का शिलान्यास इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा एवं उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सके।

ट्रांस गंगा परियोजना में 350 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक एवं प्रदूषण मुक्त उद्योग स्थापित किए जाएंगे। आवासीय परियोजनाएं 150 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी तथा शेष में कॉमर्शियल संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल, स्टॉक एक्सचेन्ज सहित अन्य परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी।

इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्थापना में किसानों व अस्पतालों, कारखानों, हरियाली जोन आदि की सुनियोजित तरीके से स्थापना कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इस परियोजना में स्किल डेवलपमेन्ट डिजाइन यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस परियोजना से गांव व शहर का संतुलित विकास हो सकेगा। श्री यादव ने कहा कि ट्रांस गंगा सिटी में विकसित किए जाने वाले औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत क्षेत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का मानना है कि ट्रांस गंगा परियोजना से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को भी भरपूर लाभ होगा। इस परियोजना से उद्योग, आवास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश और भागीदारी के लिए आगे आएंगे।

उन्नाव के कन्हवापुर ग्राम के पास गंगा बैराज के निकट ट्रांस गंगा परियोजना का शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री यादव ने बताया कि इस परियोजना की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जा रही है। यह परियोजना 1156 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही है।

स्थानीय जनता के विशेष सहयोग के लिए उन्हें बधाई देते हुये कहा कि यह परियोजना एक निर्धारित पॉलिसी के तहत स्थापित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में नयी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति लागू की गयी है। इसके तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को

ट्रांस गंगा परियोजना से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय जनता को भी भरपूर लाभ होगा

प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाओं का प्राविधान किया गया है। श्री यादव ने कहा कि ट्रांस गंगा परियोजना में भी हाउसिंग स्कीमों, को एक दूसरे से हरित क्षेत्रों के माध्यम से पृथक रखा जायेगा।

सम्पूर्ण परियोजना को शून्य उत्प्रवाह के रूप में विकसित किया जायेगा। समाजवादी सरकार ने प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया है और गरीबों, पिछड़ो के उत्थान के लिए हरसम्भव कदम उठाये हैं। गंगा से सभी जाति धर्म के लोगों को फायदा मिलता है। सभी के खेतों की सिंचाई होती है। समाजवादी सरकार गंगा को धर्म से नहीं, बल्कि समाजवाद से जोड़ती है। प्रदेश सरकार जहां गॉव-गरीब के लिए काम कर रही है वहीं उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश का सन्तुलित विकास कर रही है।

इस परियोजना में तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र के साथ ही 6 अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी।

प्रदेश के विकास के तीन कदम

लखनऊ आई.टी. सिटी

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

मेदान्ता-अवध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

वैसे तो सभी प्रदेशों की सरकारें अपने राज्यों के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने तथा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए नई योजनायें लागू करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पिछले ढाई साल में उत्तर प्रदेश में इस दिशा में जो प्रयास किए गए वैसे प्रयास इतने बड़े पैमाने पर कहीं और नहीं किए गए। इसी क्रम में सरकार जहॉ एक ओर युवाओं के विकास के लिए लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) का शिलान्यास कर रही है, वहीं आई.टी. सिटी की स्थापना के साथ-साथ प्रदेश वासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को भी बढ़ावा दे रही है।

आई.टी. सिटी

एच.सी.एल. द्वारा विकसित की जाने वाली आई.टी. सिटी पर लगभग रूपये 1500 करोड़ का पूँजी निवेश अनुमानित है। 100 एकड; में सम्पूर्ण आई.टी. सिटी की स्थापना के निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर 25,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। आई.टी. सिटी में प्रत्येक रोजगार का कम-से-कम दो गुना अर्थात् लगभग 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार (सहायक स्टाफ, संविदात्मक स्टाफ) अनुषांगिक कार्यकलापों के माध्यम से सृजित होना संभावित है। माइलस्टोन-2 के दौरान कौशल विकास केन्द्र से उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या 5,000 होगी।

आई.आई.आई.टी.

इलाहाबाद में आई.आई.आई.टी. के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की 50 एकड़ भूमि पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा इण्डस्ट्री पार्टनर (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड) के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) लखनऊ की स्थापना का निर्णय लिया गया है,

ढ़ाई साल में पूरी होंगी योजनाएं

बड़ी संख्या में रोजगार के नये अवसर

बढ़ेगा उत्तर प्रदेश का महत्व

जिसमें प्रथम वर्ष 120, दूसरे वर्ष 180 तथा तीसरे वर्ष 300 सीटों का प्राविधान होगा।

मेदान्ता अवध

विश्व प्रसिद्ध डॉ. नरेश त्रेहन द्वारा लखनऊ में 12 एकड़ भूमि पर स्थापित 'मेदान्ता अवध' दुनिया की सबसे एडवांस्ड हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करता है। 1,000 बेडों की क्षमता वाले इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 30 ऑपरेटिंग कमरे, क्रिटिकल केयर के 300 बेड्स, यूनानी मेडिकल सेन्टर, आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास, हेल्थकेयर बीपीओ, बहुराष्ट्रीय हेल्थकेयर एवं दवा कम्पनियों के कार्यालय, सहायक एवं समर्थन सेवाएं, विश्वस्तरीय शिक्षा सुविधाएं, आवासीय परिसर एवं इन्टेलीजेंट हेल्थ केयर सिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सी.जी. सिटी चक गंजरिया में आई.टी. सिटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) तथा मेदान्ता-अवध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं से जहां बड़ी संख्या में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे, वहीं उत्तर प्रदेश का महत्व भी बढ़ेगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है ये अगले ढाई साल में बनकर तैयार हो जाएंगी और इनका लाभ जनता को मिलने लगेगा।

उत्तर प्रदेश को एक बड़ा प्रदेश है और जब तक यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के विकास के आँकड़े ठीक नहीं होंगे, तब तक देश की छवि ठीक नहीं बनेगी। प्रदेश सरकार इस तथ्य से भलीभॉति अवगत है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इतने कम समय में जितने फैसले लिए हैं उतने फैसले किसी अन्य राज्य की सरकारों ने नहीं लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

प्रदेश की आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक बनेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे

एक्सप्रेस वे या हाईवे किसी भी राष्ट्र की सुख, समृद्धि और सम्पन्नता का अभी तक प्रतीक माने जाते रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी एक दिन उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की ऐसी ही इबारत दर्ज कराएगा।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। हरे भरे लहलहाते खेतों के बीच से निकलता हुआ 302 किमी लंबा एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे भी है और देश में पहली बार ईपीपी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन) पद्धति पर तैयार किया जा रहा है। इसकी एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण की अवधि 36 माह निर्धारित की गई थी जबकि 24 महीनों में ही इसका निर्माण पूरा किया जा रहा है जो एक रिकार्ड होगा। ज्ञातव्य है कि 165 किलोमीटर लंबा नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की क्वालिटी में कोई कमी न रह जाए इसके लिए स्पेन की जानी मानी अथारिटी इंजीनियरिंग कंपनी 'आएशा' को इसकी गुणवत्ता को देखने परखने के लिए वैश्विक टेंडर के माध्यम से अधिकृत किया गया है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य किसी एक कंस्ट्रक्शन फर्म को न देकर पांच प्रतिष्ठित कंपनियों को दिया गया है ताकि प्रतिस्पर्धा के चलते इसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। इसी कारण इसके निर्माण को पांच पैकेज में विभाजित किया गया है। पहले पैकेज में आगरा से फिरोजाबाद तक का निर्माण कार्य पीएनसी इंफ्रा को दिया गया, दूसरे पैकेज में फिरोजाबाद से इटावा तथा चौथे पैकेज में कन्नौज से उन्नाव तक के निर्माण का कार्य एफ्कान्स इंफ्रा कंपनी को और तीसरे पैकेज का कार्य एनसीसी लिमिटेड को दिया गया एवं पांचवे पैकेज में उन्नाव से लखनऊ तक निर्माण कार्य एलएंडटी को दिया गया है।

माना जा रहा है कि यह पूरा एक्सप्रेस-वे टोल फ्री रहे और इस पर किसी तरह का

302 किमी. लम्बा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मात्र 24 महीनों के रिकार्ड समय मे होगा तैयार देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

टैक्स नहीं लगे क्योंकि इसके निर्माण में ही समाजवादी विचार धारा का ध्यान रखा गया है जिसके तहत किसानों से सीधे भूमि ली गई और उसका सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा अदा किया गया।

सरकार के इस फैसले का हर वर्ग ने स्वागत किया और किसानों में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं पनपा। गौरतलब है कि नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान भट्टा परसौल और पट्टल जैसी घटनाएं हुई और कई महीनों तक किसानों ने हिंसक संघर्ष किया था. इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान इसीलिए कोई कानूनी अड़चन भी नहीं हुई और निर्माण के शुरुआत के शुरु के सात महीनों में ही 99 प्रतिशत भूमि खरीद ली गई थी। केवल एक प्रतिशत भूमि ही इसके लिए अधिग्रहीत की गई।

इस एक्सप्रेस वे के लिए कुल 30 हजार किसानों से 3400 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई जिनमें से सिर्फ 15 किसानों ने भूमि क्रय की शर्तों से संतुष्ट न होते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने सरकार की भूमि खरीद की शर्तों पर विश्वास जताते हुए इन मुकदमों से भी किसानों को जल्दी ही छुटकारा दिला दिया।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निर्माण की कुल लागत 14000 करोड़ रुपए है। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है और इस पूरी लागत का सिर्फ 35 फीसदी धन इस एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से भूमि खरीदने के लिए व्यय किया गया है, इसी कारण भारत सरकार ने भी इसके निर्माण के मॉडल को सराहते हुए इसका अध्ययन कराने की बात कही है।

इसकी एक और विशेषता यह है कि यह जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है वे सभी अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञताओं के लिए जाने जाते हैं. आगरा तो पर्यटन के अलावा चमड़े के जूते, पेठे और पत्थर की कटाई के लिए जाना जाता है तो कन्नौज दुनिया भर में अपने इत्र के लिए मशहूर है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारोबार ने उसे प्रसिद्धि दिलाई है तो उन्नाव चमड़े और डेयरी उद्योग के लिए विश्व भर में जाना जाता है।

110 मीटर चौड़ा और चार रेल ओवर ब्रिज समेत 13 बड़े पुलों, 149 अंडर पास, 75 वर्नाकुलर अंडर पास और 11 इंटरचेंज के साथ 3.75 मीटर की सर्विस लेन वाला आगरा एक्सप्रेस वे इटावा से भी गुजरेगा जहां विश्व स्तरीय लायन सफारी बनाई जा रही है जहां गुजरात के गिर से शेर लाए गए हैं। उन्नाव की नवाबगंज बर्ड सेंक्चुरी हो या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व, दिल्ली से आने वाले पर्यटकों को अब आगरा से जयपुर का रुख करने की जरूरत नहीं है।

यानी आगरा एक्सप्रेस वे के शुरू हो जाने के बाद आगरा तक आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लखनऊ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगरा से लखनऊ और अयोध्या, काशी तक पर्यटकों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी की वजह यही एक्सप्रेस वे बनेगा।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पिछले दिनों भारतीय सेना के विमानों की लैंडिंग ने भविष्य में इसके सैन्य इस्तेमाल के संकेत भी दे दिए हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा 24x7 ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित

नोएडा-ग्रेटर नोएडा सहित आसपास का इलाका देश का सर्वोत्तम औद्योगिक क्षेत्र है। यहां अवस्थापना सुविधाएं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से बेहतर हैं। राज्य सरकार पूरे प्रदेश का इसी प्रकार का विकास करने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसलिए नगरों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लगभग 6796 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए यह पंक्तियां कहीं।

श्री यादव ने प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उन्हें तय समय में पूरा किया जाए ताकि जनता को समय से इनका लाभ मिल सके। उन्होंने नोएडा में साईकिल ट्रैक, शिल्प हाट एवं बुनकर भवन तथा ग्रेटर नोएडा की लोहिया पारिस्थितिकीय संरक्षण वन परियोजना को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोएडा में निर्मित होने वाला शिल्प हाट एवं बुनकर भवन प्राधिकरण क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ निजी मॉल से बेहतर होना चाहिए।

प्रदेश सरकार राज्य को स्थाई विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब हैं, जिसके कारण इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन इलाकों में हो रहे औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। इसलिए इन्हें 24x7 ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा का महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ने वाला यह देश का इकलौता शहर होगा। 'मेक इन इण्डिया' अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इस अभियान के लिए उत्तर प्रदेश सभी संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने अवस्थापना विकास निधि के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था करने पर बल दिया।

फसलें बचाने के लिए हथगोले रख कर मारी जा रही हैं गायें

तो इस पर मौन क्यों हैं गौभक्त?

चौथी दुनिया ब्यूरो

फसलों को पशुओं से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों में बड़े पैमाने पर हथगोलों का इस्तेमाल हो रहा है. बड़ी तादाद में गायें व अन्य पशु बुरी तरह जख्मी होकर मर रहे हैं, लेकिन गायों की इस तरह हो रही दर्दनाक मौतों पर सारे गौभक्त मौनी बाबा बने हुए हैं. ऐसी हरकतों के बारे में पुलिस को भी पता है और राजनीतिक दलों को भी जानकारी है, लेकिन इस मामले में वोट संलग्न नहीं है, तो उनकी दिलचस्पी भी संलग्न नहीं है. इसका खामियाजा पशुओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है.

फसलों को गायों से बचाने के लिए हथगोलों के इस्तेमाल का फैशन उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से होता हुआ लखनऊ तक पहुंच चुका है. लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी खेतों के किनारे-किनारे खाद्य पदार्थों में लपेट कर हथगोले रख दिए जा रहे हैं और गायों को लहूलुहान कर फसलें बचाई जा रही हैं. गायों के मुंह में ही हथगोले फट जाते हैं जिससे दर्दनाक दृश्य खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा करने वाले किसानों को केवल फसलें बचाने का दर्द है. फसलें बचाने का अन्य कोई तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा. पिछले दिनों लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में इस तरह की दो घटनाएं हुईं. इन घटनाओं ने यह साबित किया कि असलियत में कोई गौभक्त नहीं है. विडम्बना यह है कि लावारिस कुत्तों को बचाने के लिए सड़कों पर सक्रिय दिखने वाले एनिमल-लवर्स में भी गायों का जख्म देख कर पशु-प्रेम जाग्रत नहीं होता.

लखनऊ रेंज के उप महानिरीक्षक देवेंद्र कुमार चौधरी ने इस मसले पर विचित्र अंदाज में कहा कि पुलिस पशुओं के बारे में सोचे या इंसानों के बारे में! उन्होंने उल्टे यह कहा कि पशुओं को लेकर सहानुभूति आप रखते हैं, हर कोई नहीं रखता. पशु किसानों की फसल चौपट कर देते हैं. किसानों को अपनी फसलों को बचाना पड़ता है. पुलिस के पास गौशाला नहीं है. यदि पशुओं के स्थान पर कोई बच्चा या व्यक्ति घायल होता है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है.

गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी जयराम और शिवचंदर के गायों की मौत हथगोले चबाने से हो गई. ये हथगोले फसलों को पशुओं से बचाने के लिए खेत के पास रखे गए थे. इन हथगोलों से दो गायों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन जिनकी खेत में बम रखे गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस को यह भी ख्याल नहीं आया कि गायों की जगह कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भी हो सकता था. बात-बात पर धरना-प्रदर्शन करने पर उतारू रहने वाले संगठन भी इस मसले पर मुखर नहीं हो रहे. हथगोले रखने के मामले में दोषी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, यह बात पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही है. पालतू पशुओं और गायों की मौत पर पूरा तंत्र चुप है. कारण स्पष्ट है कि तंत्र की रुचि ऐसे मामलों में नहीं है. गाय पर भाषण देना हो तो पक्ष-विपक्ष में तमाम राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी फेंटा कस कर कूद पड़ेंगे. लेकिन इस तरह विस्फोटक लगा कर मारे जा रहे पशुओं पर बात भी करना उन्हें औचित्यहीन लगता है. इस तरह की अमानवीय घटनाएं कई स्थानों पर हो रही हैं. पशुओं से फसल बचाने के लिए ऐसे कई बर्बर उपाय किए जा रहे हैं, जिसे देख-सुनकर आपके होश उड़ जाएं. शाहजहांपुर जिले के खुटार वनक्षेत्र में तो कई किसानों ने खेतों के किनारे बिजली के तारों का जाल बिछा रखा है. उन तारों में रात में करंट दौड़ता है. बिजली के झटके से कुछ दिनों के अंतराल में ही दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है. पुलिस और वनविभाग से बचने के लिए किसान इन पशुओं को नदी में फेंक देते हैं या रेत में दफना देते हैं. शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर खुटार जंगल से सटे सैकड़ों एकड़ खेत हैं, जहां इस तरह की घटनाएं आम हैं. कुछ ही महीने पहले यहां के ग्राम नरौठा हंसराम के पास गुलदार के शावक का शव मिला, उसकी नाक से खून बह रहा था. शावक की मौत का कारण करंट लगना बताया गया था. मलिका गांव के निवासी महिपाल सिंह कहते हैं कि हमारे जानवर सुरक्षित नहीं हैं. इस तरह जानवरों को करंट लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. जबकि स्थानीय अधिकारियों और वनविभाग के अधिकारियों को इस बारे में बाकायदा सूचित किया जा चुका है. इस बारे में पूछने पर खुटार रेंज के वन संरक्षक शिवाजी सिंह ने कहा कि खुटार जंगल क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें अलग-अलग हिस्सों पर कई लोगों की तैनाती है. सिंह ने कहा कि जानवरों के इस तरह मारे जाने की घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई है. इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने में असमर्थता जताई, लेकिन उनकी असमर्थता ने ही हालात के बारे में काफी कुछ बयान कर दिया. अहम बात यह है कि हथगोले में इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद भी बड़ी आसानी से गांवों में उपलब्ध है. कम दाम पर हर गांव में बारूद मिल जाता है, जहां उसे किसी खाने में मिलाकर हथगोला बना दिया जाता है. गैरकानूनी रूप से इस बारूद की बिक्री हो रही है. पुलिस को रिश्वत दिखती है, लिहाजा बारूद नहीं दिखता. पुलिस को न बारूद बेचने वाले मिलते हैं और न खरीदने वाले. जीवाश्रय संस्था के सचिव यतींद्र त्रिवेदी कहते हैं कि गायों या अन्य पशुओं के साथ हो रही इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं. दुर्घटना होने के बाद कई मामले में पुलिस ने जख्मी गायों को पशु अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की. मामला संवेदनशील है और यही घटनाएं कभी साम्प्रदायिक तनाव का रूप भी ले सकती हैं.

लखनऊ रेंज के उप महानिरीक्षक देवेंद्र कुमार चौधरी ने इस मसले पर विचित्र अंदाज में कहा कि पुलिस पशुओं के बारे में सोचे या इंसानों के बारे में! उन्होंने उल्टे यह कहा कि पशुओं को लेकर सहानुभूति आप रखते हैं, हर कोई नहीं रखता. पशु किसानों की फसल चौपट कर देते हैं. किसानों को अपनी फसलों को बचाना पड़ता है. पुलिस के पास गौशाला नहीं है. यदि पशुओं के स्थान पर कोई बच्चा या व्यक्ति घायल होता है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है. बारूद का गैरकानूनी तरीके से उपयोग हो रहा है. इस बारे में ठोस सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, राज्य सरकार द्वारा निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि हथगोले से किसी इंसान की मौत होती है तो वह आईपीसी की धारा 302 के तहत संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. लेकिन पशुओं की मौत पर इस धारा के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती. पुलिस इसे एक दुर्घटना मान लेती है. बारूद की उपलब्धता पर पुलिस को नियंत्रण करना चाहिए. बारूद मिलेगा ही नहीं तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होंगी. प्रदेश की कानून व्यवस्था देखने वाले महकमे के एडीजी दलजीत चौधरी कहते हैं कि बिना लाइसेंस बारूद बेचना अपराध है. इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है. वाहन चेकिंग के दौरान कई बार विस्फोटक पदार्थ पुलिस बरामद करती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई

गाय मारना या गाय के मांस की तस्करी करते हुए पाए जाने पर 5/8 गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है. इस धारा में पांच से 11 वर्ष तक की सजा होती है. दूसरी तरफ हथगोले से किसी पशु की मौत होती है तो पशु क्रूरता अधिनियम-11 के तहत कार्रवाई की जाती है. इसमें पुलिस सूचना दर्ज करके हथगोले रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है. ■

लम्बित मुकदमों का यूपी-रिकॉर्ड, न्याय की आस में उम्र बीत जा रही जेलों में

अदालतों में बंधक न्याय

प्रभात रंजन दीन

न्यायिक सक्रियता के दौर में उत्तर प्रदेश की अदालतों में 50 लाख मुकदमों का लम्बित होना आश्चर्यजनक भी है और अत्यंत दुखद भी. बात-बेबात के मसलों पर अत्यधिक सक्रिय दिखने वाली अदालतें लम्बित मुकदमों से बोझिल होती अपनी फाइलें नहीं देखतीं, यह भारतीय लोकतंत्र की नकारात्मक विशेषता है. अदालतों से लेकर तमाम न्यायिक संस्थाएं तक इस बात के लिए औपचारिक दुख-तकलीफ जताती रहती हैं कि देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ है लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकतीं. जेलों में ठुंसी हुई भीड़ की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश अव्वल है, इसीलिए लम्बित मुकदमों का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश की अदालतें ही कायम कर रही हैं. अदालतों से कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वे विशेषाधिकार सम्पन्न हैं. जिसने पूछा उसे अदालत की अवमानना के आरोप झेलने पड़ सकते हैं. खुद-मुख्तारी के अलग-अलग खेमों-खानों में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था फंसी पड़ी है.

अदालतों में लम्बित मुकदमों का आंकड़ा आधिकारिक है. नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में तकरीबन 50 लाख मुकदमे लटके पड़े हैं. महिलाओं को कानूनी संरक्षण के सियासी शोर के बरक्स सच यह है कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में महिलाओं से जुड़े लगभग सवा चार लाख से अधिक मुकदमे लम्बित हैं, जिनपर फैसला आना बाकी है. विचित्र तथ्य यह भी है कि छह लाख मामले 10 साल से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं और जज साहब के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इनसे सम्बन्धित अधिकांश लोग विचाराधीन कैदियों के रूप में बिना कोई फैसला आए जेल की सजा काट रहे हैं. फैसला आया और उसमें विचाराधीन कैदी दोषी नहीं पाया गया तो उसके जेल में

बिताए गए 10 साल कौन सी अदालत लौटाएगी, इसकी कोई जवाबदेही भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में तय नहीं है.

नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड की रिपोर्ट कहती है कि कुल 49 लाख 68 हजार 190 मामले उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इनमें दीवानी (सिविल) के 12 लाख 57 हजार 348 मामले और फौजदारी (क्रिमिनल) के 37 लाख 10 हजार 842 मामले लम्बित पड़े हैं. इन लम्बित पड़े मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगाह नहीं जाती. इन लम्बित पड़े मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगाह नहीं जाती. इन लम्बित पड़े मामलों पर मानवाधिकार के नाम पर किस्म-किस्म की दुकान चलाने वाली सामाजिक संस्थाओं की निगाह नहीं जाती. आम आदमी का न्याय अदालतों में बंधक बना हुआ है, उस पर लोकतंत्र के किसी भी पहरुए की निगाह नहीं जाती. ये सब अदालतों से डरते हैं. सत्ता पर बैठे या सत्ता पर बैठने का स्वप्न संजोते रहते नेताओं से ऐसे किसी साहस की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती. आप इन लम्बित पड़े मामलों के विस्तार में जाएं, और अगर आप संवेदनशील हैं, तो शायद आप ठीक मानसिक संतुलन में नहीं रह पाएंगे. न्याय की प्रतीक्षा करते लोगों की अथाह पीड़ा आपको अत्यंत विचलित कर देगी. मन में स्वाभाविक सवाल उठेगा कि आम आदमी इस पीड़ा को इतनी संजीदगी से महसूस कर रहा तो अदालतें क्यों नहीं महसूस कर रहीं. न्यायाधीशों की श्रृंखला इससे विचलित क्यों नहीं हो रही! यह विडम्बना ही तो है! मुजफ्फरनगर के कांकड़ा गांव के रहने वाले किसान रामपाल कोई अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो पिछले 10 साल से खेत के विवाद को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं. खेत बंधक पड़ा है. उसकी वजह से किसान का परिवार भी बंधक पड़ा हुआ है, लेकिन अदालत कोई फैसला नहीं कर रही. रामपाल की पीड़ा में तमाम लोगों के कष्ट की आवाज सुनाई देगी जब वे यह कहते हैं कि 10 बरस से वे पेशी पर हाजिर हो रहे हैं और अगली तारीख लेकर घर चले जाते हैं और अगली तारीख पर फिर अदालत आने की तैयारी करने लगते हैं. कभी दूसरे पक्ष का आदमी नहीं आता, कभी मुकदमा लड़ने वाला वकील नहीं आता, कभी जज नहीं आते, कभी इसकी तबीयत खराब, कभी वह बीमार, कभी वकील हड़ताल पर तो कभी जज छुट्टी पर, इसी चक्कर में मुकदमे घिसटते रहते हैं और अदालतें उन पर निर्णायक रुख अख्तियार कर मामले निपटाने में भी कोई रुचि नहीं दिखातीं. वकील पैसे वसूलता रहता है और मुद्दई चुसता रहता है. हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि न्यायाधीशों के 160 पद हैं, लेकिन कार्यरत जजों की संख्या केवल 72 है. इस तरह अन्य अदालतों में भी जजों के पद खाली पड़े हुए हैं. इस वजह से भी ढेर सारे मुकदमे लम्बित हैं. प्रदेश की कई निचली अदालतों में कम्प्यूटरीकरण का काम भी नहीं हुआ है, जिस वजह से पारदर्शिता नहीं आ पा रही और काम भी तेजी से नहीं हो पाता.

न्याय की फाइलों को लम्बित रखने का फैशन केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी है. इसके लिए राज्य सरकारों का लचर रवैया भी दोषी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में ढिलाई के कारण भी लम्बित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी हाईकोर्ट में जजों के 984 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें 382 पद खाली पड़े हैं. अधिनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 19 हजार 756 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें 4356 पद खाली पड़े हैं. 2015 का आधिकारिक आंकड़ा है कि देश की अदालतों में तीन करोड़ 70 लाख पांच हजार से अधिक मुकदमे लम्बित हैं. इनमें सुप्रीम कोर्ट में 63 हजार 843 और देश के 24 उच्च न्यायालयों में 44 लाख 62 हजार 957 मामले विचाराधीन लम्बित पड़े हैं. अधिनस्थ अदालतों में तो लम्बित मुकदमों का आंकड़ा दुर्गंध देने लगा है. अधिनस्थ न्यायालयों में दो करोड़ 68 लाख 88 हजार 405 मुकदमे लम्बित हैं. दुनिया के किसी अन्य देश में न्यायिक दुर्गति का ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

लम्बित मुकदमों का ख़ौफ़नाक आंकड़ा

कुल लंबित मामले	-49,68,190
फौजदारी (क्रिमिनल)	-37,10,842
दीवानी (सिविल)	-12,57,348
महिलाओं से जुड़े मामले	- 4,24,718

रंगों की जादूगर हैं सुजाता बजाज

गणपति से सुजाता को खास लगाव है. इस थीम पर वह पिछले 30 वर्षों से काम कर रही हैं. उन्होंने अपनी चित्रकला और मूर्तिकला में अमूर्त कला का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी कला पूरी तरह से भारतीय रंग में डूबी हुई है. अपनी तस्वीरों में उन्होंने शोख रंगों का बेखौफ इस्तेमाल किया है. वह कहती हैं कि रंगों में अलग-अलग जज्बातों के चित्रण की ज़बरदस्त शक्ति होती है. सुजाता ने अपनी पेंटिंग्स में प्रयोग से भी परहेज नहीं किया है.

शफीक आलम

सुजाता बजाज का नाम कला जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. उन्होंने रंगों और लकीरों के सहारे एक ऐसी दुनिया का सृजन किया है, जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी, जो आसान भी है और तहदार भी, जिसमें खुशी भी है और गम भी, जिसमें खोने का एहसास भी है और खुद को पा लेने का बोध भी. हालांकि उन्होंने अपनी चित्रकला और मूर्तिकला में अमूर्त कला (एब्सट्रैक्ट आर्ट) का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी कला पूरी तरह से भारतीय रंग में डूबी हुई है. अपनी तस्वीरों में उन्होंने शोख रंगों का बेखौफ इस्तेमाल किया है. वह खुद को रंगकार (कलरिस्ट) कहती हैं. वह कहती हैं कि रंगों में अलग-अलग जज्बातों के चित्रण की ज़बरदस्त शक्ति होती है. इसमें कोई शक नहीं कि तस्वीरों में रंगों का बहुत महत्व होता है और हर रंग के मायने भी अलग-अलग होते हैं. उनमें गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, अध्यात्म भी होता है और ज़मीन की खुशबू भी. दरअसल, एक ही रंग अलग-अलग पृष्ठभूमि में अलग-अलग भावनाओं का चित्रण करता है. रंगों से अपने लगाव को ज़ाहिर करते हुए वह कहतीं हैं कि मैं राजस्थान में जन्मी हूं, शेखावाटी की हूं, जयपुर में पढ़ी हूं. रंग तो मेरे खून में है.

सुजाता ने प्रयोग से भी परहेज़ नहीं किया है. इसलिए उनके चित्रों और मूर्तियों में संस्कृत के श्लोकों के इस्तेमाल के साथ-साथ अंक और संगीत के चिन्ह भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं. खास बात यह है कि उनकी तस्वीरों और मूर्तियों को देखने वाले पहली नज़र में ही इन बातों को महसूस कर लेते हैं. इसके बारे में सुजाता का कहना है कि ये सब मेरी ज़िन्दगी की तरह हैं. जैसे मेरे पति नॉर्वे के रहने वाले हैं, मैं पेरिस में रहती हूं, दुबई में रहती हूं, भारत भी आती रहती हूं, तो मेरी ज़िन्दगी चारों तरफ है. इसलिए मेरे काम में कहीं भुजपत्र दिखाई देता है, कहीं न्यूज़पेपर है तो कहीं वॉलपेपर. इस तरह मेरी ज़िन्दगी के अलग-अलग अनुभवों को मिला कर ये काम बने हैं.

गणपति से सुजाता को खास लगाव है. इस थीम पर वह पिछले 30 वर्षों से काम कर रही हैं. पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर के विजुअल आर्ट गैलरी में इसी थीम पर सुजाता द्वारा बनाई गई चित्रकृतियों और मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी. इस प्रदर्शनी में फ्रांस के मशहूर फिल्मकार और ऑस्कर पुरस्कार विजेता जां-कलौदिया कारिएख द्वारा रचित किताब *सुजाता बजाज: गणपति* का विमोचन भी हुआ. इंडिया हैबिटैट सेंटर की आर्ट गैलरी कलाप्रेमियों से खचाखच भरी हुई थी. आर्ट गैलरी में इस किताब का विमोचन फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी, गीतकार और शायर जावेद अख्तर और भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांस्वा रिचियर के हाथों हुआ.

कहते हैं कि आर्ट से उसके आर्टिस्ट को अलग नहीं किया जा सकता है. आर्टिस्ट के व्यक्तित्व की झलक उसकी कृति में नज़र आ ही जाती है. सुजाता को बचपन से ही गणपति के आकार ने प्रभावित किया है. वह गणपति को अपना दोस्त मानती हैं. सुजाता कहतीं हैं कि वह हमेशा उनके साथ हैं और इसलिए वह अलग-अलग तरीके से सुजाता की ज़िन्दगी में शामिल हुए. यह बात गणपति पर बनाई गई उनकी कलाकृतियों से भी ज़ाहिर होती है, क्योंकि ललितकला की मामूली समझ रखने वाले व्यक्ति को भी इस प्रदर्शनी को देखने के बाद यह अंदाज़ा हो जाएगा कि गणपति की इतनी सारी तस्वीरों में भी कोई दो तस्वीरें एक जैसी नहीं थीं.

सुजाता ने गणपति को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों बनाया? इसके पीछे भी एक व्यक्तिगत कारण है. वह कहतीं हैं कि एक बार वह अपने पिताजी को गोपुरी से पौनार आश्रम ले जा रही थीं, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें पांच-छह हफ्ते आराम करने की सलाह दी. उस समय वह एक छात्रा थीं. उन्होंने समय गुजारने के लिए ड्रॉइंग बनाना शुरू किया. इस दौरान उनकी पहली और आखिरी ड्रॉइंग गणेशजी की ही थी. यहां से गणपति के साथ उनका जो सफ़र शुरू हुआ, वह आज तक जारी है. गणपति को वह अनंत मानती हैं. उनका कहना है कि वह गणपति के साथ खुद को बहुत स्वतंत्र और आज़ाद महसूस करती हैं और जिस आज़ादी के साथ वह गणपति की आकृति को एब्सट्रैक्ट कर लेती हैं, वह आज़ादी किसी दूसरी विधा (फॉर्म) में नहीं मिलती. गणपति की तस्वीरों में बने चक्र और एक गणपति में दूसरे गणपति की आकृतियां अनंत की ओर ही इशारा करती हैं.

सुजाता बजाज का जन्म 1958 में जयपुर (राजस्थान) में एक ऐसे माता-पिता के घर हुआ था, जिनकी जोड़ी महात्मा गांधी ने मिलाई थी. जिनके बारे में शबाना आज़मी ने कहा कि वे भारत के आखिरी गांधीवादी थे. सुजाता को आचार्य विनोवा भावे प्यार से चित्रकारनी कहा करते थे. उन्हें बचपन से ही चित्रकारी का शौक़ था. उन्होंने शुरुआती शिक्षा जयपुर में हासिल की. उसके बाद वह पूणे चली गईं, जहां से ललितकला में उन्होंने एमए किया और आदिवासी कला पर पीएचडी की. फिर मशहूर पेंटर एसएच रजा के कहने पर और फ्रांसीसी सरकार के स्कॉलरशिप पर पेरिस गईं, जहां उन्होंने अपनी कला और अनोखी पहचान को निखारा. देश और विदेश में उनकी कई प्रदर्शनियां लग चुकी हैं. कला क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है. इसमें कोई शक नहीं कि वह रंगों की जादूगर हैं. ■

आम तौर पर जो आर्टिस्ट यूरोप या अमेरिका जाते हैं तो उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने में वक्त लगता है, लेकिन सुजाता को इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई. वह इसलिए प्राप्त हुई कि उनके जो मां-बाप थे, वे वर्धा में रहते थे, वे गांधीवादी थे, जिनकी वजह से उनकी भारतीयता की जड़ें मज़बूत हैं.

-शबाना आज़मी (फिल्म अभिनेत्री)

सुजाता की पेंटिंग्स में आधुनिकतावाद और परम्परावाद का अनोखा मिश्रण है, जो बहुत ही खूबसूरत है .

-जावेद अख्तर (शायर और गीतकार)

यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि सुजाता पेरिस में रहते हुए पिछले 30 वर्षों से इन पेंटिंग्स पर बड़ी ख़ामोशी से काम कर रही थीं, लेकिन उनकी प्रेरणा भारतीय रही है. गणपति के विषय को उन्होंने अपने खास अंदाज़ में अपनाया है.

-फ्रांस्वा रिचियर (भारत में फ्रांस के राजदूत)

feedback@chauthiduniya.com

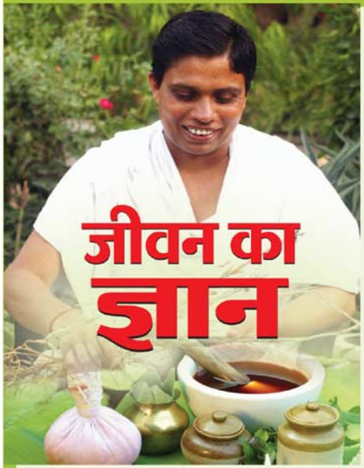

अर्जुन

परिचय

पहाड़ी क्षेत्रों में नदी, नालों के किनारे 18-25 मी तक ऊंचे पंक्तिबद्ध हरे पल्लवों के वल्कल ओढ़े अर्जुन के वृक्ष ऐसे लगते हैं. अर्जुन का वृक्ष जंगलों में पाया जाता है. इस पेड़ का अर्जुन नामकरण केवल स्वच्छ श्वेत वर्ण के आधार पर किया गया है.

बाह्या-स्वरुप

यह अत्यन्त सूक्ष्म हरित तथा श्वेत वर्ण की आभा से युक्त व पुष्पदंड के चारों ओर लगे होते हैं. इसके फल कमरख जैसे 5 या 7 उठी हुई धारियों से युक्त होते हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- इसका सार एड्रियामायसिन प्रेरित क्षति से डी.एन.ए की सुरक्षा करता है.
- इसका अनॉक्सीकारक जलीय-सार अर्बुदजननरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

कर्ण रोग:

- कर्णशूल-3-4 बूंद अर्जुन पत्र-स्वरस को कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है.

मुख रोग:

- मुखपाक- अर्जुन मूल चूर्ण में मीठा तैल मिलाकर मुंह के अंदर लगाकर गुनगुने पानी का कुल्ला करने से मुखपाक में लाभ होता है.

वक्ष रोग:

- क्षयजकास- अर्जुन छाल के चूर्ण में वासा पत्र स्वरस की सात भावना देकर, 2-3 ग्राम की मात्रा लेकर, शहद मिश्री या गोघृत के साथ चटाने से क्षयज कास (जिसमें कफ में खून आता हो) में लाभ होता है.

हृदय रोग:

- हृदय की सामान्य धड़कन जब 72 से बढ़कर 150 से ऊपर रहने लगे तो एक गिलास टमाटर के रस में 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर नियमित सेवन करने से शीघ्र ही लाभ होता है.
- अर्जुन छाल चूर्ण दूध, मिश्री और मधु मिलाकर चटाने से हृदयरोगों में लाभ होता है.
- 6-10 ग्राम अर्जुन छाल चूर्ण में गुड़ मिलाकर दूध के साथ पकाकर छानकर पिलाने से हृदय का शमन होता है.
- यह उच्च रक्तचाप में लाभप्रद है. उच्च रक्तचाप के कारण यदि हृदय में शोथ (सूजन)उत्पन्न हो गई हो तो उसको भी दूर करता है.

उदर रोग:

- उदावर्त्त- 20 मिली अर्जुन छाल क्वाथ का नियमित सेवन करने से उदावर्त्त में लाभ होता है.
- अर्जुन की पत्ती, बेल की पत्ती, जामुन की पत्ती, मृणाली, कृष्णा, श्रीपर्णी की पत्ती, मेहंदी की पत्ती और धाय की पत्ती, इन सभी पत्तियों के स्वरस से अलग- अलग खड़ यूषों का घी, अम्ल तथा लवण मिलाकर निर्माण करें. ये सभी खडयूष परम संग्राहिक होते हैं.

वृक्कवस्ति रोग:

- प्रमेह- अर्जुन की छाल, नीम की छाल, आमलकी छाल, हल्दी तथा नीलकमल के समभाग चूर्ण 20 ग्राम को 400 मिली पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष बचाकर, 10-20 मिली क्वाथ में मधु मिलाकर नित्य प्रातः सायं करने से पित्तज-प्रमेह में लाभ होता है.
- शुक्रमेह- अर्जुन की छाल या श्वेत चंदन से निर्मित 10-20 मिली क्वाथ को नियमित प्रात: सायं पिलाने से शुक्रमेह में लाभ होता है.

प्रजननसंस्थान रोग:

- रक्तप्रदर- 1 चम्मच अर्जुन छाल चूर्ण को 1 दूध में उबालकर पकाएं, आधा शेष रहने पर थोड़ी मात्रा में मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें.इसके सेवन से रक्तप्रदर में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

- अर्जुन त्वक से सिद्ध 20-40 मिली क्षीरपाक में 5 ग्राम घी एवं मिलाकर पीने से अस्थि भंग में लाभ होता है.
- समभाग अर्जुन त्वक तथा लाक्षा चूर्ण (2-4 ग्राम) में गुग्गुलु तथा घी मिलाकर सेवन करने से तथा भोजन में घी तथा दूध का प्रयोग करने से शीघ्र भग्न संधान होता है.
- भग्न के उपरांत 2-4 ग्राम अर्जुन त्वक चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से अस्थियों को बल मिलता है.

त्वचा रोग:

- कुष्ठ- अर्जुन छाल को एक चम्मच चूर्ण को जल के साथ सेवन करने से एवं इसकी छाल को जल में घिसकर त्वचा पर लेप करने से कुष्ठ में लाभ होता है.
- अर्जुन छाल को यवकुट कर क्वाथ बनाकर व्रणों को धोने से लाभ होता है.
- 1 चम्मच अर्जुन मूल चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से घृष्ट व्रण में लाभ होता है.
- व्यंग- अर्जुन त्वक से बनाए कल्क का व्यंग पर लेप करने से लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग:

- बादी के रोग- अर्जुन मूल छाल चूर्ण और गंगेरन मूल छाल चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर 2-2 ग्राम की मात्रा में नियमित प्रात: सायं दूध के साथ सेवन करने से शूल तथा शोथ का शमन होता है.
- ज्वर- 20 मिली अर्जन छाल क्वाथ को पिलाने से ज्वर में लाभ होता है.
- 1 चम्मच अर्जुन छाल चूर्ण को गुड़ के साथ सेवन करने से जीर्ण ज्वर का शमन होता है.
- क्षेय रोग-अर्जुन त्वक नागबला तथा केवांच बीज चूर्ण (2-4 ग्राम) में मधु, घी मिश्री मिलाकर दूध के साथ पीने से क्षय, कासादि रोगों का शीघ्र

प्रयोज्यांग: काण्डत्वक, मूल, पत्र तथा फल

मात्रा: चूर्ण 2-4 ग्राम स्वरस 5-10 मिली. क्वाथ 20-40 मिली.

चिकित्सक के परामर्शानुसार ■

आचार्य बालकृष्ण

साई वंदना

सद्गुरु का मूलभूत गुण है ईश्वरीय करुणा

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

क्या पाप-कर्म करने वालों की मुक्ति सम्भव है?

जीवन में किए गए नकारात्मक एवं सकारात्मक कर्मों का स्त्रोत एक ही है. चरम सीमा तक किसी गुण में जाने से व्यक्ति गुण के अंत में पहुंचता है, गुणातीत होता है. पाप का भोग निश्चित है. यदि पापी धैर्यपूर्वक पाप के फूल को सह लेता है, तो वह भी पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है. जो ईश्वर का स्मरण करता है, अपनी उस कुछ समय की शुद्ध चेतना की अवस्था के कारण वह पाप की अवस्था से बाहर आ जाता है. ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अच्छा है कि मनुष्य पुण्यात्मक मार्ग से आगे बढ़े.

पाप और पुण्य का समन्वय कैसे करना चाहिए?

सामान्य मानवीय बुद्धि के अनुसार धर्म एवं अधर्म के बीच संघर्ष ही पाप एवं पुण्य के समन्वय का एक मिलन बिंदु है. सामान्य आदमी प्राय: पाप एवं पुण्य के समन्वय के बारे में कम और विरोधाभास के बारे में अधिक विचार करता है, लेकिन सन्त एवं सद्गुरु पाप एवं पुण्य के समन्वय के लिए प्रयत्न करते हैं, विरोधाभास के बारे में नहीं. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सन्त या सद्गुरुओं का मुख्य कर्म है- जीव-गति. वे जानते हैं कि पापी एवं पुण्यवान दोनों में ईश्वर निवास करते हैं. इसलिए मानव जैसे एक बुद्ध जीव को, जो कि अपनी आत्मा की दिव्यता एवं ईश्वरता का अनुभव नहीं कर पाता, वे उसे अपनी दिव्यता का अनुभव कराते हैं. इसलिए वे चेतना के स्तर के अनुसार पापी एवं निष्पापी हर व्यक्ति की सहायता करते हैं और पुण्यवंत लोगों की आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रयास करते हैं. पापी की आत्मा में सद्वृत्ति के जो अंकुर छुपे रहते हैं, वे उसे जागृत करते हैं. वे कभी भी किसी पापी को- चाहे वह कितना ही बड़ा पापी हो- नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि सद्गुरु का मूलभूत गुण है- ईश्वरीय करुणा. ■

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

बिलियर्ड्स और स्नूकर

छठे एशियाई खिताब पर टिकी पंकज की निगाहें

मैंने जितने भी टूर्नामेंट में भाग लिया है, कोई भी आसान नहीं था. खेल के सभी फॉर्मेट में हर टूर्नामेंट ने हमेशा चुनौती और प्रतियोगिता पेश की है. इस तरह की चुनौतियों से पार पाने का रोमांच ही मुझे आगे बढ़ाता है.

भारत के स्टार बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी के खिताबों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन ट्राफियों की भूख हमेशा बरकरार रहती है. आडवाणी ने बिलियर्ड्स और स्नूकर के सभी फॉर्मेट में रिकॉर्ड 15 विश्व खिताब अपने नाम किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एशियाई खिताब हासिल करने का खुद का रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार हैं और अब उनकी निगाहें कोलंबो में शुरू हो रहे टूर्नामेंट में छठा एशियाई खिताब हासिल करने पर लगी हैं.

30 वर्षीय आडवाणी पिछले सत्र के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हमवतन ध्रुव सितवाला से हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने स्वीकार किया कि तीन साल बाद खिताब जीतना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन साथ ही रोमांचक भी.

आडवाणी ने कहा कि मैंने जितने भी टूर्नामेंट में भाग लिया है, कोई भी आसान नहीं था. खेल के सभी फॉर्मेट में हर टूर्नामेंट ने हमेशा चुनौती और प्रतियोगिता पेश की है. इस तरह की चुनौतियों से पार पाने का रोमांच ही मुझे आगे बढ़ाता है.

उन्होंने कहा कि इस चैम्पियनशिप में पांच खिताब का रिकॉर्ड रखना और अगले खिताब की ओर बढ़ना चुनौतीपूर्ण है, जिसमें सिंगापुर के गिलक्रिस्ट, थाईलैंड के प्रापुट और थावट से कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और भारत के पिछले साल के चैम्पियन ध्रुव से भी कड़ी चुनौती मिलेगी.■

जब तक मुझे मजा आएगा, खेलूंगा: महेश भूपति

टेनिस

मैं अपनी लय फिर हासिल करने की कोशिश में हूं. जितने ज्यादा मैच खेलूंगा, उतना बेहतर महसूस होगा. चेन्नई ओपन की तुलना में अब बेहतर महसूस कर रहा हूं.

भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति का कहना है कि पेशेवर सर्किट पर लगातार उनकी मौजूदगी को रियो ओलंपिक की तैयारी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वह घुटने की चोट से उबरने के बाद दोबारा लय हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं.

भूपति एटीपी चैलेंजर सर्किट के टूर्नामेंट दिल्ली ओपन में युकी भांबरी के साथ खेल रहे हैं. इससे अटकलें लगने लगी हैं कि वह ओलंपिक की वापसी की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि पिछले दो साल में उन्होंने कोई टेनिस नहीं खेला.

भूपति ने कहा कि ओलंपिक मेरे मन में नहीं है. मैं खेल का मजा ले रहा हूं. स्वस्थ महसूस कर रहा हूं. मैं चोट की वजह से नहीं खेल रहा था. जब तक मुझे मजा आएगा, मैं खेलूंगा. मजा नहीं आएगा तो नहीं खेलूंगा. दुबई में अगर मुझे लगा कि अच्छा नहीं खेल रहा हूं तो खेलना छोड़ दूंगा.

चोट के कारण छह महीने प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर रहे खिलाड़ी को एंट्री प्रोटेक्शन के लिए नौ टूर्नामेंटों में या नौ महीने (जो भी पहले आए) खेलना होता है. प्रोटेक्टेड रैंकिंग का निर्धारण चोट के पहले तीन महीने में खिलाड़ी की औसत एटीपी रैंकिंग के आधार पर होता है.

भूपति की नजरें भले ही अपने छठे ओलंपिक पर नहीं हों, लेकिन अच्छे नतीजे आने और रैंकिंग में सुधार पर उनके चयन पर विचार किया जा सकता है. वह हालांकि सितंबर 2011 से डेविस कप नहीं खेले हैं. नियमों के तहत खिलाड़ी को चयन के लिए ओलंपिक से ओलंपिक के चार साल में कम से कम तीन बार डेविस कप टीम का हिस्सा होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मैं अपनी लय फिर हासिल करने की कोशिश में हूं. जितने ज्यादा मैच खेलूंगा, उतना बेहतर महसूस होगा. चेन्नई ओपन की तुलना में अब बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैंने चेन्नई में तीन, बैंकाक में दो, ऑस्ट्रेलिया में दो और फ्रांस में तीन मैच खेले. यह पूछने पर कि उन्हें कब तक लय हासिल करने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे मजा आ रहा है. मैं ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहता हूं. देखते हैं कि आगे क्या होता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर

स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है. न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च टेस्ट में 7 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रांस तस्मान ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2-0 जीत लिया और साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर-1 स्थान पर कब्जा जमा लिया. यह ब्रैंडन मैकुलम के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का भी आखिरी मैच था.

चौथे दिन के स्कोर एक विकेट पर 70 रन से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बचे हुए 131 रन बनाने के लिए 34 ओवर खेले. स्टीव स्मिथ ने 46 गेंदों पर 53 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन का लक्ष्य पांचवें और अंतिम दिन लंच के बाद ही हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने जो बर्न्स (65) और उस्मान ख्वाजा (45) के विकेट गंवाए. जीत का लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट से जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट एक पारी और 52 रन से जीता था. सीरीज 2-0 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 टीम बन गई. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रैंकिंग में दूसरे स्थान पर धकेल दिया.

यह टेस्ट ब्रैंडन मैकुलम का आखिरी टेस्ट था और उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मैकुलम ने पहली पारी में टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ा जबकि अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय पारी में उन्होंने 25 रन बनाए. इस मैच की समाप्ति पर मैकुलम का टेस्ट रिकॉर्ड 38.64 की औसत से 101 टेस्ट की 176 पारियों में 12 शतक और 31 अर्धशतक के साथ 6,453 रन रहा. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान एक तिहरा शतक और चार दोहरे शतक जड़े. 35 बार बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे मैकुलम अपने टेस्ट करियर के दौरान 9 बार नॉट आउट रहे, जबकि 14 बार अपना खाता भी नहीं खोल सके. उनका उच्चतम टेस्ट स्कोर 302 रन है जो उन्होंने फरवरी 2014 में भारत के खिलाफ वेलिंग्टन में बनाया. टेस्ट करियर के दौरान मैकुलम ने नवंबर 2014 में पाकिस्तानी बल्लेबाज विकेट कीपर सरफराज अहमद का विकेट लिया जो उनका एकमात्र टेस्ट विकेट है.■

टेनिस

महिला टेनिस संघ रैंकिंग

सेरेना लगातार 157 हफ्तों से नंबर-1 पर कायम

जर्मनी की एंजेलिक केरबर, सिमोना हालेप को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गई हैं. सिमोना को चौथा स्थान हासिल हुआ है. वहीं पौलैंड की एगनिस्का राडवांस्का को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.

अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स महिला टेनिस संघ (डब्ल्यूटीए) की रैंकिंग में 9,245 अंकों के साथ पहला स्थान कायम रखा है. इसके साथ ही वो लगातार 157 हफ्ते से नंबर-1 पर बनी हुई हैं और वह इस मामले में ऑल टाइम दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. उन्होंने मार्टिना नवरातिलोवा के 156 हफ्ते के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

जर्मनी की एंजेलिक केरबर, सिमोना हालेप को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गई हैं. सिमोना को चौथा स्थान हासिल हुआ है. वहीं पौलेंड की एगनिस्का राडवांस्का को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंकिक सातवें स्थान पर आ गई हैं जबकि इटली की फ्लाविया पेनेटा नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं. 10वें स्थान पर इटली की रोबर्टा विंसी हैं.■

टॉप-10 महिला रैंकिंग

1. सेरेना विलियम्स (अमेरिका)9,245
2. एंजेलिक केरबर (जर्मनी) 5,700
3. एगनिस्का राडवांस्का (पौलेंड) 5,210
4. सिमोना हालेप (रोमानिया) 4,745
5. जी. मुगुरुजा (स्पेन) 4,642
6. मारिया शारापोवा (रूस) 3,672
7. बेलिंडा बेंकिक (स्विट्जरलैंड) 3,505
8. पेट्रा क्विटोवा (चेक गणराज्य) 3,478
9. फ्लाविया पेनेटा (इटली) 3,422
10. रोबर्टा विंसी (इटली) 3,325

बैडमिंटन

चीन ने जीता एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब

चीन की यु सुन ने दूसरे एकल से अपनी टीम का भाग्य बदल दिया, उन्होंने जापान की सयाका सातो को 22-20, 21-19 से मात दी. दूसरे युगल मैच में चीन की यु लुओ और युआनटिंग टांग ने नाओको फुकुमैन और कुरूमी योनाओ को 21-11, 21-10 से हराया.

चीन ने गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के महिला वर्ग के फाइनल में जापान को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की. पांच मैचों के मुकाबले में तीन एकल और दो युगल शामिल हैं. जापान के नोजोमी ओकुहारा ने चीन की शिजियान वांग को 17-21, 21-16, 21-15 से शिरक्त देकर टीम की दमदार शुरुआत कराई. मिसाकी मातसुतोमो-अयाका ताकाहाशी की युगल जोड़ी ने चीन की यिंग लुओ और किंग टियान पर 21-12, 21-16 से मात देकर टीम की विजयी लय जारी की. चीन की यु सुन ने दूसरे एकल से अपनी टीम का भाग्य बदल दिया, उन्होंने जापान की सयाका सातो को 22-20, 21-19 से मात दी. दूसरे युगल मैच में चीन की यु लुओ और युआनटिंग टांग ने नाओको फुकुमैन और कुरूमी योनाओ को 21-11, 21-10 से हराया. निर्णायक एकल में चीन की बिंगजियाओ ही (31वीं रैंकिंग) ने जापान की युई हाशिमोटो (16वीं रैंकिंग) को हराकर टीम को जीत दिलायी. भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई थी.■

एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को मिले 9 मेडल

रेसलिंग

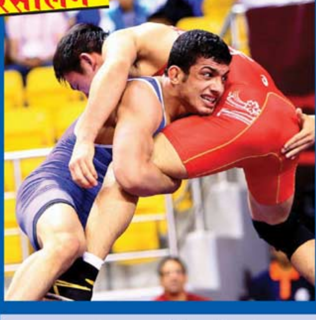

पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में संदीप तोमर ने फाइनल में उत्तर कोरिया के जोंग हाक जिन को हराकर भारत को टूर्नामेंट का एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया. विनोद कुमार हालांकि 70 किग्रा के फाइनल में बहरीन की एडम बैतिरोव से हार गए.

भारतीय पहलवानों ने थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एक गोल्ड सहित नौ पदक जीतकर अपने अभियान का अंत किया. भारत ओवरऑल पदक तालिका में सातवें स्थान पर रहा. वहीं महिला और पुरुष फ्रीस्टाइल टीमें चौथे, जबकि ग्रीको रोमन टीम छठे स्थान पर रही. पुरुषों की फ्रीस्टाइल के 57 किलोग्राम भार वर्ग में संदीप तोमर ने स्वर्ण पदक जीता. ओमप्रकाश विनोद कुमार ने 70 किग्रा में रजत पदक जीता. भारतीय महिलाओं में उदीयमान पहलवान प्रियंका फोगाट (55 किग्रा) ने रजत पदक जबकि विनेश फोगाट (53 किग्रा) और अनिता तोमर (63 किग्रा) ने कांस्य पदक जीते. दिलचस्प बात यह है कि ग्रीको रोमन में भारत बहुत मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें उसने चार पदक जीते.

पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में संदीप तोमर ने फाइनल में उत्तर कोरिया के जोंग हाक जिन को हराकर भारत को टूर्नामेंट का एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया. विनोद कुमार हालांकि 70 किग्रा के फाइनल में बहरीन की एडम बैतिरोव से हार गए. प्रियंका फोगाट ने महिलाओं के 55 किग्रा में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में वह मंगोलिया की दवासुखिन ओतोंगसेतसेग से हार गईं. उनसे अधिक अनुभवी विनेश और अनिता को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा. ग्रीको रोमन में हरदीप सिंह ने रजत पदक जीता. वह 98 किग्रा के फाइनल में ईरान के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मेहदी अलियारी फेयाजाबदी से हार गए. गौरव शर्मा ने 59 किग्रा में कांस्य पदक जीता. उन्होंने तीसरे स्थान के मुकाबले में कोरिया के इयुन बिन किम को हराया. हरदीप सिंह ने 80 किग्रा भार वर्ग में उज्बेक के अपने प्रतिद्वंद्वी जोनिबेक ओताबेकोव को हराकर कांसे का तमगा हासिल किया जबकि नवीन ने 130 किग्रा के तीसरे स्थान के मुकाबले में चीन के सुने हेई को हराया. इस प्रतियोगिता में पिछली बार भारत ने दोहा में पांच पदक (एक रजत और चार कांस्य) जीते थे. वह दसवें स्थान पर रहा था.■

एक सीन के कारण रात भर रोती थीं

सीमा बिश्वास

सीमा ने यूं तो अपने करियर में वाटर और हजार चौरासी की मां जैसी कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें आज भी बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है. यह फिल्म दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी. सीमा की यह पहली फिल्म थी. सीमा बिश्वास भारत भवन की 34वीं वर्षगांठ के मौके पर नाटक स्त्री पत्र की प्रस्तुति देने भोपाल पहुंची थीं. सीमा बिश्वास जिस फिल्म से देश भर में प्रसिद्ध हुई थीं, उसी फिल्म के एक न्यूड सीन के

कारण वह कभी रात-रात भर रोती थीं. वहीं जब यह सीन फिल्माए गए तो वहां डायरेक्टर, कैमरामैन के अलावा सभी की एंट्री बैन थी.

सीमा बिस्वास ने कहा, उस समय फिल्म के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया काफी बुरी थी. खासतौर पर फिल्म के न्यूड सीन के बारे में, कई लोग मुझसे इस रोल की वजह से नफरत करने लगे थे. हालांकि, मैंने कभी इस बारे में सफाई नहीं दी. सीमा ने बताया कि बोल्ड सीन मैंने नहीं, बल्कि डुप्लिकेट ने किए थे. इस बारे में मेरे घर वालों को पता था, इसलिए किसी को कोई सफाई नहीं दी. जबकि वह सीन मैंने किया ही नहीं था, लेकिन भारत में लोग उस फिल्म को दूसरी दृष्टि से देखते हैं. आज भी हॉलीवुड एक्टर्स फिल्म के उस सीन के लिए मुझे सलाम करते हैं. फिल्म में उस सीन के बाद पूरी फिल्म यूनिट रोई थी. सीन के दौरान सभी को सेट से बाहर कर दिया गया था. सीमा ने बताया कि उन्होंने शेखर कपूर से कहा था कि फिल्म से न्यूड सीन हटा दिए जाएं, लेकिन शेखर कपूर ने कहा कि सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में लोगों की असंवेदनशीलता को दिखाने के लिए वह सीन करना जरूरी है. अपनी कहानी के चलते फिल्म कई आलोचनाओं का शिकार भी हुई और फूलन ने स्वयं इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया. हालांकि बाद में कोर्ट की स्वीकृति के बाद वह प्रदर्शित हो सकी. ■

आपातकाल पर आधारित होगी अजय की बादशाहो

अजय देवगन स्टारर बादशाहो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन एक प्रेस वार्ता के दौरान फिल्म के बारे में काफी कुछ बाहर आ गया है. मिलन लूथरिया की बादशाहो अपनी ड्रीम टीम के साथ तैयार है. फिल्म की कास्ट और क्रू फाइनल हो चुकी है. फिल्म की फीमेल लीड के लिए करीना कपूर और पैरेलल लीड के लिए विद्युत जामवाल का नाम फाइनल हो चुका है. यह फिल्म जनवरी 2017 में रिलीज़ होगी. फिल्म की स्टोरी जैसे ही मिलन के दिमाग में आई वह अजय से मिलने पहुंच गए. अजय ने पूछा क्या हो गया तो मिलन ने आइडिया बताना शुरू किया और आधे घंटे में ही फिल्म ओके डन हो गई.

बादशाहो राजस्थान के सेट अप पर बनी आपातकाल के दौरान की कहानी है और इसमें 70 के दशक की पूरी घटना दिखाने की कोशिश की जा रही है. फिल्म की हर डीटेल पर काम किया जा रहा है. फिल्म में करीना कपूर एक राजस्थानी राजकुमारी की भूमिका निभाएंगी. ■

अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में प्रियंका ने ही जगह बनाई

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी ने कहा, अभी तक प्रियंका के अलावा ज्यादा कलाकार पश्चिम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास भारतीय कलाकारों के लिए ज्यादा अच्छे किरदार नहीं हैं. लेकिन प्रियंका ने यह कारनामा कर दिखाया है.

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि प्रियंका चोपड़ा के अतिरिक्त भारतीय फिल्म उद्योग के बेहद कम कलाकार ही पश्चिम में अपनी जगह बना पाए हैं. उन्होंने यह बात जी सिने अवॉर्ड्स 2016 में कही. सोनाक्षी ने कहा, अभी तक प्रियंका के अलावा ज्यादा कलाकार पश्चिम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास भारतीय कलाकारों के लिए ज्यादा अच्छे किरदार नहीं हैं. लेकिन प्रियंका ने यह करनामा कर दिखाया है. उन्होंने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं. मुझे लगता है कि वह बेहतरीन काम कर रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में जगह मिलना, जहां बॉलीवुड में काफी बड़ी बात मानी जाती है, वहीं सोनाक्षी का कहना है कि वह बॉलीवुड में काम करके ही खुश हैं. सोनाक्षी का एकल गीत आज मूड इश्कोहलिक है हाल ही में रिलीज हुआ था. इस पर सोनाक्षी का कहना है कि वह जल्द ही एक और गीत पेश करेंगी. इसी बीच सोनाक्षी अकीरा और फोर्स 2 की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. ■

लूलिया वंतूर को हिंदी सिखा रहे सलमान खान

रोमानियन की एक्ट्रेस और टीवी एंकर लूलिया वंतूर की खस्ताहाल हिंदी से सभी वाकिफ हैं. इन्हीं सब को देखते हुए सलमान ने अपनी इस कथित गर्लफ्रेंड के लिए एक हिंदी ट्यूटर अपॉइंट करवाया है. वह लूलिया को बेसिक हिंदी का ज्ञान देगा, क्योंकि उनकी यह कमजोरी बॉलीवुड में स्थापित होने और सलमान के परिवार से घुलने-मिलने में बड़ी बाधा है. अभी लूलिया और सलमान के परिवार के बीच सही ढंग से संवाद नहीं हो पाता है. साथ ही लूलिया की भाषाई समस्याओं के कारण उन्हें बॉलीवुड में काम भी नहीं मिलता. इसे निर्माता एक बड़ी परेशानी के रूप में देखते हैं. लेकिन अब वे ट्यूटर की मदद से हिंदी को सुधारने के लिए गंभीर हैं. उनके इस कदम से यह भी स्पष्ट हो गया कि लूलिया बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए एक्टिव हो गई हैं. इससे पहले जब लूलिया सलमान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में मनाए गए जन्मदिन समारोह में पहुंची थीं तो किसी से हिंदी में बात नहीं कर पा रही थीं. ■

रंगून में दिखाई देंगी मणिपुर की लिन

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर की हीरोइन लिन लाइश्रम निर्देशक विशाल भारद्वाज की आने वाली फिल्म रंगून में नजर आएंगी. लिन इससे पहले मेरी कॉम और ओम शांति ओम में भी नज़र आ चुकी हैं. इन फिल्मों में उनकी भूमिका उतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन इस बार रंगून में कंगना रनौत के बाद सेकेंड लीड में दिखाई देंगी. वह तीरंदाज (आर्चरी) की राष्ट्रीय चैंपियन (जूनियर) रह चुकी हैं. मॉडल रह चुकीं लिन रंगून में एक रोचक किरदार निभा रही हैं. लिन का कहना है कि लोग उन्हें एक घिसी-पीटी अभिनेत्री मानेंगे, लेकिन वह सकारात्मक सोच पर विश्वास रखती हैं. उनका मानना है कि रंगून में जो भूमिका उन्हें मिल रही है, वह बहुत खास है. यह उनके जीवन और करियर में बदलाव लाने वाला अनुभव होगा. इससे केवल उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके गृह राज्य के लोगों के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा. गौरतलब हो कि मणिपुर में वर्ष 2000 से हिंदी फिल्मों के रिलीज होने पर अलगाववादी संगठनों ने प्रतिबंध लगा दिया था. जिस समय मेरीकॉम रिलीज हो रही थी उस वक्त लोग इस बात से निराश थे कि फिल्म राज्य में रिलीज नहीं हो सकी थी. फिलहाल लिन ग्लैमर की दुनिया के बड़े डिजायनरों मसलन तरुण तेहलानी, शांतनु गोयनका और रोहित बल के साथ काम कर रही हैं. वह सबसे पहले रैंप पर साल 2008 में न्यूयॉर्क में उतरी थीं. वह न्यूयॉर्क ब्राइडल वीक फैशन शो और विल्स इंडिया फैशन वीक आदि में हिस्सा ले चुकी हैं.

गौरतलब हो कि लिन को उमंग कुमार की मेरीकॉम फिल्म में प्रियंका चोपड़ा द्वारा निभाया गया रोल मिलने वाला था, लेकिन वह रोल हथियाने से चूक गई. यह लिन का बॉलीवुड में काम करने का पहला मौका था. हालांकि, पूर्वोत्तर भारत के लोगों को उनकी शारीरिक बनावट और लुक की वजह से बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलना थोड़ा कठिन है. इन सभी बाधाओं को पार करके लिन आगे बढ़ चुकी हैं. अब देखना है कि लिन बॉलीवुड में कितना धमाल मचा पाएंगी. ■

फ्लैशबैक

परवीन

बॉबी को थी सच्चे प्यार की तलाश

1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई. यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी केअपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी. वह अलग बात थी कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया. इसकेबाद उनकी फिल्म आई धुएं यही वह वक्त था जब उन्होंने डैनी डोंगजप्पा को अपना दिल दे दिया. लेकिन उनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला.

परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था. परवीन अपने माता-पिता की शादी के चौदह साल बाद पैदा हुई थीं और यह इकलौती संतान थीं. उन्होंने अपने पिता को सात साल की उम्र में ही खो दिया था. परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद से पढ़ाई की. मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थीं. इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बीआर इशारा की नजर पड़ी. जब बीआर इशारा ने उन्हें देखा, उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया.

1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई. यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी. वह अलग बात थी कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया. इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं यही वह वक्त था जब उन्होंने डैनी डोंगजप्पा को अपना दिल दे दिया. लेकिन उनका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला.

1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर, बॉबी की पहली हिट फिल्म थी. जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन नजर

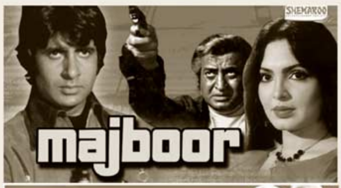

आए थे. इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी, में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया. उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही.

इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ अभिनय किया. 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता-आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की. इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई. परवीन बॉबी की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा.

बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रहीं. उनके करीब तीन साल के करियर में उन्हें तीन आदमियों के साथ जोड़ा गया. बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे. डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द पहुंचाया.

अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब आठ फिल्मों में काम किया. दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया. परवीन बॉबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा है. रीना रॉय के बाद 1976 से 1980 के बीच परवीन बॉबी दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली ऐक्ट्रस थीं. जीवन भर सच्चे प्यार के तलाश में रहीं परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिलीं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com